



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 29 मार्च, 2005/8 चैत्र, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 29 मार्च, 2005

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-24/2005.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक-9) जो आज दिनांक 29 मार्च, 2005 को

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ता/—

(जे० आर० गाज़टा),

सचिव।

2005 का विधेयक संख्याक 9.

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर विधेयक, 2005
(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में माल के विक्रयों या क्रयों पर मूल्य परिवर्धित कर के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध करने हेतु विधि पुनः अधिनियमित करने और उससे सम्बद्ध कतिपय अन्य विषयों के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित अधिनियम, 2005 है ।

संक्षिप्त
नाम और
प्रारम्भ।

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात, विषय या संदर्भ में विरुद्ध परिभाषाएं न हो, —

- (क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है ;
- (ख) “निर्धारण प्राधिकारी” से राज्य सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार का निर्धारण करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ग) “कारबार” के अन्तर्गत है,—

- (i) व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण की प्रकृति में कोई व्यापार, वाणिज्य, या विनिर्माण या कोई प्रोधम या समुत्थान है चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोधम या समुत्थान अभिलाभ या लाभ कमाने हेतु किया जाता है या नहीं और चाहे उससे कोई अभिलाभ या लाभ

प्रोद्भूत होता है या नहीं; और

(ii) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्योगिकी या समुत्थान से सम्बन्धित या आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई संव्यवहार ;

(घ) "पूँजी माल" से सिविल अवसंरचना, जैसी विहित की जाए, को छोड़कर विक्रय के लिए माल के विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर अभिप्रेत है;

(ङ.) "आकस्मिक व्यौहारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नकदी, आस्थगित संदाय, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल के क्रय, विक्रय, आपूर्ति या वितरण के कारबार का यदाकदा किए जाने वाले संव्यवहार करता है ;

(च) "आयुक्त" से धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त अभिप्रेत है;

(छ) "व्यौहारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो (चाहे नियमित रूप से या अन्यथा), नकदी के लिए या आस्थगित संदाय के लिए, या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः माल के क्रय, विक्रय, आपूर्ति या वितरण का कारबार करता है और निम्नलिखित इसके अन्तर्गत है,-

(i) स्थानीय प्राधिकरण, निगमित निकाय, कम्पनी, सहकारी सोसाइटी या अन्य सोसाइटी, क्लब, फर्म, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या अन्य व्यक्तियों का संगम जो ऐसा कारबार करता है;

(ii) फैक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, व्यौहारी का अभिकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए ;

(iii) कोई नीलामकर्ता जो किसी मालिक से सम्बन्धित, चाहे प्रकट किया गया है या नहीं, माल के विक्रय या नीलाम का कारबार करता है, और चाहे आशयित क्रेता की प्रस्थापना उस द्वारा या मालिक द्वारा अथवा मालिक के नाम-निर्देशित द्वारा स्वीकार की जाती है ;

(iv) निम्नलिखित कारबार में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति,—

(क) संविदा के अनुसरण से अन्यथा, नकद, आस्थगित

- संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में सम्पत्ति का अन्तरण;
- (ख) निर्माण संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल (जो माल के या किसी अन्य रूप में हो) में सम्पत्ति का अन्तरण ;
- (ग) अवक्रय या किस्तों द्वारा संदाय की किसी प्रणाली पर माल का परिदान;
- (घ) किसी प्रयोजन के लिए (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए है या नहीं) किसी माल का नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण;
- (ङ.) किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अपने सदस्य को नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल की आपूर्ति; और
- (च) माल की, किसी सेवा के रूप में या भागरूप में या किसी अन्य रीति में, जो भी हो, खाद्य या मानवीय उपयोग के लिए किसी अन्य वस्तु अथवा किसी पेय (चाहे मादक है या नहीं) के नाते आपूर्ति जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है ।

स्पष्टीकरण (1).—प्रत्येक व्यक्ति जो इस राज्य से बाहर निवास कर रहे किसी व्यौहारी के अधिकर्ता के रूप में हिमाचल प्रदेश में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, आपूर्ति या वितरण करता है या ऐसे व्यौहारी की ओर से निम्नलिखित रूप में कार्य करता है—

- 1930 का 3 (i) माल विक्रय अधिनियम, 1930 में यथा परिभाषित वाणिज्यिक अधिकर्ता; या
- (ii) माल की उठाई-धराई या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजों का अधिकर्ता; या
- (iii) माल की बिक्री कीमत के संदाय का संग्रहण करने के या ऐसे संग्रहण या संदाय के लिए प्रत्याभूतिदाता के रूप में अधिकर्ता;

और इस राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत फर्म या कम्पनी या अन्य निगमित निकाय की हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक स्थानीय शाखा या कार्यालय या कोई कम्पनी जिसका प्रधान कार्यालय या मुख्यालय इस राज्य के बाहर है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए व्यौहारी समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण (2).—सरकार का प्रत्येक विभाग या इसके अधीनस्थ कार्यालय जो चाहे कारबार के अनुक्रम में है या नहीं, प्रत्यक्षतः या अन्यथा नकदी या आस्थगित

संदाय के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय, विक्रय आपूर्ति या वितरण करता है, सिवाए अधिशेष, बेकार या पुराने सामान या सामग्री अथवा अपशिष्ट उत्पाद या गतकालिक या त्यक्त मशीनरी अथवा उसके भाग या उप-साधन के किसी विक्रय, आपूर्ति या वितरण के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए व्यौहारी समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण (3).—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए “सरकार” के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार होगी ;

- (ज) “घोषित माल” का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (ग) में इसका है ; 1956 का
- (झ) “उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त” से, इस अधिनियम की धारा 74 3 की उप धारा (1) के अधीन, आयुक्त की सहायता करने के लिए नियुक्त उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संयुक्त/अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त भी है;
- (ञ) “दस्तावेज” के अन्तर्गत हक विलेख, लिखित या उत्कीर्ण लेख, लेखा विवरण या किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिकली संचित डाटा और इसके सदृश जो साक्ष्य दे, सम्मिलित है;
- (ट) “माल” से (समाचार पत्रों, अनुयोज्य दावों, स्टाकों, शेयरों या प्रतिभूतियों से भिन्न) प्रत्येक प्रकार की जंगम सम्पत्ति अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत पशुधन, समस्त सामग्री, पदार्थ और वस्तुएं तथा कार्य संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य स्वरूप में) और समस्त उगती फसलें, घास, पेड़ और स्थाई रूप से भूबद्ध किसी चीज से बद्ध या जकड़ी हुई चीजें भी हैं किन्तु विक्रय संविदा के अधीन जिन्हें विच्छेद करने के लिए करार पाया गया है ;
- (ठ) “आयात” से हिमाचल प्रदेश में इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर के किसी स्थान से माल लाना अभिप्रेत है ;
- (ड) “आगत कर” (इनपुट टैक्स) से रजिस्ट्रीकृत क्रेता व्यौहारी द्वारा कारबार के अनुक्रम में पुनः विक्रय के लिए या कराधेय माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए या पात्र (कन्टेनर) या पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग के लिए या संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए माल के क्रय पर रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यौहारी को इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में संदत्त या संदेय रकम अभिप्रेत है ;
- (ढ) “बीजक” से कीमत, मात्रा, अन्तर्वलित कर और अन्य विशिष्टियां, जैसी विहित की जाएं, सहित माल को सूचीबद्ध करने वाला दस्तावेज अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत बिल, नकदी ज्ञापन, पर्ची, रसीद और इसके प्ररूप

के अनपेक्ष, समरूप अभिलेख भी है ;

- (ण) “मोटर स्प्रिट” से कोई ज्वलनशील हाइड्रो-कार्बन जिसके अन्तर्गत हाइड्रो-कार्बनों का मिश्रण या हाइड्रो-कार्बनयुक्त कोई द्रव्य है, अभिप्रेत है, जिसका साधारणतया किसी भी प्रकार के मोटरयान को युक्तियुक्त रूप से दक्ष चालक शक्ति देने के लिए साधारणतया प्रयोग किया जाता है ;
- (त) “अधिसूचना” से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;
- (थ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के सम्बन्ध में “उत्पाद कर” (आउटपुट टैक्स) से, कारबार के अनुक्रम में उस व्यौहारी द्वारा किए गए माल के किसी कराधेय विक्रय या क्रय की बाबत इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है ;
- (द) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (ध) “क्रय” से, इसके सभी व्याकरणिक या सजातीय पदों सहित किसी बन्धक, आड़मान, प्रभार या गिरबी के अधीन से अन्यथा नकद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का अर्जन अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:—

- (i) संविदा के अनुसरण से अन्यथा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी माल में सम्पत्ति का अन्तरण ;
- (ii) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में (चाहे माल या किसी अन्य रूप में हो) सम्पत्ति का अन्तरण ;
- (iii) अवक्रय पर या किस्तों में संदाय की किसी प्रणाली पर माल का परिदान;
- (iv) किसी प्रयोजन के लिए (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए है या नहीं) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण;
- (v) किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अपने सदस्य को नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल की आपूर्ति ;
- (vi) माल की किसी सेवा या भाग के रूप में या किसी अन्य रीति जो भी हो, खाद्य या मानवीय उपयोग के लिए किसी अन्य वस्तु अथवा किसी पेय (चाहे मादक है या नहीं) के नाते आपूर्ति, जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है ;

और किसी माल का ऐसा अन्तरण, परिदान या आपूर्ति उस माल का अन्तरण, परिदान या प्रदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय और उस व्यक्ति द्वारा, जिसको ऐसा अन्तरण, परिदान या आपूर्ति की जाती है, उस माल का क्रय समझा जाएगा ;

- (न) "रजिस्ट्रीकृत" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है ;
- (प) "प्रतिवर्ती आगत कर" (रिवर्स इनपुट टैक्स) से किसी भी प्रकार के माल से सम्बन्धित आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की वह रकम अभिप्रेत है, जिसके लिए आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ उठाया गया है, किन्तु जो धारा 11 की उप-धारा (9) और (10) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में प्रतिवर्तित हो जाएगा ;
- (फ) "विक्रय" से बन्धक, आड़मान, प्रभार या गिरबी से भिन्न नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए सम्पत्ति का माल में कोई अन्तरण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:—

- (i) किसी संविदा के अनुसरण से अन्यथा, नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यावान प्रतिफल के लिए माल में सम्पत्ति का अन्तरण ;
- (ii) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में (चाहे माल या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति का अन्तरण ;
- (iii) अवक्रय या किस्तों में संदाय की किसी प्रणाली पर माल का परिदान ;
- (iv) किसी भी प्रयोजन के लिए (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए है या नहीं) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण ;
- (v) किसी भी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अपने सदस्य को नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल की आपूर्ति ;
- (vi) माल की, किसी सेवा का भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में जो भी हो, खाद्य या मानवीय उपयोग के लिए किसी अन्य वस्तु अथवा किसी पेय (चाहे मादक है या नहीं) के नाते आपूर्ति, जहाँ ऐसी आपूर्ति या सेवा, नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है ;

और किसी माल का ऐसा अन्तरण, परिदान या आपूर्ति उस माल का अन्तरण, परिदान या प्रदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय और उस व्यक्ति द्वारा, जिसको ऐसा अन्तरण, परिदान या आपूर्ति की जाती है, उस माल का क्रय समझा जाएगा ;

- (ब) "अनुसूची" से, अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (भ) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (म) "राज्य सरकार" या "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (य) "कर" या "मूल्य परिवर्धित कर" से धारा 6 या धारा 7 के अधीन माल के विक्रय या क्रय पर उद्गृहीत कर अभिप्रेत है;
- (यक) "कर अवधि" से, विवरणी दाखिल करने के लिए विहित अवधि अभिप्रेत है ;
- (यख) "इमारती लकड़ी" के अन्तर्गत वृक्ष आते हैं जब वे गिर गए हों या गिराए गए हों अथवा गिराए जाने के लिए तय पाए गए हों और सब प्रकार की लकड़ी है चाहे वह किसी प्रयोजन के लिए काटी, गढ़ी या खोखली की गई हो या न की गई हो;
- (यग) "अधिकरण" से, धारा 44 के अधीन स्थापित अधिकरण अभिप्रेत है ;
- (यघ) "आवर्त" से, दी गई अवधि के दौरान किसी भी व्यौहारी द्वारा दी गई अवधि के दौरान किए गए विक्रयों, क्रयों तथा विक्रयों और क्रयों के भागों की सकलित रकम अभिप्रेत है और माल भाड़े, भण्डारकरण, डेमेरेज, बीमे के मद्दे और माल के बारे में उसके परिदान के समय या उससे पूर्व व्यौहारी द्वारा की गई किसी बात के लिए, प्रभारित कोई रकम भी इसके अन्तर्गत है ;

स्पष्टीकरण (I).— किसी व्यौहारी द्वारा, जो हिमाचल प्रदेश के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर कारबार करता है, तो हिमाचल प्रदेश से बाहर किए गए विक्रय के आगमों को आवर्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण (II).—अग्रिम संविदाओं के संव्यवहारों के बारे में किसी व्यौहारी के आवर्त, जिनमें वस्तुतः माल का परिदान नहीं किया जाता है, आवर्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण (III).— किसी माल के विक्रय आगमों जिनके क्रय पर इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्राह्य है, या किसी माल का क्रय मूल्य जिसके विक्रय पर इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्राह्य है, आवर्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण (IV).— साधारण व्यापार पद्धति (आर्डनरी ट्रेड प्रैक्टिस) के अनुसार नकद छूट के रूप में अनुज्ञात राशि ।

स्पष्टीकरण (V).— अवक्रय या किशतों द्वारा संदाय की किसी भी पद्धति पर माल के परिदान की बाबत आवर्त में सम्मिलित की जाने वाली रकम इस प्रकार परिदत्त माल या किशतों पर वस्तुतः संदत्त रकम की बाबत अवक्रय करार के अधीन भाड़े पर लेने वाले द्वारा संदेय कुल राशि होगी ।

स्पष्टीकरण (VI).— संकर्म निविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में (चाहे यथा माल या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति के अन्तरण के बारे आवर्त में सम्मिलित की जाने वाली रकम इस की विक्रय कीमत होगी ।

- (यड.) “यान” के अन्तर्गत भूमि पर या जल अथवा वायु में प्रयोग की जाने वाली कोई गाड़ी या वाहन है; और
(यच) “वर्ष” से, वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय- 2

कराधायक प्राधिकारी

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को आबकारी एवं कराधान आयुक्त के रूप में और ऐसे अन्य व्यक्तियों को ऐसे पदनामों के साथ जैसा वह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इतने निर्धारण प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह उचित समझे ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्ति ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित हों या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रदत्त किए जाएं ।

(4) आयुक्त और राज्य मुख्यालय में तैनात अन्य अधिकारियों की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा और अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की अधिकारिता का विस्तार, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेशित न करे, अधिसूचना द्वारा जिलों या जिलों के उन क्षेत्रों जिनमें कि वे तत्समय तैनात हैं विस्तारित किया जाएगा ।

अध्याय- 3

कर का भार, उद्ग्रहण और दर

4. (1) धारा 6, 7 और धारा 16 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के कर का अध्वधीन, प्रत्येक व्यौहारी (धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल में अनन्य भार। रूप से कारबार कर रहे के सिवाए) जिसका सकल आवर्त इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कराधेय मात्रा से अधिक था, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् किए गए सभी विक्रयों और क्रयों पर इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी होगा ।

(2) प्रत्येक व्यौहारी जो धारा 9 के अधीन कर-मुक्त घोषित किए गए माल का अनन्य रूप से कारबार नहीं करता है तो वह इस अधिनियम के अधीन उस तारीख से, जिससे उसका सकल आवर्त किसी भी वर्ष में कराधेय मात्रा से प्रथमतः अधिक हो जाता है, कर संदत्त करने का दायी होगा ।

(3) उप-धारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी माल के विक्रय पर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा यदि इस अधिनियम के अधीन उनके क्रय पर कर उद्गृहीत किया गया है ।

(4) प्रत्येक व्यौहारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी हो गया है, तीन क्रमवर्ती वर्षों के अवसान तक, जिनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान उसका सकल आवर्त कराधेय मात्रा से अधिक होने में असफल रहा है और ऐसे अवसान की तारीख के पश्चात् ऐसी अतिरिक्त अवधि तक, जैसी विहित की जाए, इस प्रकार दायित्वाधीन बना रहेगा और इसके पश्चात्पूर्वी अवधि के अवसान पर उसका कर देने का दायित्व समाप्त हो जाएगा ।

(5) प्रत्येक व्यौहारी, जिसका उप-धारा (4) के उपबन्धों के अधीन कर संदत्त करने का दायित्व समाप्त हो गया है, इस अधिनियम के अधीन उस तारीख से, जिसको उस का सकल आवर्त प्रथमतः कराधेय मात्रा से अधिक हो जाता है, कर संदत्त करने का पुनः दायी होगा ।

(6) इस अधिनियम में, 'कराधेय मात्रा' पद से अभिप्रेत है, —

(क) किसी व्यौहारी के सम्बन्ध में, जो किसी माल के विक्रय के लिए अथवा विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोगार्थ हिमाचल प्रदेश में किसी माल का आयात करता है ... एक रुपया;

(ख) किसी व्यौहारी के सम्बन्ध में, जो विक्रय के लिए किसी माल का स्वयं विनिर्माण या उत्पादन करता है ... 2,00,000/- रुपये;

(ग) किसी व्यौहारी के सम्बन्ध में, जो होटल, रेस्तरां, बेकरी या अन्य ऐसा ही स्थापन चलाता है, जिसमें चाय सहित तैयार खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं ... 2,00,000/- रुपये;

(घ) खण्ड (क), (ख), और/या (ग) के अन्तर्गत न आने वाले व्यौहारियों के किसी विशिष्ट वर्ग के सम्बन्ध में, ऐसी राशि जो विहित की जाए; या

(ङ) किसी अन्य व्यौहारी के सम्बन्ध में ... 4,00,000/- रुपये :

परन्तु इस खण्ड के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों का रजिस्ट्रीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि उनका आवर्त प्रत्येक तीन क्रमवर्ती वर्षों में उप-धारा (4) के अधीन उन्हें रद्दकरण का हकदार नहीं बनाता है ।

केन्द्रीय
विक्रय कर
अधिनियम,
1956 के
अधीन
रजिस्ट्रीकृत
व्यौहारी का
दायित्व।

5. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी 1956 का 74 जो धारा 4 के अधीन कर संदत्त करने का दायी नहीं है, ऐसा होने पर भी इस अधिनियम के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर उस द्वारा किए गए किसी विक्रय या क्रय पर कर संदत्त करने का दायी होगा :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात उस व्यौहारी पर लागू नहीं होगी जो धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल का अनन्य रूप से कारबार करता है।

कर का
उद्ग्रहण ।

6. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन,—

(क) अनुसूची “क” के द्वितीय स्तंभ में विनिर्दिष्ट माल की बाबत विक्रय के प्रत्येक स्तर (प्वाइंट) पर,

(ख) अनुसूची “ग” के द्वितीय स्तंभ में विनिर्दिष्ट माल की बाबत क्रय के विहित स्तर (प्वाइंट) पर, और

(ग) अनुसूची “घ” के द्वितीय स्तंभ में विनिर्दिष्ट माल की बाबत विक्रय के प्रथम स्तर (प्वाइंट) पर,

व्यौहारी के कराधेय आवर्त पर अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट दरों पर, तत्सम्बन्धी अनुसूचियों में या रुपये में सौ पैसे से अनधिक ऐसी दरों पर, जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, कर उद्गृहीत किया जाएगा :

परन्तु राज्य सरकार भिन्न-भिन्न प्रकार के माल या माल की श्रेणियों की बाबत भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित कर सकेगी :

1956 का 74 परन्तु यह और कि घोषित माल के बारे में कर की दर, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कर की अधिकतम दर से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि घोषणा, जो विहित की जा सकेगी, प्रस्तुत किए जाने के अध्यक्षीन, सरकार अधिसूचना द्वारा उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहीत कर की दर को, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी न होते हुए, सरकार को तार संचार नेटवर्क, या विद्युत के उत्पादन या वितरण में या उर्जा के किसी और रूप में, आबद्ध (कैपिटिव) प्रयोग हेतु विक्रीत माल की बाबत, चार प्रतिशत तक कम कर सकेगी ।

(2) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई माल किसी पात्र (कन्टेनर) में विक्रीत किया जाता है या किसी पैकिंग सामग्री में पैक किया जाता है तो ऐसे पात्र (कन्टेनर) या पैकिंग सामग्री के लिए लागू कर की दर वही होगी जो उसमें अन्तर्विष्ट या पैक किए गए माल को लागू है चाहे पात्र (कन्टेनर) या पैकिंग सामग्री की कीमत अलग से प्रभारित की गई है या नहीं और पात्र (कन्टेनर) या पैकिंग सामग्री की बाबत आवर्त ऐसे माल की आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा। जहां पात्र (कन्टेनर) और पैकिंग सामग्री में विक्रीत माल कर मुक्त है वहां ऐसे पात्र (कन्टेनर) या पैकिंग सामग्री की बिक्री भी कर मुक्त होगी ।

(3) इस अधिनियम में पद “कराधेय आवर्त” से, किसी भी अवधि के दौरान व्यौहारी के सकल आवर्त का वह भाग अभिप्रेत है, जो उससे,—

(क) उस अवधि के दौरान निम्नलिखित पर उसके आवर्त—

- (i) धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल का विक्रय;
- (ii) धारा 58 के अधीन आने वाले माल का विक्रय और क्रय; और
- (iii) अन्य ऐसे विक्रय और क्रय जो विहित किए जाए; और

(ख) सकल आवर्त में सम्मिलित कर की रकम, की कटौती के पश्चात् शेष रह जाता है ।

उपधरणात्मक
कर का
उद्ग्रहण ।

7. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, जिसका सकल आवर्त किसी भी वर्ष में ऐसी रकम से अधिक नहीं होता है, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के बदले, यथास्थिति, विक्रयों या क्रयों के सम्पूर्ण कराधेय आवर्त पर, धारा 6 में विनिर्दिष्ट दरों से अनधिक, ऐसी दरों पर, जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उपधरणात्मक कर संदत्त करेगा :

परन्तु ऐसे व्यौहारी को कोई आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) उपलब्ध नहीं होगा :

परन्तु यह और कि कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, जो विक्रय के लिए या विक्रय के लिए किसी भी प्रकार के माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग के लिए किसी माल का आयात करता है तो वह इस धारा के अधीन उपधरणात्मक कर का संदाय करने का हकदार नहीं होगा ।

कतिपय
परिस्थितियों
में कतिपय
माल पर
क्रय-कर का
उद्ग्रहण।

8. जहां व्यौहारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी है, अनुसूची "ख" में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल किसी स्रोत से खरीदता है, और—

- (क) अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में राज्य के भीतर उपयोग करता है, या
- (ख) अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न किसी माल के विनिर्माण में उनका उपयोग राज्य के भीतर करता है और इस प्रकार विनिर्मित माल का अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न किसी रीति में राज्य से बाहर भेजता है, या
- (ग) ऐसे माल का, राज्य में पुनर्विक्रय या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, या
- (घ) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न किसी रीति में उनको राज्य से बाहर भेजता है;

और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ऐसे माल के क्रय

पर कोई भी कर संदेय नहीं है, तो ऐसे माल के क्रय पर राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित दर के बराबर कर उद्गृहीत किया जाएगा।

9. अनुसूची 'ख' के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर कोई कर मुक्त भी कर, उसके तृतीय स्तम्भ में उपवर्णित तटस्थानी प्रविष्टि की शर्तों और उपवादों के अध्वधीन, यदि कोई हो, देय नहीं होगा और कोई भी व्यौहारी माल के विक्रय पर, जो इस धारा के अधीन समय-समय पर कर मुक्त घोषित किए जाते हैं, विक्रय कर प्रभारित नहीं करेगा।

10. राज्य सरकार इसका ऐसा करने के आशय का अधिसूचना द्वारा कम से कम तीस दिन का नोटिस देने के पश्चात्, ऐसी ही अधिसूचना द्वारा "क", "ख", "ग" और "घ" अनुसूचियों में किसी भी प्रकार के माल का परिवर्धन या लोप कर सकेगी या अन्यथा इन अनुसूचियों में संशोधन कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा।

11. (1) आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट), जिसके लिए क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् क्रेता व्यौहारी कहा गया है) दावा करने का हकदार है, ऐसे व्यौहारी जिसने कर योग्य माल का विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से क्रय किया है, कर अवधि के दौरान उस द्वारा, ऐसी शर्तों के अध्वधीन जो विहित की जाए, किए गए क्रयों के आवर्त पर संदत्त या संदेय कर की रकम होगी और आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) इस धारा में यथा उपबन्धित के अनुसार संगणित किया जाएगा और ऐसी शर्तों के अध्वधीन अनुज्ञात किया जाएगा जो विहित की जा सकेगी।

(2) आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त करने वाला व्यौहारी कर बीजक, रजिस्टर और लेखा बहियाँ ऐसी रीति में रखेगा जो विहित की जाएं।

(3) आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) क्रेता व्यौहारी द्वारा राज्य में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जो विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रखता हो, क्रय किए गए कराधेय माल पर संदत्त आगत कर (इनपुट टैक्स) की रकम की सीमा तक ही अनुज्ञात किया जाएगा, जो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आशयित हों, —

- (क) राज्य में उनके द्वारा माल के विक्रय या पुनर्विक्रय; या
- (ख) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय; या

- (ग) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय; या
 (घ) खण्ड (क), (ख) या (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति के विक्रय के लिए कराधेय माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में कच्चे माल के रूप में या पूंजी माल के रूप में उपयोग; या
 (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति के विक्रय के लिए कराधेय माल के पात्रों (कन्टेनरज) या पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग :

परन्तु यदि इस प्रकार क्रय किया गया माल इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अंशतः उपयोग में लाया जाता है तो आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट), इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उनके उपयोग के विस्तार के अनुपात में, अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ईन्धनों और स्नेहकों पर आगत कर प्रत्यय, इस शर्त के अध्वधीन कि ऐसे ईन्धन और स्नेहक कराधेय माल के विनिर्माण या उर्जा के आवद्ध (कैपटिव) उत्पादन में प्रयुक्त किए गए हैं, उस विस्तार तक अनुज्ञात किया जाएगा जिस के द्वारा राज्य में संदत्त आगत कर (इनपुट टैक्स) की रकम 4 प्रतिशत से अधिक हो जाती है ।

(4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) उस विस्तार तक अनुज्ञात किया जाएगा जिस के द्वारा राज्य में संदत्त आगत कर (इनपुट टैक्स) की रकम,-

- (क) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से अन्यथा राज्य से बाहर भेजे गए ; और
 (ख) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से अन्यथा कराधेय माल के विनिर्माण या पैकिंग में प्रयुक्त किए गए, माल के क्रय पर चार प्रतिशत से अधिक हो जाती है ।

(5) क्रेता व्यौहारी द्वारा आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का उस कर अवधि के लिए दावा नहीं किया जाएगा जिससे वह उस रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जिससे उसने माल का क्रय किया है, जब तक विहित प्ररूप में कर बीजक

(मूल रूप में) आगत कर (इनपुट टैक्स) की रकम की अदायगी के साक्ष्य के रूप में, प्राप्त नहीं कर लेता है :

परन्तु सही और पर्याप्त कारणों को लिखित में अभिलिखित कर के और विहित रीति में, धारा 3 के अधीन नियुक्त आयुक्त या किसी व्यक्ति द्वारा यथा विहित की गई ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्वधीन ऐसे प्रत्यय (क्रेडिट) को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(6) पूंजी माल पर आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) तैयार माल के विनिर्माण और प्रसंस्करण के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध प्लांट और मशीनरी तक सीमित होगा और इस धारा के अधीन अनुज्ञेय आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने की तारीख से प्रारम्भ होगा और तीन वर्ष की अवधि से ऊपर के विक्रय की आवर्त पर संदेय कर के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि से पूर्व कारबार के बन्द होने की दशा में, कोई आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा और अग्रेषित आगत कर (इनपुट टैक्स), यदि कोई हो, समपहत किया जाएगा ।

(7) क्रेता व्यौहारी द्वारा, भी आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का न तो दावा किया जाएगा न ही उसे निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,—

- (क) धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या पैकिंग में प्रयुक्त माल के क्रयों पर संग्रहीत कर के लिए ;
- (ख) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात या राज्य के बाहर से आयात के अनुक्रम में किए गए क्रयों के लिए किसी भी अन्य देश या अन्य राज्य में संदत्त कर की बाबत ;
- (ग) राज्य में,—

- (i) किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यौहारी या आकस्मिक व्यौहारी से, या
- (ii) व्यौहारी से, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलम्बित किया गया हो, या
- (iii) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जिसने धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन शमन स्वरूप धारा 7 के अधीन उपधारणात्मक

कर स्वरूप या कर के बदले एक मुश्त रकम संदत्त करने का विकल्प दिया हो, से क्रय किए गए माल के लिए;

- (घ) मुफ्त नमूने या दान या व्यक्तिगत उपयोग के रूप में प्रयुक्त माल के विक्रय के लिए ;
- (ङ) उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट उपयोगों के लिए क्रय किए गये माल के लिए किन्तु जिनका प्राकृतिक आपदाओं सहित चोरी, हानि या नष्ट होने के किसी कारण से विक्रय नहीं किया गया हो ;
- (च) उप-धारा (6) में विनिर्दिष्ट से अन्यथा पूंजी माल के क्रय के लिए;
- (छ) कारबार बन्द करने के समय अविक्रीत बचे माल के स्टॉक के लिए, और यदि व्यौहारी ने पहले ही ऐसे क्रय किए गये माल के स्टॉक के लिए कोई आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) लिया हो, वहां ऐसे कारबार के बन्द होने पर प्रतिवर्तित कर उधार (रिवर्स टैक्स क्रेडिट) लगेगा ;
- (ज) उप-धारा (4) में यथा उपबन्धित के सिवाय माल के क्रय पर संगृहीत कर के लिए, किन्तु जिन्हें तत्पश्चात् राज्य के बाहर किसी स्थान पर अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय से अन्यथा, किसी रीति में भेजा गया है ;
- (झ) उप-धारा (4) में यथा उपबन्धित के सिवाय माल के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किये गए माल के क्रय पर संगृहीत कर के लिए, और ऐसा विनिर्मित माल विक्रय से अन्यथा किसी रीति में राज्य के बाहर अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में भेजा गया है ;
- (ञ) किसी भी प्रयोजन के लिए (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) अधिकार के अन्तरण के अधीन विक्रय हेतु माल के क्रय के लिए ;
- (ट) क्रयों के लिए जहां,—
 - (i) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के पास कर बीजक उपलब्ध न हो ; या
 - (ii) जहां साक्ष्य हो कि विक्रेता व्यौहारी द्वारा, जिससे माल क्रय किया गया है या क्रय किया गया कहा गया है, द्वारा कर बीजक जारी नहीं किया गया है; या
 - (iii) विक्रेता व्यौहारी द्वारा, जिससे क्रेता व्यौहारी ने माल क्रय किया है, द्वारा मूल कर बीजक में पृथक रूप से प्रभारित कर का व्यौरा अन्तर्विष्ट नहीं है ।

(8) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विहित रीति में किसी भी माल को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसकी बाबत आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) भाग में या पूर्ण रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा या व्यौहारियों के उस वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो भाग में या पूर्ण रूप में आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के हकदार नहीं होंगे ।

(9) यदि क्रय किया गया माल उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आशयित है और तत्पश्चात् उक्त उप-धारा में विनिर्दिष्ट से भिन्न प्रयोजनों के लिए पूर्ण रूप से या अंशतः उनका उपयोग किया गया है, तो आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट), यदि ऐसे क्रय के समय उसका लाभ उठाया गया है, उस कर अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसा उपयोग हुआ है दावाकृत आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) से कम कर दिया जाएगा और ऐसी कमी ऐसी रीति में की जाएगी जो विहित की जा सकेगी ।

(10) इस धारा के उपबन्धों के अधधीन आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) जिसका पहले लाभ उठाया गया है प्रतिवर्तित हो जाएगा यदि; —

- (क) व्यौहारी कारबार बन्द कर देता है; या
- (ख) व्यौहारी को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है; या
- (ग) माल उप-धारा (6) के खण्ड (घ), (ङ), या (छ) के अन्तर्गत आता है; या
- (घ) अधिक आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का दावा किया गया है; या
- (ङ) क्रय किया गया माल विक्रेता व्यौहारी को ऐसे माल का क्रय करने की तारीख से तीन मास के भीतर वापस कर दिया गया हो ; या
- (च) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय कर से अधिक प्रभारित किए गए कर की रकम के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यौहारी से जमा पत्र (क्रेडिट नोट) प्राप्त किया जा चुका हो ; या
- (छ) कोई अन्य यथाविहित परिस्थितियां विद्यमान हों ।

(11) व्यौहारी प्रतिवर्ती आगत कर प्रत्यय (रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम धारा 19 के अधीन ब्याज सहित विवरणी दाखिल करने के लिए विहित अन्तिम तारीख से ठीक पश्चात्वर्ती तारीख से उस अवधि के लिए संदत्त करने का दायी होगा जिसके लिए ऐसा आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का इसके

1ak; dh rgh[k rd nlok fl ;k x;k Fk।

(12) जहां किसी क्रेता व्यौहारी को साख पत्र या नामें नोट जारी किया जा चुका है या यदि वह क्रय किए गए माल को वापस करता या नामंजूर करता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर अवधि के दौरान (जिससे माल का क्रय सम्बन्धित है) आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) जिसका उसके द्वारा लाभ उठाया गया है, या तो कम हो जाता है या अधिक हो जाता है, तो वह ऐसी कमी या अधिकता को उस कर अवधि की बाबत जिसमें उसे साख पत्र या नामें नोट जारी किया गया है या माल वापस किया या नामंजूर किया गया है, विहित की जाने वाली शर्तों के अधीन उसे अनुज्ञात आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम को समायोजित कर क्षतिपूरित करेगा ।

(13) शुद्ध आगत कर प्रत्यय (नैट इनपुट टैक्स क्रेडिट) जिसका क्रेता व्यौहारी द्वारा लाभ उठाया जा सकेगा, की रकम निम्नलिखित सूत्र (फार्मूले) के आधार पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात् :—

$$\text{शुद्ध आगत कर प्रत्यय} = \text{क} + \text{ख} - \text{ग}$$

स्पष्टीकरण.— इस सूत्र (फार्मूले) में —

- (i) “क” आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम का द्योतक है जिसके लिए क्रेता व्यौहारी हकदार है ;
- (ii) “ख” पूर्व अवधि से अग्रनीत किए गए परादेय आगत कर प्रत्यय (आउटस्टैंडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट) का द्योतक है ; और
- (iii) “ग” उप-धारा (10) के अधीन यथा अवधारित प्रतिवर्ती आगत कर प्रत्यय (रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट) को द्योतक करता है ।

(14) पद्धतियां, जो क्रेता व्यौहारी द्वारा वर्ष में उस परिमाण, जिस तक कराधेय विक्रय करने के अनुक्रम में माल विक्रीत, प्रयुक्त, उपभुक्त या आपूरित किया गया है या विक्रय करने, प्रयोग करने या आपूरित करने के लिए आशियत है, को अवधारित करने के लिए प्रयुक्त की गई है, उचित और युक्तियुक्त होगी :

परन्तु आयुक्त या धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, व्यौहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और लिखित में कारणों को अभिलिखित करके क्रेता व्यौहारी द्वारा अपनाई गई पद्धति को नामंजूर कर सकेगा और आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम को संगणित कर सकेगा ।

(15) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी विक्रय संव्यवहार किए बिना ही, दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को कर बीजक, परचून बीजक, बिल या कैश मेमों को राज्य सरकार के राजस्व को प्रबंचित करने के आशय से जारी करता है या इस आशय

से जारी करता है जिसे कि सरकार अपने राजस्व से प्रबंधित हो जाए तो आयुक्त या धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी जांच पड़ताल जैसी वह ठीक समझे, करने के पश्चात् ऐसे कर बीजक, परचून बीजक, बिल या केश में या अन्य बीजक जारी करने वाले या स्वीकार करने वाले ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को या तो भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से ऐसी तारीख, जैसी वह नियत करे, से आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ देने से इन्कार कर सकेगा।

12. (1) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा कर अवधि के लिए संदेय शुद्ध कर, संदेय शुद्ध उत्पाद कर जमा क्रय कर, यदि कोई हो, और आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स कर। क्रेडिट) जिसे निम्नलिखित सूत्र (फार्मूले) से अवधारित किया जा सकता है अर्थात:-
शुद्ध संदेय कर = (ओ+पी)-आई

स्पष्टीकरण.—इस सूत्र (फार्मूले) में—

- (i) “ओ” अक्षर किसी भी कर अवधि के लिए संदेय उत्पाद कर (आउटपुट टैक्स) का द्योतक है ;
- (ii) “पी” अक्षर किसी भी कर अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा संदत्त कर का द्योतक है ;
- (iii) “आई” अक्षर उक्त कर अवधि के लिए संदत्त या संदेय आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का द्योतक है जिसके अन्तर्गत धारा 11 के अधीन अवधारित किसी पूर्ववर्ती कर अवधि से अग्रेषित किया गया आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट), यदि कोई हो, सम्मिलित है ।

(2) यदि आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम, उत्पाद कर (आउटपुट टैक्स) की रकम से अधिक है तो उसे व्यौहारी के विकल्प पर उक्त कर अवधि, यदि कोई हो, के लिए कर दायित्व के विरुद्ध केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन समायोजित किया जा सकेगा केवल केन्द्रीय विक्रय कर की अतिशेष रकम संदेय होगी ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन समायोजन के पश्चात् आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, को इस अधिनियम के अधीन किसी परादेय कर के लिए, शास्ति या ब्याज के विरुद्ध या, व्यौहारी के विकल्प पर या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन, समायोजित किया जाएगा ।

(4) उप-धारा (2) और (3) के अधीन समायोजित करने के पश्चात् आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, को पश्चात्वर्ती कर अवधि के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा या व्यौहारी के विकल्प पर, विहित रीति में किए गए आवेदन पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिदत्त किया जाएगा ।

(5) किसी कर अवधि के लिए किसी व्यौहारी, जो कर संदत्त करने के लिए दायी है परन्तु जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, द्वारा संदेय शुद्ध कर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त कर अवधि के लिए संदेय उत्पाद कर (आऊटपुट टैक्स) जमा क्रय कर, यदि कोई हो, के बराबर होगा और कोई आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) उसे अनुज्ञेय नहीं होगा ।

सबूत का
भार ।

13. व्यौहारी द्वारा किए गए किसी विक्रय या कय के बारे में यह सावित करने का भार कि वह धारा 6 या धारा 8 के अधीन कर संदत्त करने का दायी नहीं है या वह धारा 11 के अधीन आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का पात्र है, उस पर होगा ।

अध्याय-4

रजिस्ट्रीकरण, विवरणियां, निर्धारण, वसूली और कर का प्रतिदाय

व्यौहारियों
का
रजिस्ट्रीकरण।

14. (1) कोई भी व्यौहारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी हो तब तक व्यौहारी के रूप में कारबार नहीं करेगा जब तक वह रजिस्ट्रीकृत न हो और उसके पास रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र न हो :

परन्तु आकस्मिक व्यौहारी की दशा में, पचास रुपये की फीस के भुगतान पर, निर्धारण प्राधिकारी या चैक पोस्ट या बैरिअर का प्रभारी अधिकारी या किसी अन्य स्थान पर माल का निरीक्षण करने वाला कोई अन्य अधिकारी इस धारा के अधीन विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगा ।

(2) किसी भी व्यक्ति को जो हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए माल के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए कारबार स्थापित करने का आशय रखता हो, इस बात के होते हुए भी कि वह उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है, को ऐसी शर्तों के अध्वधीन और ऐसी रीति में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए और ऐसा व्यक्ति जब जिसे ऐसा

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो, अधिनियम के अधीन उस समय तक कर संदत्त करने का दायी होगा जब तक ऐसा प्रमाण पत्र प्रवृत्त रहता है :

परन्तु ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्रदान किया जाना ऐसी शर्तों के अधीन होगा कि यदि ऐसा व्यक्ति प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कारबार स्थापित करने में असफल रहता है या उसमें विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो वह निर्धारण प्राधिकारी के आदेश द्वारा कर की रकम के आधे के समतुल्य, जो उस द्वारा क्रय किए गये समस्त माल की बाबत संदेय होती मानो कि वह इस उप-धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं था, शास्ति संदत्त करने के लिए दायी होगा ।

परन्तु यह और कि कराधेय माल का विक्रय करने वाला कोई व्यौहारी, जो उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है परन्तु जो स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकृत होने की वांछा रखता है तो वह विहित की जाने वाली रीति में समुचित निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन करेगा और वह उस तारीख से, जिस को कि उसका सकल आवर्त धारा 4 की उप-धारा (6) में यथा विनिर्दिष्ट कराधेय मात्रा से अधिक हो जाता है, धारा 4 के अनुसार कर संदत्त करेगा ।

(3) उप-धारा (1) द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यौहारी और प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकेगा, निर्धारण प्राधिकारी को इस निमित्त विहित रीति में आवेदन करेगा ।

(4) यदि निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सही रूप में है तो वह ऐसे नियमों के अनुसार और ऐसी फीस के संदाय पर और यथा विहित की गई ऐसी शर्तों के अधीन आवेदक को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसे विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा ।

(5) जब कोई व्यौहारी उप-धारा (1) के उल्लंघन में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण इस प्रकार प्रभावी होगा जैसे कि यह व्यौहारी के आवेदन पर उप-धारा (4) के अधीन किया गया था ।

(6) निर्धारण प्राधिकारी आदेश द्वारा,—

- (क) व्यौहारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का संशोधन कर सकेगा यदि व्यौहारी या उसका विधिक प्रतिनिधि यह सूचना प्रस्तुत करता है कि —
- (i) उसने अपना कारबार अन्तरित (ट्रान्सफर) कर दिया है, या
 - (ii) उसने कारबार का नाम (संविधान) या उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया है, या
 - (iii) वह कारबार का नया स्थान खोलना चाहता है या कारबार के स्थानों में या अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट पुनः विक्रय या विक्रय के लिए माल के निर्माण में उपयोग हेतु माल की श्रेणी या श्रेणियों में कोई परिवर्तन करना चाहता है;
- (ख) किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को निलम्बित कर सकेगा यदि व्यौहारी या व्यक्ति ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया है ;
- (ग) यथास्थिति, व्यौहारी या उसके विधिक प्रतिनिधि के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से ऐसे रद्दकरण तक कर संदत्त करने के दायित्व को प्रभावित किए बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर सकेगी,-
- (i) यदि व्यौहारी अपने कारबार या कारबार के किसी स्थान का विक्रय करता है या अन्यथा निपटान करता है या अपना कारबार बन्द करता है, या
 - (ii) यदि व्यौहारी की मृत्यु हो जाती है, या
 - (iii) किसी अन्य प्रर्याप्त हेतुक के लिए, जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का दुरुपयोग या इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के दायित्व की परिवर्ति (समाप्ति) भी है :

परन्तु इस उप-धारा के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना

उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश नहीं किया जाएगा; और

(घ) ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जा सकेगी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण करेगा ।

15. (1) आयुक्त या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उस की सहायता करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति को यदि इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर की उचित वसूली के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत होता है तो वह कारणों को अभिलिखित करके, व्यौहारी को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने या किसी व्यौहारी को जारी किए गए ऐसे प्रमाण पत्र के प्रभाव में बने रहने की शर्त के रूप में, यह अपेक्षा अधिरोपित कर सकेगा कि व्यौहारी ऐसी रकम के लिए विहित रीति में प्रतिभूति देगा जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

व्यौहारियों के कतिपय वर्ग से प्रतिभूति।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी भी व्यौहारी से प्रतिभूति देना तब तक अपेक्षित नहीं होगा, जब तक उसे सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है ।

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यौहारी द्वारा दी गई प्रतिभूति प्रतिभू-बंधपत्र के रूप में है और प्रतिभू दिवालिया हो जाता है या अन्यथा असमर्थ हो जाता है अथवा मर जाता है या नाम वापस ले लेता है, तो वहां व्यौहारी, उपर्युक्त घटनाओं में से किसी के घटित होने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र देने वाले प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसी घटना के तीस दिन के भीतर एक नया प्रतिभू-बंधपत्र देगा ।

(4) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा, अच्छे और पर्याप्त हेतुक के लिए किसी व्यौहारी द्वारा संदेय कर, ब्याज या शास्ति की किसी रकम को वसूल करने के लिए व्यौहारी द्वारा दी गयी सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा :

परन्तु व्यौहारी और प्रतिभू को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना, इस उप-धारा के अधीन कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

(5) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी, व्यौहारी द्वारा आवेदन करने पर, उस द्वारा दी गई प्रतिभूति या उसके किसी भाग को वापस करने

का आदेश कर सकेगा, यदि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित न हो ।

कर का
संदाय और
विवरणियाँ।

16. (1) अधिनियम के अधीन संदेय कर, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में ऐसे अन्तरालों पर, जो विहित किए जाएं, संदत्त किया जाएगा ।

(2) राज्य सरकार, लोक हित में और ऐसी शर्तों के अधीन जैसी वह उचित समझे, व्यौहारियों के किसी वर्ग से, इस अधिनियम के अधीन किसी अवधि के लिए संदेय कर की रकम के बदले में, प्रशमन के रूप में, ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए अवधारित और संदत्त की जाने वाली एक मुश्त राशि स्वीकार कर सकेगी या एक मुश्त रकम को कराधेय आवर्त पर नियत दर पर संगणित किया जा सकेगा, जैसी ऐसे वर्ग के व्यौहारियों की बाबत विहित की जा सकेगी और इस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण, लेखों के अनुरक्षण, विवरणियों को दाखिल करने की सरलीकृत पद्धति भी विहित की जा सकेगी जो ऐसे शमन की अवधि के दौरान प्रवृत्त रहेगी ।

(3) ऐसे व्यौहारी, जिनसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, विहित रीति में तामिल किए गए नोटिस द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ऐसी विवरणियाँ, ऐसी तारीख तक और ऐसे प्राधिकारी को देगा, जो विहित किया जाए ।

(4) इससे पूर्व कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित विवरणियाँ दे, वह ऐसी विवरणियों के अनुसार अधिनियम के अधीन उस से देय कर की पूर्ण रकम किसी सरकारी खजाने में या अनुसूचित बैंक में जो खजाना बैंक (ट्रेजरी बैंक) है अथवा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के आबकारी एवं कराधान अधिकारी के कार्यालय में, विहित रीति में, संदत्त करेगा और विवरणियों के साथ, ऐसी रकम के संदाय को दर्शित करने वाली ऐसे खजाने, बैंक या सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त अथवा जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी से प्राप्त रसीद देगा :

परन्तु ऐसी रकम का कोई संदाय, निर्धारण अधिकारी के पक्ष में स्थानीय अनुसूचित बैंक में संदेय क्रॉस चैक या बैंक ड्राफ्ट के सिवाए, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के कार्यालय में स्वीकृत नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जब व्यौहारी खजाना बैंक (ट्रेजरी बैंक) से भिन्न

अनुसूचित बैंक के माध्यम से संदाय करता है तो वह ऐसे बैंक से प्रमाण पत्र, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा कि बैंक ने व्यौहारी के निदेशों पर कर की रकम खजाना (ट्रेजरी) बैंक को विप्रेषित कर दी है और निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा प्रमाण पत्र पेश करने पर व्यौहारी द्वारा उस तारीख को, जिस दिन ऐसे बैंक द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, कर संदत्त किया गया समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित बैंक के माध्यम से संदाय की दशा में, जो खजाना बैंक (ट्रेजरी बैंक) से भिन्न अन्य स्थान पर स्थित है, व्यौहारी को पूर्ववर्ती परन्तुक में यथावर्णित सम्बद्ध बैंक से, उप-धारा (2) के अधीन विवरणियां दाखिल करने के लिए विहित देय तारीख के अवसान से कम से कम तीन दिन पूर्व उपाप्त करनी होगी और केवल इसी दशा में यह समझा जाएगा कि व्यौहारी ने देय तारीख को संदाय कर दिया है :

परन्तु यह और कि जहां क्रास चैक के माध्यम से संदाय किया जाता है, तो ऐसा क्रास चैक सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय में, उप-धारा (3) के अधीन विवरणी दाखिल करने के लिए विहित सम्यक् तारीख के अवसान से कम से कम दस पूर्ण दिन पूर्व, परिदत्त किया जाना चाहिए और व्यौहारी द्वारा उस तारीख को, जिस दिन क्रास चैक इसके बैंक में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् सरकारी लेखे में वास्तव में जमा किया जाता है और बैंक द्वारा व्यौहारी के पक्ष में आवश्यक रसीद जारी की जाती है, संदाय किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां क्रास चैक के माध्यम से संदाय किया जाता है और चैक अनादृत होता है, वहां व्यौहारी द्वारा संदाय नहीं किया हुआ समझा जाएगा और किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए दायी होगा जो इस अधिनियम या तद्धीन विरचित नियमों के अधीन संदाय न करने के लिए की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए “अनुसूचित बैंक” से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक अधिप्रेत है । 1934 का 2

(5) यदि किसी व्यौहारी को उस द्वारा दी गई किसी विवरणी में किसी लोप या अन्य गलती का पता चलता है तो वह, उस द्वारा आगामी विवरणी देने के लिए विहित तारीख से पूर्व, किसी भी समय, संशोधित विवरणी दे सकेगा और यदि संशोधित विवरणी में दर्शित देय कर की रकम, मूल विवरणी में दर्शाई गई रकम से अधिक है, तो उसके साथ, उप-धारा (4) में, अतिरिक्त रकम के संदाय को दर्शित करने वाली रसीद जो विहित की जा सकेगी, भी होगी ।

(6) यदि कोई व्यौहारी उप-धारा (3) के अधीन यथापेक्षित विहित की गई तारीख तक बिना किसी पर्याप्त हेतुक के विवरणी तैयार करने में असफल रहता है तो व्यौहारी शास्ति स्वरूप विवरणी को प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए पच्चीस रुपए प्रतिदिन के बराबर की राशि दस दिन तक के लिए संदत्त करने के लिए दायी होगा और उसके पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहने तक शास्ति पच्चास रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होगी किन्तु ऐसी शास्ति तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, परन्तु जहां कोई कर संदेय नहीं है, ऐसी शास्ति प्रत्येक विवरणी के लिए पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगी ।

(7) यदि व्यौहारी पर्याप्त हेतुक के बिना उप-धारा (4) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है तो आयुक्त या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, शास्ति के रूप में, ऐसी राशि, जो दस प्रतिशत से कम नहीं होगी, किन्तु जो, कर की रकम जिसके लिए उसका निर्धारण किया जाता है या जिसके निर्धारण के लिए दायी है, के अतिरिक्त कर की रकम जिसके लिए उसका निर्धारण किया जाता है या धारा 21 के अधीन निर्धारित किए जाने के लिए दायी है, से डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी, संदत्त करने का उसे निदेश दे सकेगा ।

(8) यदि किसी व्यौहारी ने अपने विक्रयों, क्रयों या माल के स्टॉक को छिपाने के विचार से मिथ्या या अशुद्ध लेखे बनाए रखे हैं अथवा अपने विक्रयों या क्रयों की किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी को कोई ऐसा लेखा, विवरणी अथवा सूचना दी गई है, जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या या अशुद्ध है, तो आयुक्त या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे व्यौहारी को, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उस कर के अतिरिक्त जिसके लिए उसका निर्धारण किया जाता है या निर्धारित किए जाने के लिए दायी है, शास्ति के रूप में, ऐसी रकम जो पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी किन्तु जो कर की रकम के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्धारण किया जाता है, संदत्त करने का निदेश दे सकेगा ।

संकर्म
ठेकेदारों
इत्यादि के
बिलों या
बीजकों से
कर की
कटौती ।

17. (1) धारा 20 में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी निम्नलिखित के लिए संदेय मूल्यवान प्रतिफल के कारण कोई संदाय या किसी दायित्व का उन्मोचन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति—

(क) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में सम्पत्ति अन्तरण के लिए, चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में, और

(ख) माल में सम्पत्ति के अन्तरण के लिए भारत सरकार या किसी राज्य सरकार को ऐसे माल के विक्रयों के मद्दे,

संकर्म ठेकेदार द्वारा या ऐसे माल के विक्रेता व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत किए बिलों या बीजकों में से व्यक्ति द्वारा यथा संदेय, चार प्रतिशत से अनधिक रकम, जो विहित की जाए, जिसका ऐसे विक्रयों पर संदेय कर का भाग या पूर्ण होना तात्पर्यित है, की कटौती करेगा :

परन्तु माल में किसी सम्पत्ति के अन्तरण की बाबत ऐसी किसी रकम की कोई कटौती नहीं की जाएगी जिसका आवर्त, धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन, व्यौहारी के सकल आवर्त से कटौती योग्य हो :

परन्तु संकर्म ठेकेदार या ऐसे माल का विक्रय करने वाले व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी बिल का कोई संदाय या उन्मोचन कटौतियों के बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि राज्य के राजस्व के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह ऐसे व्यक्तियों के नामों/पदों को अधिसूचित कर सकेगी जो ऐसी कटौती करने के लिए सक्षम व्यक्ति होंगे ।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कटौती ऐसी रीति में की जाएगी जैसी विहित की जाए और सरकारी खजाने में ऐसी कटौतियों का संदाय करना ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगा ।

(3) ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति या व्यौहारी को विहित रीति में कटौती प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसके बिल या बीजक में से ऐसी कटौती की गई है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या (2) या (3) के किसी या सभी उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो विहित प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित रूप में, आदेश द्वारा, यह निदेश करेगा कि ऐसी उप-धारा (1) के अधीन कटौती योग्य कर रकम के दुगने से अनधिक राशि शास्ति के रूप में संदत्त करेगा ।

(5) किसी व्यौहारी से देय कर की किसी रकम की वसूली के लिए धारा 25 और 27 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, काटे गए कर की किसी रकम की वसूली और/या अधिरोपित, किन्तु इस धारा के अधीन जमा न की गई, किसी शास्ति के लिए लागू होंगे ।

विवरणियों
के साथ
दाखिल की
जाने वाली
घोषणा और
प्रमाण-पत्र।

18. प्रत्येक व्यौहारी जो, -

- (i) अपनी सकल आवर्त से किसी कटौती; या
- (ii) अपने कराधेय आवर्त के किसी भाग को सरकार को की गई बिक्री; या
- (iii) कराधेय आवर्त के किसी भाग को इस अधिनियम के अधीन कर की रियायती दर के लिए दायी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यौहारी धारा 16 की उप-धारा (3) के अधीन दी जाने वाली विवरणी सहित, इस अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित घोषणा या प्रमाण पत्र निर्धारण प्राधिकारी को देगा ।

ब्याज का
संदाय ।

19. (1) यदि कोई व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन उससे देय कर की रकम, उप-धारा (2) में उल्लिखित परिमाण तक के सिवाए, संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह, कर की रकम के अतिरिक्त अन्तिम तारीख से ठीक पश्चात्पूर्वी तारीख से, जिसको या तो व्यौहारी द्वारा विवरणी दाखिल की जानी चाहिए थी अथवा इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त किया होता, उस द्वारा देय और संदेय कर की रकम पर प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रति मास की दर से जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी होगा ।

(2) यदि किसी व्यौहारी से देय कर या शास्ति की रकम उस द्वारा, मांग नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या यदि कोई अवधि विनिर्दिष्ट न की गई हो तो ऐसे नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो व्यौहारी, कर या शास्ति की रकम के अतिरिक्त ऐसी रकम पर, यथास्थिति, उस तारीख से जिसको नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि या तीस दिन की अवधि का अवसान होता है, के ठीक पश्चात्पूर्वी तारीख से एक मास की अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से और तत्पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी होगा:

परन्तु जहां किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा किसी कर या शास्ति की वसूली रोक दी जाती है, तो कर या शास्ति की रकम, रोक के आदेश को रद्द करने के पश्चात्, उस रकम पर, जो अंततः देय पाई जाती है, पूर्वोक्त दर

पर ब्याज सहित, वसूलीय होगी और ऐसा ब्याज उस तारीख से संदेय होगा जिस को कर या शास्ति प्रथमतः देय बनती है ।

(3) इस धारा के अधीन संदेय ब्याज की रकम—

- (i) संग्रहण और वसूली के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के अधीन कर समझी जाएगी;
- (ii) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी ।

20. (1) कोई भी व्यक्ति किसी माल के विक्रय या क्रय के बारे में, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर संदेय नहीं है, कर के रूप में किसी राशि का संग्रहण नहीं करेगा ।

कतिपय मामलों में कर संग्रहण के विरुद्ध प्रतिषेध ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है और किसी विक्रय या क्रय के बारे में कर संदत्त करने का दायी है, किसी अन्य व्यक्ति से कर के रूप में किसी माल के विक्रय या क्रय पर कोई राशि संगृहीत नहीं करेगा और कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा संदेय कर की रकम से अधिक कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यौहारी इन उपबन्धों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो वह, किसी भी कर के अतिरिक्त जिसके लिए वह दायी हो सकेगा, पांच सौ रुपये से अनधिक रकम की शास्ति या इस प्रकार संगृहीत रकम का दोगुणा, जो भी अधिकतर हो, संदत्त करने का दायी होगा ।

(4) यदि आयुक्त या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में या अन्यथा, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उप-धारा (3) के अधीन शास्ति संदत्त करने का दायी हो गया है, तो वह ऐसे व्यक्ति पर विहित प्ररूप में उससे यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि उस पर उप-धारा (3) में यथा उपबन्धित शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाए, नोटिस की तामील करेगा और तदुपरि जांच करेगा और ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझता है ।

21. (1) व्यौहारी द्वारा दाखिल की गई विवरणियों को सम्यक् रूप से कर का विहित रीति में अभिस्वीकृत किया जाएगा और जहां किसी भी वर्ष से सम्बन्धित समस्त विवरणियां दाखिल कर दी हैं और तात्त्विक विशिष्टियों में सही और पूर्ण निर्धारण ।

है तो व्यौहारी, उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन, उस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु जहां विवरणियां तात्त्विक विशिष्टियों में पूर्ण नहीं हैं तो व्यौहारी को नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर उन्हें पूर्ण करने का अवसर दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.--उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए विवरणी--

- (i) तभी सही समझी जाएगी यदि इसका संस्करण (वर्शन) व्यौहारी द्वारा अनुरक्षित लेखों के अनुरूप है और लेखा संस्करण (अकाउन्ट वर्शन) आगामी वर्ष के 31 अक्टूबर तक अभिलेख पर उपलब्ध किसी प्रतिकूल सूचना द्वारा अधिक्षिप्त नहीं किया जा सकता है; और
- (ii) तात्त्विक विशिष्टियों में, तभी पूर्ण समझी जाएगी यदि इसमें प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित समस्त सूचना, अंकगणितीय रूप में सही है और वैधानिक या विहित सूचियां, दस्तावेज तथा विवरणियों के अनुसार देय कर की पूर्ण रकम के संदाय का सबूत इनके साथ संलग्न है और व्यौहारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित है ।

(2) राज्य सरकार उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यौहारियों द्वारा दाखिल विवरणियों की संवीक्षा हेतु मामलों के चयन की रीति विहित कर सकेगी और निर्धारण प्राधिकारी, प्रत्येक चयनित मामले की बाबत, व्यौहारी पर विहित रीति में नोटिस की तामील करेगी जिसमें, उससे विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर या तो व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने या ऐसे किसी साक्ष्य, जिस पर ऐसा व्यौहारी उप-धारा (1) के अधीन उस द्वारा दाखिल विवरणियों के समर्थन में निर्भर रह सकेगा, पेश करने या पेश करवाने की अपेक्षा की जाएगी और व्यौहारी की सुनवाई करने तथा उस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य (सबूत) पर विचार करने के पश्चात्, उससे देय कर की रकम, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा ।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे तो यह किसी व्यौहारी की बाबत, जिसका सकल आवर्त एक वर्ष में ऐसी रकम से अधिक नहीं होता है, जिसे सरकार, किसी भी वर्ष के लिए स्वतः निर्धारण स्कीम, जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जा सकेगा, में विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु यह कि यदि कोई व्यौहारी, जिसका कराधेय आवर्त स्वतः निर्धारण स्कीम के अधीन निर्धारित किया गया है, कर का अपवंचन करते पाया जाता है, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे निर्धारित कर की रकम के अतिरिक्त, शास्ति के रूप में, राशि जो सौ प्रतिशत से कम नहीं होगी परन्तु जो अपवंचित और निर्धारित पाई गई कर की रकम के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी, संदत्त करने का निदेश देगा ।

(4) निर्धारण प्राधिकारी व्यौहारी को, जो उप-धारा (1) के अधीन न आता हो, विहित रीति में नोटिस की तामील करेगा जिसमें, उससे उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर या तो व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने या ऐसे किसी साक्ष्य, जिस पर ऐसा व्यौहारी अपनी विवरणियों के समर्थन में निर्भर रह सकेगा, को पेश करने या पेश करवाने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे साक्ष्य, जिसे व्यौहारी प्रस्तुत कर सकेगा, और ऐसा अन्य साक्ष्य, जिसकी निर्धारण प्राधिकारी विनिर्दिष्ट प्रश्नों (प्वाइन्ट्स) पर अपेक्षा करे, को सुनवाई करने के पश्चात्, व्यौहारी से देय रकम का निर्धारण करेगा ।

(5) यदि कोई व्यौहारी, जिसने किसी अवधि के बारे में विवरणियां दे दी हों, उप-धारा (2) या (4) के अधीन जारी किए गए नोटिस के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् पाँच वर्ष के भीतर, व्यौहारी से देय कर की रकम को अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार, निर्धारित करने के लिए अग्रसर होगा ।

(6) यदि कोई व्यौहारी, किसी अवधि के बारे में विहित तारीख तक विवरणियां नहीं देता है, तो निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात्, पाँच वर्ष के भीतर, व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अपनी सर्वोत्तम विवेक-बुद्धि के अनुसार, व्यौहारी से देय कर की रकम, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए अग्रसर होगा ।

(7) यदि किसी सूचना पर, जो उसके कब्जे में आई है, निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई व्यौहारी किसी अवधि के बारे में इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी है, किन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहा है, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् पाँच वर्ष के भीतर, व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी अवधि और पश्चात्वर्ती सभी अवधियों के बारे में व्यौहारी से देय कर की रकम, यदि कोई हो, अपनी सर्वोत्तम विवेक-बुद्धि के अनुसार, निर्धारित करने के लिए अग्रसर होगा और उन मामलों में जहां ऐसा व्यौहारी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

करने में जानबूझ कर असफल रहा है, वहां निर्धारण प्राधिकारी यह निदेश कर सकेगा कि व्यौहारी इस प्रकार निर्धारित रकम के अतिरिक्त ऐसी राशि जो पन्द्रह प्रतिशत से अन्यून होगी, किन्तु जो उस रकम के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी, शास्ति के रूप में संदत्त करेगा ।

(8) इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति या ब्याज की रकम व्यौहारी द्वारा ऐसी तारीख तक, जो उस प्रयोजन के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, संदत्त की जाएगी और इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख ऐसे नोटिस की तारीख से पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी और तीस दिन से अधिक नहीं होगी :

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिले के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे संदाय की तारीख को बढ़ा सकेगा किन्तु नव्वे दिन से अधिक नहीं, या प्रर्याप्त प्रतिभूति या बैंक गारन्टी के विरूद्ध तीन से अनधिक मासिक किश्तों द्वारा संदाय अनुज्ञात कर सकेगा ।

(9) यदि इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कर या उस की कोई किश्त, किसी व्यौहारी द्वारा, निर्धारण नोटिस या किश्तों में संदाय अनुज्ञात करने वाले आदेश में उस के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो आयुक्त या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे व्यौहारी को, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो उससे देय राशि से अधिक नहीं होगी ।

(10) इस धारा के अधीन किया गया कोई निर्धारण इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

आकस्मिक

22. (1) किसी आकस्मिक व्यौहारी का, जो इस अधिनियम के अधीन व्यौहारी का रजिस्ट्रीकृत है, धारा 21 के अधीन किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी की तरह निर्धारण किया जाएगा ।

(2) कोई आकस्मिक व्यौहारी जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है विक्रय या क्रय को संव्यवहार पूर्ण होने पर, जिसके लिए वह कर का संदाय करने का दायी है, तत्काल ऐसे संव्यवहार के स्थान के संदर्भ में अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को, समीपस्थ चैक पोस्ट अथवा बैरिअर के प्रभारी अधिकारी को, विक्रय या क्रय की कीमत की रकम और तदुपरि संदेय कर की रिपोर्ट देगा तथा ऐसे निर्धारण प्राधिकारी या चैक-पोस्ट अथवा बैरिअर के ऐसे प्रभारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति

में, जैसी ऐसा प्राधिकारी या प्रभारी निदेश दे, कर की रकम जमा करेगा :

परन्तु यदि आकस्मिक व्यौहारी, उस माल के बारे में, जिसे ऐसा व्यौहारी विक्रय करने या क़य करने, का आशय रखता है, अग्रिम में कर स्वेच्छा से संदत्त करने की वांछा करता है, तो वह कर निर्धारण प्राधिकारी या समीपस्थ चैकपोस्ट या बैरिअर के प्रभारी अधिकारी को ऐसे माल के मूल्य का दस प्रतिशत बढ़ा करके कर की रकम संदत्त कर सकेगा ।

(3) जहां आकस्मिक व्यौहारी उप-धारा (2) में यथा अपेक्षित रिपोर्ट करने में असफल रहता है, वहां अधिकारिता रखने वाला निर्धारण प्राधिकारी या समीपस्थ चैक-पोस्ट या बैरिअर का प्रभारी अधिकारी एवं कराधान अधिकारी, ऐसे आकस्मिक व्यौहारी से, विक्रय अथवा क़य की कीमत तथा देय कर की रिपोर्ट करने की अपेक्षा कर सकेगा, ऐसा न होने पर ऐसा निर्धारण प्राधिकारी या चैक पोस्ट या बैरिअर का ऐसा प्रभारी देय कर की रकम का, अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार निर्धारण कर सकेगा और आकस्मिक व्यौहारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा वह निदेश दे, कर की रकम संदत्त करने का निदेश दे सकेगा ।

(4) जहां उप-धारा (2) या (3) के अधीन आकस्मिक व्यौहारी, निर्धारण प्राधिकारी या चैक-पोस्ट अथवा बैरिअर के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा यथानिर्देशित कर संदत्त करने में असफल रहता है, वहां ऐसे आकस्मिक व्यौहारी से सम्बंधित माल तब तक निरूद्ध रखा जाएगा जब तक कि कर संदत्त नहीं किया जाता है या कर के संदाय के लिए पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दी जाती है।

कर का पुनर्निर्धारण । **23. (1)** यदि निश्चित सूचना के परिणाम स्वरूप जो उसके कब्जे में आई है, निर्धारण प्राधिकारी को यह पता चलता है कि व्यौहारी के कारबार के आवर्त को किसी वर्ष में अवनिर्धारित किया गया है या वह निर्धारण से छूट गया है, तो निर्धारण प्राधिकारी धारा 21 के अधीन निर्धारण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, उस आवर्त पर, जो अवनिर्धारित किया गया है या निर्धारण से छूट गया है, संदेय कर को पुनः निर्धारित करने के लिए अग्रसर होगा :

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन शास्ति और ब्याज अधिरोपित करने के लिए, कार्रवाई भी कर सकेगा :

परन्तु यह और कि पुनर्निर्धारण अथवा शास्ति या ब्याज के अधिरोपण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यौहारी को विहित रीति सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है ।

(2) कोई निर्धारण प्राधिकारी या ऐसा कोई प्राधिकारी, जो विहित किया जाए, उस द्वारा पारित किए गये किसी आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर, किसी भी समय, और ऐसी शर्तों के अध्वधीन जो विहित की जाए, अभिलेख से प्रकट किसी लिपिकीय या गणितीय भूल को सुधार सकेगा ।

कतिपय
मामलों में
निर्धारण या
पुनर्निर्धारण
को पूरा
करने के
लिए
परिसीमा
काल का
लागू न
होना ।

24. (1) धारा 21 या धारा 23 में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में परिसीमाकाल से सम्बन्धित उपबन्धों के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय द्वारा या अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप या उसको प्रभावी करने के लिए, निर्धारण या पुनर्निर्धारण किसी भी समय किया जा सकेगा ।

(2) जहां किसी अवधि के लिए किसी व्यौहारी से सम्बन्धित निर्धारण कार्यवाहियां किसी न्यायालय के या अन्य प्राधिकारी के आदेशों के अधीन रूकी रही हैं, वहां ऐसी अवधि, इस अधिनियम की धारा 21 या धारा 23 या इसके किसी अन्य उपबन्ध में विनिर्दिष्ट निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए, परिसीमा काल की संगणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी ।

कर और
शास्ति का
भू-राजस्व
की बकाया
के रूप में
वसूलीय
होना ।

25. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर और शास्ति की रकम या संदेय ब्याज, जो नियत तारीख के पश्चात् असंदत्त रहता है, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

कर, शास्ति
और ब्याज
का संपत्ति
पर प्रथम
भार होना।

26. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यौहारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर और शास्ति की रकम जिसके अन्तर्गत ब्याज, यदि कोई हो, भी है, व्यौहारी या ऐसे अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम भार होगी ।

वसूली का
विशेष ढंग।

27. (1) धारा 25 या किसी विधि या संविदा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, आयुक्त या धारा 3 के अधीन आयुक्त की सहायता करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षक से भिन्न, नियुक्त कोई अधिकारी, किसी भी समय या समय-समय पर लिखित नोटिस द्वारा (जिस की एक प्रति व्यौहारी को, नोटिस जारी करने वाले अधिकारी को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी जाएगी) —

(क) कोई व्यक्ति जिससे व्यौहारी को कोई रकम देय है या देय हो जाती है, जो इस अधिनियम के अधीन देय किसी रकम के लिए मांग के नोटिस का अनुपालन करने में असफल रहा है ;

(ख) कोई व्यक्ति जो ऐसे व्यौहारी के लिए या के मद्दे कोई धन धारण करता है या तत्पश्चात् धारण करेगा,

इस उप-धारा के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट रीति में, उतना धन जो इस अधिनियम के अधीन व्यौहारी से कर के बकाया, ब्याज और शास्ति के बारे में देय रकम संदत्त करने के लिए पर्याप्त है ।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा व्यौहारी को देय रकम या किसी व्यौहारी के लिए या मद्दे धारित धन ऐसे दावे, यदि कोई हो, को हिसाब में लेते हुए संगणित किया जाएगा जो ऐसे व्यौहारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को संदाय के लिए देय हो गया हो और विधिपूर्ण अस्तित्व में रहा हो ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय, या समय-समय पर, ऐसे नोटिस को संशोधित या प्रतिसंहृत कर सकेगा अथवा नोटिस के अनुसरण में कोई संदाय करने के लिए समय को बढ़ा सकेगा ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में कोई संदाय करने वाले किसी व्यक्ति को व्यौहारी के प्राधिकार के अधीन संदाय करने वाला समझा जाएगा और ऐसे संदाय के लिए खजाने की रसीद, रसीद में विनिर्दिष्ट रकम के परिमाण तक ऐसे व्यक्ति के दायित्व का अच्छा और पर्याप्त उन्मोचन होगा ।

(4) उप-धारा (1) के अधीन जारी नोटिस के उस पर तामील के पश्चात् व्यौहारी के किसी दायित्व का उन्मोचन दायित्व के परिमाण तक या व्यौहारी का कर, ब्याज और शास्ति, जो भी कम हो, के लिए दायित्व के परिमाण तक राज्य सरकार के प्रति दायी होगा ।

(5) जहां कोई व्यक्ति जिस पर उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील की गई है, उस अधिकारी, जिसने नोटिस जारी किया है, के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई भाग व्यौहारी को देय नहीं था अथवा यह कि उसके पास व्यौहारी के लिए या उसके मद्दे कोई धन उस समय नहीं था जब ऐसे व्यक्ति पर नोटिस की तामील की गई थी, तब इस धारा की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति से यथास्थिति, ऐसा कोई धन या उसका भाग, सरकारी खजाने में संदत्त करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(6) कोई धन राशि जो किसी व्यक्ति से उप-धारा (1) के अधीन संदत्त करने के लिए अपेक्षित है या जिसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से उप-धारा (4)

के अधीन सरकार के प्रति दायी है, यदि यह असंदत्त रहती है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी ।

(7) इस धारा के उपबन्ध, व्यौहारी से देय कर, ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, के बकाया की वसूली के लिए की गई किसी कार्रवाई के प्रतिकूल नहीं होंगे ।

प्रतिदाय ।

28. (1) निर्धारण प्राधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यौहारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त कर, ब्याज या शास्ति की किसी रकम का, विहित रीति में, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को, यदि इस प्रकार संदत्त कर, शास्ति या ब्याज की रकम, इस अधिनियम के अधीन उससे देय रकम से अधिक-है, या तो प्रतिदाय बाउचर द्वारा या व्यौहारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के विकल्प पर, किसी अन्य अवधि के बारे में इस प्रकार संदत्त रकम का उससे देय रकम से समायोजन द्वारा, प्रतिदाय करेगा :

परन्तु धारा 12 की उप-धारा (4) के अधीन किसी भी आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम के प्रतिदाय के लिए, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष के अवसान तक आवेदन नहीं किया जाएगा और प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और तत्पश्चात् दावा प्रत्येक पश्चात्पूर्ति वर्ष के अन्त में किया जाएगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिदाय तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक की प्रतिदाय हेतु दावा, उस तारीख से जिस को ऐसा दावा प्रोद्भूत होता है, तीन वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन जारी ऐसे प्रतिदाय की मंजूरी वाले आदेश के आधार पर कोई रकम जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को प्रतिदत्त की जानी अपेक्षित है, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उस को प्रतिदत्त नहीं की जाती है तो व्यौहारी उक्त एक मास के अवसान की तारीख के ठीक पश्चात्पूर्ति तारीख से ऐसी रकम पर प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से और तत्पश्चात् प्रतिदाय किए जाने तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) उप-धारा (1) या (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण प्राधिकारी, ऐसे समायोजन की तारीख को व्यौहारी से देय किसी रकम की वसूली के लिए पहले प्रतिदत्त की जाने वाली रकम को समायोजित करेगा, और तत्पश्चात् बाकी, यदि कोई हो, प्रतिदत्त करेगा ।

(4) यदि पूर्वोक्त नब्बे दिन की अवधि के भीतर प्रतिदाय अनुज्ञात किए जाने में विलम्ब निर्धारण प्राधिकारी के नियन्त्रण से परे के कारणों से है या व्यौहारी को, चाहे पूर्णतः या भागतः अरोप्य है, तो ऐसी देरी की अवधि उस अवधि से अपवर्जित की जाएगी जिसके लिए ब्याज संदेय है ।

(5) यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई अवधि उप-धारा (4) के अधीन ब्याज की संगणना के प्रयोजनार्थ अपवर्जित की जानी है, तो इसे आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे, निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) जहां प्रतिदाय अनुज्ञात करने वाला आदेश किसी अपील या अतिरिक्त कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य कार्यवाहियां लम्बित हैं और निर्धारण प्राधिकारी की यह राय है कि प्रतिदाय से वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वहां निर्धारण प्राधिकारी प्रतिदाय को रोक सकेगा और मामला आयुक्त को निर्दिष्ट करेगा जिसका आदेश अन्तिम होगा ।

(7) वह अवधि जिसके दौरान उप-धारा (6) के अधीन प्रतिदाय, विधारित रहता है, इस धारा के अधीन ब्याज की संगणना के प्रयोजनार्थ अपवर्जित की जाएगी ।

अध्याय-5

लेखे, सर्वेक्षण और निरीक्षण

29. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी या अन्य व्यौहारी जिस पर धारा 16 लेखे । की उप-धारा (3) के अधीन विवरणियां देने के लिए नोटिस की तामील की गई है उस द्वारा क्रय किए गए, विनिर्मित किए गए और विक्रय किए गए माल के मूल्य का या स्टॉक में उसके द्वारा धारित माल का सही और अद्यतन लेखा रखेगा और इस उप-धारा में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए व्यौहारी द्वारा बनाई रखी लेखा बहियों के अतिरिक्त वह ऐसे रजिस्टर और लेखे ऐसे प्ररूप में रखेगा जो विहित किए जाएं ।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यौहारी अपने कारबार के स्थान पर सभी लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज रखेगा ।

(3) जहां उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट व्यौहारी ने कारबार के मुख्य स्थान के अतिरिक्त राज्य में कारबार के शाखा कार्यालय स्थापित किए हैं, तो ऐसी प्रत्येक

शाखा की बाबत, उप-धारा (5) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी प्रत्येक शाखा पर भी उसके द्वारा सुसंगत लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज बनाए जाएंगे और रखे जाएंगे ।

(4) यदि निर्धारण प्राधिकारी की यह राय है कि किसी व्यौहारी या व्यौहारियों के वर्ग द्वारा अनुरक्षित लेखे पर्याप्त रूप में उसे विवरणियों के सत्यापन या उसके आधार पर उचित रूप में कर निर्धारण करने में समर्थ नहीं बनाते हैं तो वह आदेश द्वारा, ऐसे व्यौहारी या व्यौहारियों के वर्ग से ऐसे लेखे ऐसी रीति, जो विहित की जा सकेगी, में अनुरक्षित रखने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(5) राज्य सरकार लोक हित में अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों के किसी भी वर्ग को इस धारा के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

कर बीजक,
परचून
बीजक
इत्यादि ।

30. (1) कर बीजक में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी इस धारा में विनिर्दिष्ट है और इसे एक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा दूसरे व्यौहारी (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या न हो) को जारी किया जाएगा जिसके आधार पर क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का दावा करने का हकदार होगा ।

(2) किसी अन्य व्यौहारी, (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या न हो) को कराधेय विक्रय करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ऐसे क्रेता व्यौहारी को विक्रय करते समय उप-धारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट कर बीजक जारी करेगा और उसकी एक प्रति रखेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा कर बीजक जारी नहीं किया जाएगा, जब विक्रय—

(क) इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन उप-धारणात्मक कर या धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन एक मुश्त राशि संदत्त करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा है ;

(ख) इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल का है ;

(ग) अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में है ; या

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय है ।

(4) प्रत्येक कराधेय विक्रय के लिए केवल एक बीजक जारी किया जाएगा ।

(5) उप-धारा (1) के अधीन जारी कर बीजक में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

- (क) शीर्ष पर या अन्य प्रमुख स्थान पर, बड़े अक्षरों में शब्द 'कर बीजक' ;
- (ख) विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की संख्या ;
- (ग) क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की संख्या ;
- (घ) क्रय संख्या और तारीख जिस को कर बीजक जारी किया गया है ;
- (ङ.) विक्रीत माल का विवरण, मात्रा, घनत्व और मूल्य तथा अन्तर्बलित कर की पृथकतः दिखाई गई रकम ;
- (च) विक्रेता व्यौहारी या उसके सेवक, प्रबन्धक या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकर्ता के हस्ताक्षर ; और
- (छ) मुद्रक का नाम और पता ।

(6) जहां कर बीजक उप-धारा (2) के अधीन जारी करना अपेक्षित है के सिवाए प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, जो दो सौ रुपये से अधिक के किसी माल का किसी एक संव्यवहार में, किसी व्यक्ति को, विक्रय करता है, तो वह क्रेता को उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट एक फुटकर बीजक जारी करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा ।

(7) फुटकर बीजक में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

- (क) शीर्ष पर या प्रमुख स्थान पर बड़े अक्षरों में शब्द 'फुटकर बीजक' या 'केश मेमों' या 'बिल' ;
- (ख) विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की संख्या ;
- (ग) यदि विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य या भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में है तो, क्रेता व्यौहारी/ विदेशी क्रेता का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि कोई है और कानूनी प्ररूप, का प्रकार, यदि कोई हो, जिसके विरुद्ध विक्रय किया गया है ;
- (घ) क्रम संख्या और तारीख जिस पर फुटकर बीजक जारी किया गया है ;

- (ड.) विक्रीत माल का विवरण, मात्रा, घनत्व और मूल्य, अन्तर्वर्तित कर की रकम, यदि कोई है ;
- (च) विक्रेता व्यौहारी या उसके सेवक, प्रबन्धक या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकर्ता के हस्ताक्षर ; और
- (छ) मुद्रक का नाम और पता ।

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी निर्धारण प्राधिकारी को, मुद्रित करवाए गए और उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष के दौरान उपयोग के लिए रखे गए कर बीजकों और फुटकर बीजकों की कुल संख्या को लिखित में सूचित करेगा ।

(9) कर बीजक की तीन प्रतियां जारी की जाएंगी और यथास्थिति, दूसरी प्रति सहित मूल प्रति क्रेता या माल का परिदान लेने वाले व्यक्ति को दी जाएगी और तीसरी प्रति विक्रेता व्यौहारी द्वारा रखी जाएगी ।

(10) फुटकर बीजक की दो प्रतियां जारी की जाएंगी और मूल प्रति क्रेता को दी जाएगी तथा दूसरी प्रति विक्रेता व्यौहारी द्वारा रखी जाएगी ।

(11) जहां कर बीजक या फुटकर बीजक जारी करने अपेक्षित नहीं है, तो प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ऐसा अन्य बीजक जैसा विहित किया जाए, जारी करेगा ।

(12) प्रत्येक व्यौहारी कर बीजकों और फुटकर बीजकों सहित लेखा बहियों वर्ष के अन्त, जिससे वे सम्बन्धित है, के पश्चात् पांच वर्ष के अवसान तक या ऐसी अन्य अवधि के लिए जैसी विहित की जाए या जब तक निर्धारण अपनी अन्तिमता प्राप्त नहीं कर लेता है, जो भी बाद में हो, अनुरक्षित रखेगा ।

(13) जहां कोई व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही में पक्षकार है तो वह ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की विषयवस्तु से सम्बन्धित प्रत्येक अभिलेख और लेखे तब तक रखे रखेगा जब तक इसका अन्तिम निपटान नहीं हो जाता है ।

(14) प्रत्येक व्यौहारी, जो अभिलेख को इलैक्ट्रॉनिकली अनुरक्षित रखता है, ऐसे समस्त अभिलेख का दिन प्रतिदिन का प्रिंट-आउट भी अनुरक्षित रखेगा और वह उन्हें, यथास्थिति, उप-धारा (12) या उप-धारा (13) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रखेगा ।

(15) राज्य सरकार, लोक हित में, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों के किसी वर्ग को उप-धारा (2) से (14) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों से छूट दे सकती है ।

(16) जहां कोई व्यौहारी उप-धारा (2) से (14) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो आयुक्त या धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी ।

31. (1) जहां माल के किसी विक्रय के लिए कर बीजक जारी किया गया है परन्तु यदि ऐसे विक्रय की तारीख से छः मास के भीतर, ऐसे कर बीजक में दर्शित कर के रूप में प्रभारित रकम संदेय कर से अधिक पायी जाती है तो विक्रय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी तुरन्त क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को ऐसी विशिष्टियां, जैसी विहित की जाएं, से अन्तर्विष्ट जमा पत्र जारी करेगा ।

जमा पत्र
और नामें
नोट जारी
करना ।

(2) जहां किसी भी माल के विक्रय के लिए कर बीजक जारी किया गया है और विक्रय के बारे में संदेय कर, ऐसे बीजक में दर्शित कर के रूप में प्रभारित रकम से अधिक हो जाता है तो विक्रय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी तुरन्त क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को ऐसी विशिष्टियां, जैसी विहित की जाएं, से अन्तर्विष्ट नामें नोट जारी करेगा ।

(3) कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी जो जमा पत्र या नामें नोट जारी करता है या प्राप्त करता है अपनी विवरणी को उस अवधि के लिए, जिसमें जमा पत्र या नामें नोट, यथास्थिति, प्राप्त किया है या जारी किया है, संशोधित करेगा और ऐसी विवरणी देने से पूर्व किसी देय कर को संदत्त करेगा ।

32. (1) आयुक्त या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने को नियुक्त कोई व्यक्ति, जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यौहारी से उसके कारबार से सम्बन्धित कोई बही, दस्तावेज या लेखा अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उसका निरीक्षण, परीक्षण कर सकेगा और उसकी प्रति बना सकेगा और ऐसे व्यौहारी से उसके कारबार से सम्बन्धित ऐसी पूछताछ कर सकेगा जैसी आवश्यक हो :

बहियों,
दस्तावेजों
और लेखों
का
प्रस्तुतीकरण
और
निरीक्षण ।

परन्तु उस वर्ष, जिस में निर्धारण किया जाता है, से पूर्विक पाँच वर्ष से अधिक अवधि की बहियाँ, दस्तावेज और लेखे इस प्रकार अपेक्षित नहीं होंगे ।

▲ (2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी —

- (क) अपने कारबार का दिन प्रतिदिन का लेखा रखेगा ;
- (ख) अपनी लेखा बहियों की एक सूची रखेगा, उसे अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के साथ संप्रदर्शित करेगा और ऐसी सूची की एक प्रति निर्धारण प्राधिकारी को देगा ;

- (ग) यदि अपेक्षित हो अपने कारबार की लेखा बहियों को विहित रीति में अधिप्रमाणन के लिए निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा ; और
- (घ) अपनी लेखा-बहियों को अपने कारबार के स्थान पर तब तक रखेगा, जब तक कि वे निरीक्षण के लिए किसी पद्धारी द्वारा, किसी शासकीय अभिकरण द्वारा या लेखा-परीक्षकों द्वारा या किन्हीं अन्य कारणों से जिन्हें निर्धारण प्राधिकारी द्वारा समाधान प्रद समझा जाए, वहां से हटाई नहीं जाती है ।

(3) यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि कोई व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य देयों के दायित्व के अपवंचन का प्रयत्न कर रहा है और उसके दायित्व के किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ आवश्यक कोई बात किसी बही, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज में पाई जा सकती हो तो वह ऐसे बही, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज को, जो आवश्यक हो, अभिगृहीत कर सकेगा । बही, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज को अभिगृहीत करने वाला अधिकारी उसके लिए तत्काल रसीद देगा और उसे —

- (क) ऐसी बही, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज के मामले में, जो अभिग्रहण के समय उपयोग में लाया जा रहा था, अभिग्रहण की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर ; और
- (ख) किसी अन्य मामले में, अभिग्रहण की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ;

इसे परीक्षण के पश्चात् या उसमें से ऐसी प्रतिलिपि या उद्धरण लेने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाए, व्यौहारी को या उस व्यक्ति को लौटा देगा, जिसकी अभिरक्षा से वह अभिगृहीत किया गया था ; परन्तु यदि जब व्यौहारी या पूर्वोक्त व्यक्ति उसे लौटाई गई बही, लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज के लिए लिखित रसीद देता है और ऐसा अधिकारी बही, लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज लौटाने से पूर्व उस पर एक या एक से अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकेगा और अपनी मोहर भी लगाएगा :

परन्तु जहाँ इस अधिनियम के अधीन बहियों का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी या ऐसे अन्य किसी अधिकारी के निदेशों का पालन करने में व्यौहारी असफल रहता है, तो ऐसा अधिकारी ऐसी बहियों को आगे ऐसी और अवधि के लिए, जैसी वह ठीक समझे, आयुक्त की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, रख सकेगा :

परन्तु यह और कि ऐसा अधिकारी व्यौहारी को, वे कारण जिनके लिए बहियां इस उप-धारा के अधीन विहित अवधि से परे रखे रखना अपेक्षित हो, सूचित करेगा।

(4) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी व्यौहारी के किसी कार्यालय, दुकान, गोदाम, जलयान, यान या कारबार के किसी अन्य स्थान में अथवा किसी भवन, निवासगृह अथवा स्थान में, जहां ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए कारण है कि व्यौहारी अपने कारबार से सम्बन्धित कोई बहियां, लेखे, रजिस्टर, दस्तावेज या माल रखता है या तत्समय रख रहा है, प्रवेश और तलाशी ले सकेगा :

परन्तु किसी निवास गृह में कोई भी प्रवेश या तलाशी-----

- (i) सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व ;
- (ii) आबकारी एवं कराधान अधिकारी से नीचे की पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा ; और
- (iii) जिला दंडाधिकारी जिसकी अधिकारिता में ऐसा गृह स्थित है, कि मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना, नहीं की जाएगी ।

(5) उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत किसी बॉक्स या पात्र को, जिसमें व्यौहारी की कोई बहियां, लेखे, रजिस्टर या अन्य सुसंगत दस्तावेज अन्तर्विष्ट हों; खोलने और उनकी तलाशी लेने तथा उक्त लेखों, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों और पाए गए माल या नकद की प्रतियां या उद्धरण लेने, जो उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, की शक्ति भी है ।

(6) उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त किसी अधिकारी को, किसी माल का, जो व्यौहारी के किसी कार्यालय, दुकान, गोदाम, जलयान, यान या कारबार के किसी अन्य स्थान अथवा किसी भवन या स्थान पर पाया जाता है, परन्तु व्यौहारी ने जिसका अपनी बहियों, लेखों, रजिस्ट्रों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों में लेखा-जोखा नहीं दिया है, अभिग्रहण करने की शक्ति होगी ।

33. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते सर्वेक्षण की हुए भी धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन आयुक्त की सहायता करने के लिए शक्ति । नियुक्त कोई सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई आबकारी एवं कराधान निरीक्षक, इस अधिनियम की धारा 14 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए कर के संदाय के दायित्व के आरम्भ के

अभिनिरुचय सम्बन्धी सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए—

- (क) उसको समनुदेशित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी स्थान, या
 (ख) किसी व्यौहारी के अधिभोग वाले किसी स्थान, जिसके बारे में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है,

में प्रवेश कर सकेगा जिसमें कारबार करने वाला व्यौहारी अपनी कोई लेखा बहियाँ या अन्य दस्तावेज अथवा माल के विक्रय या क्रय से सम्बन्धित अपनी नकदी का कोई भाग या अपने कारबार से सम्बन्धित माल का स्टॉक रखता है और किसी व्यौहारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति, जो उस समय और स्थान पर किसी भी रीति में ऐसा व्यापार चलाए जाने में हाजिर होता है या सहायता करता है, से अपेक्षा कर सकेगा—

- (i) कि वह ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने में उसको आवश्यक सुविधाएं दे, जैसी वह अपेक्षा करे, और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों ;
- (ii) कि वह नकद और माल का स्टॉक जो वहां पाया जाए की जांच पड़ताल या सत्यापन के लिए उसे आवश्यक सुविधाएं दे; और
- (iii) कि वह ऐसे कथन सहित ऐसी सूचना दे जिसकी वह, किसी विषय के बारे, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या उनसे सुसंगत हो, अपेक्षा करे

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए किसी निवास गृह में कोई प्रवेश—

- (i) सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व ;
- (ii) आबकारी एवं कराधान अधिकारी से नीचे की पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा ; और
- (iii) जिला दंडाधिकारी की मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना, जिसके अधिकारिता में ऐसा गृह स्थित है, नहीं किया जाएगा ।

चैक पोस्टों
 या बैरिअरों
 की स्थापना
 और
 अभिवहन में
 माल का
 निरीक्षण ।

34. (1) यदि, इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन को निवारित करने या उसकी जांच पड़ताल करने की दृष्टि से, राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, वह अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे स्थान या स्थानों पर, जो अधिसूचित किए जाएं, चैक पोस्ट की स्थापना या किसी बैरिअर के परिनिर्माण अथवा दोनों के लिए निदेश दे सकेगी ।

(2) माल गाड़ी या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, यथास्थिति, माल गाड़ी अभिलेख, यात्रा पत्र, या लॉग बुक और कारबार के प्रयोजन के लिए ऐसे माल के बारे में जो, यथास्थिति, माल गाड़ी या जलयान में ले जाया जा रहा है, विक्रय बिल या ऐसी विशिष्टियों से युक्त परिदान नोट, जैसा विहित किया

जाए, अपने साथ रखेगा और उसे चैक पोस्ट या बैरिअर के प्रभारी अधिकारी अथवा किसी स्थान पर, यान या जलयान की जांच करने वाले, किसी अन्य अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(3) जब उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, जो प्रत्येक चैक पोस्ट या बैरिअर अथवा किसी अन्य स्थान पर, मालगाड़ी या जलयान का चालक या कोई अन्य भारसाधक व्यक्ति, यथास्थिति, यान या जलयान को रोकेंगे और उसे उतनी देर तक, जितनी युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो खड़ा रखेगा और चैक पोस्ट या बैरिअर के भार साधक अधिकारी या पूर्वोक्त अधिकारी को यान या जलयान में रखी अर्न्तवस्तु का पैकेज या पैकेजों को खोल कर, यदि आवश्यक हो, परीक्षण करना अनुज्ञात करेगा और वहन किये गए माल से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का निरीक्षण करेगा जो चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति के कब्जे में हों, वह ऐसी अन्य सूचना भी देगा जैसी उपर्युक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और यदि आवश्यक समझा जाए तो ऐसा अधिकारी मालगाड़ी या जलयान और माल के या यान के या जलयान के चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति की तलाशी भी ले सकेगा ।

(4) राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाली या राज्य की सीमाओं से बाहर निकलने वाली मालगाड़ी या जलयान या स्वामी या भारसाधक व्यक्ति चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी के समक्ष तीन प्रतियों में एक घोषणा (इलैक्ट्रॉनिकली तैयार की गई अन्यथा) भी देगा, जिसमें, यथास्थिति, ऐसे यान या जलयान में ले जाए जा रहे माल की ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विहित की जाएं, और उक्त अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित और उसे लौटाई गयी उक्त घोषणा की प्रति उसे या इस धारा के अधीन जांच पड़ताल के समय उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां राज्य से बाहर किसी स्थान को जाने वाली माल गाड़ी या जलयान राज्य में से होकर गुजरता है, वहां ऐसी मालगाड़ी या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, राज्य में अपने प्रवेश की, चैक पोस्ट या बैरिअर के प्रभारी अधिकारी को, विहित प्ररूप में, एक घोषणा दो प्रतियों में देगा और उससे सम्यक् रूप से सत्यापित एक प्रति अभिप्राप्त करेगा । यथास्थिति, मालगाड़ी या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति राज्य से बाहर अपने निकासी के स्थल पर उक्त प्रति, चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी को बहत्तर घंटों के भीतर परिदत्त करेगा, ऐसा न करने पर वह प्रवेश के चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शास्ति, जो माल के मूल्य के पच्चीस

प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, किन्तु जो माल के मूल्य से पन्द्रह प्रतिशत कम नहीं होगी, संदत्त करने का दायी होगा :

परन्तु यह और कि कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है ।

(5) किसी रेल सीमान्त या डाकघर से भिन्न, माल परिवहन के प्रत्येक स्टेशन, बस-अड्डे या माल चढ़ाने या उतारने के किसी अन्य स्टेशन या स्थान पर, जब आयुक्त द्वारा या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा जब ऐसी अपेक्षा की जाए तब मालगाड़ी का चालक या स्वामी या परिवहन कम्पनी अथवा माल बुकिंग अधिकरण का कर्मचारी, उस द्वारा विहित रीति में रखी गई और वहन, परिवहन किए गए, चढ़ाए गए, उतारे गए, पारेषित या परिवहन के लिए प्राप्त माल से सम्बद्ध परिवहन की रसीदे, और अन्य सभी दस्तावेज तथा लेखा बहियां (जो उस द्वारा विहित रीति में रखी गई हैं) परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा । आयुक्त या इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को ऐसी परिवहन रसीदे या अन्य दस्तावेज अथवा लेखा बहियां, वहन किए गए, परिवहन किए गए, चढ़ाए गए, उतारे गए, या पारेषित या परिवहन के लिए प्राप्त माल के बारे में परीक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसे माल के किसी पैकेज या किन्हीं पैकेजों को तोड़ने की शक्ति प्राप्त होगी ।

(6) यदि चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी या उप-धारा (2) में वर्णित अन्य अधिकारी के पास यह सन्देह करने के कारण हों कि परिवहन के अधीन माल कारबार के लिए है और, यथास्थिति, उप-धारा (2) या उप-धारा (4) में यथावर्णित समुचित और वास्तविक दस्तावेजों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, या माल वहन करने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है, तो वह कारण अभिलिखित करते हुए और उक्त व्यक्ति को सुनने के पश्चात् परन्तु बैरिअर के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्वधीन ऐसी अवधि के लिए जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, माल को उतारने और निरुद्ध रखने का आदेश कर सकेगा और कर की रकम सुनिश्चित करने के लिए, माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा माल के स्वामी की ओर से यान या जलयान के चालक अथवा अन्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा, ऐसी रकम के लिए जो माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो किन्तु जो माल के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी, विहित प्ररूप और रीति में, प्रतिभूति सहित या रहित, उसकी तुष्टि की प्रतिभूति देने या बन्ध पत्र निष्पादित करने पर ही उसे वहन करना अनुज्ञात करेगा :

परन्तु जहां किसी माल को निरुद्ध किया जाता है, वहां माल निरुद्ध करने वाले अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, जिला के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान

आयुक्त या जिला या बैरिअर के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को तुरन्त या किसी भी दशा में माल निरुद्ध करने के चौबीस घण्टे के भीतर, रिपोर्ट की जाएगी, जब कभी माल को चौबीस घण्टे से अधिक की किसी अवधि के लिए निरुद्ध करना अपेक्षित हो तो इसके पश्चात् कथित की अनुज्ञा मांगी जाएगी और यदि पश्चात् कथित से कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो पहला यह धारणा कर सकेगा कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ।

(7) माल निरुद्ध करने वाला अधिकारी माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा चालक या माल गाड़ी अथवा जलयान के अन्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन को, यदि कोई हो, अभिलिखित करेगा और उससे, यथास्थिति, उप-धारा (2) या उप-धारा (4) में यथा निर्दिष्ट समुचित और वास्तविक दस्तावेज विनिर्दिष्ट तारीख को अपने समक्ष, अपने कार्यालय में प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, जिस तारीख को अधिकारी सम्बद्ध अभिलेखों सहित कार्यवाही को ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा विषय में आवश्यक जांच संचालित करने के लिए उस निमित्त प्राधिकृत किया जाए प्रस्तुत करेगा, उक्त अधिकारी जांच संचालित करने से पूर्व, माल के स्वामी पर एक नोटिस तामील करेगा और उसे सुनवाई का अवसर देगा और यदि, जांच के पश्चात् ऐसे अधिकारी का यह निष्कर्ष हो कि इस अधिनियम के अधीन देय कर का अपवंचन करने का प्रयत्न किया गया है तो वह, आदेश द्वारा, माल के स्वामी पर माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक किन्तु जो माल के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी, शास्ति अधिरोपित करेगा और उस दशा में जब उसका निष्कर्ष अन्यथा हो माल को छोड़ देने का आदेश देगा ।

(8) यदि माल का स्वामी या उसका प्रतिनिधि या माल गाड़ी या जलयान का चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति, माल या मालगाड़ी या जलयान को निरुद्ध करने की तारीख से दस दिन के भीतर उप-धारा (6) द्वारा यथा अपेक्षित प्रतिभूति नहीं देता है या बन्धपत्र निष्पादित नहीं करता है, तो उस उप-धारा में निर्दिष्ट अधिकारी माल को और आगे के लिए निरुद्ध करने का आदेश कर सकेगा और शास्ति अधिरोपित करने के आदेश की तारीख से बीस दिन के भीतर उप-धारा (7) के अधीन अधिरोपित शास्ति संदत्त न करने की दशा में निरुद्ध माल उस अधिकारी जिसने शास्ति अधिरोपित की है, विहित रीति में सार्वजनिक नीलामी द्वारा, शास्ति की वसूली के लिए, विक्रय किए जाने के लिए दायी होगा । यदि निरुद्ध माल नाशवान प्रकृति का है या शीघ्रता और प्रकृत्या क्षयशील है अथवा जब ऐसा सम्भाव्य है कि उसे अभिरक्षा में रखने का खर्च उसके मूल्य से अधिक होगा, तब, यथास्थिति, चैक पोस्ट या बैरिअर का भार साधक अधिकारी या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी, ऐसे माल को तुरन्त बेच देगा या उसका अन्यथा व्ययन करेगा । विक्रय आगम को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा और माल

का स्वामी, माल को निरुद्ध करने और व्ययन करने में उपगत खर्चें और अन्य आनुषंगिक प्रभारों में कटौती करने के पश्चात् केवल आगम की अतिशेष रकम का हकदार होगा ।

(9) माल-निरुद्ध करने वाला अधिकारी, माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा मालगाड़ी या जलयान के चालक या भारसाधक व्यक्ति को इस प्रकार निरुद्ध किए गए माल का विवरण और परिमाण विनिर्दिष्ट करते हुए रसीद जारी करेगा और ऐसे व्यक्ति से अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करेगा या यदि ऐसा व्यक्ति अभिस्वीकृति देने से इन्कार करता है, तो दो साक्षियों की उपस्थिति में इन्कार करने का तथ्य अभिलिखित करेगा ।

(10) यदि इसी बीच उप-धारा (6) के अधीन माल निरुद्ध करने या उप-धारा (7) या उप-धारा (8) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का आदेश अपील में या अन्य कार्यवाहियों में अपास्त या उपान्तरित कर दिया जाता है, तो, यथास्थिति, माल निरुद्ध करने वाला या शास्ति अधिरोपित करने वाला अधिकारी, यथास्थिति, ऐसी अपील में या अन्य कार्यवाहियों में किए गए आदेशों को प्रभावशील बनाने के लिए परिणामिक आदेश भी पारित करेगा ।

(11) कोई व्यौहारी या कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत किसी व्यौहारी की ओर से कार्य करने वाला माल वाहक या परिवहन कम्पनी या बुकिंग अधिकरण का अधिकर्ता है, किसी जलयान, स्टेशन, विमान पतन या किसी अन्य स्थान से, चाहे समरूप प्रकृति का हो या अन्यथा, निजी सामान या निजी उपयोग के लिए माल से भिन्न, माल के किसी प्रेषण जिनका विक्रय या क्रय इस अधिनियम के अधीन कराधेय है, सिवाए ऐसी शर्तों के अनुसार जो यह सुनिश्चित करने के लिए विहित की जाएं कि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर का कोई अपवंचन नहीं किया है, परिदान नहीं लेगा या परिवहन नहीं करेगा :

परन्तु कोई भी स्थान, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जाएगा, जो रेल सीमान्त या डाकघर है ।

1988 का
केन्द्रीय
अधिनियम
संख्यांक

59

स्पष्टीकरण-I.— इस धारा में पद “माल गाड़ी” का वही अर्थ होगा जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खण्ड (14) में इसका है ।

स्पष्टीकरण-II.— उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए निजी उपयोग के प्रयोजनों के लिए माल का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा कि यह कारबार के प्रयोजनार्थ है ।

स्पष्टीकरण-III.— उप-धारा (7) के प्रयोजनों के लिए स्वामी के प्रतिनिधि या माल गाड़ी या जलयान के चालक अथवा अन्य भारसाधक व्यक्ति पर नोटिस की तामील माल के स्वामी पर विधिमान्य तामील समझी जाएगी ।

35. (1) धारा 34 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में कारबार का स्थान रखने वाला प्रत्येक माल वाहक, परिवहन कम्पनी और बुकिंग अधिकरण के अधिकर्ता और व्यौहारी की ओर से जो माल का परिवहन या निकासी या अग्रेषण कर रहा हो, को उस क्षेत्र के निर्धारित प्राधिकारी से जिस में इसके कारबार का स्थान है, ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, और उक्त प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में उसी रीति में जैसी विहित की जाए, प्रतिभूति देने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

रजिस्ट्रीकरण
और माल
के वाहक
और
परिवहन
कम्पनियों
के
अधिकर्ता
द्वारा
विवरणियां
प्रस्तुत
करना ।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकरण, इस द्वारा परिवहन किए गए, निकासित या अग्रेषित माल की विवरणी, ऐसी तारीख तक और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(3) प्रस्तुत की गई विवरणियों की शुद्धता और धारा 34 के उपबन्धों की अपेक्षाओं के अनुपालन का सत्यापन करने की दृष्टि से, ऐसे अधिकरण के कब्जे में लेखा बहियों, दस्तावेजों और अन्य अभिलेख को मंगाने और परीक्षण करने की निर्धारण प्राधिकारी को शक्ति होगी ।

36. कोई निर्धारित, व्यौहारी या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का हकदार है या जिससे उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है, सिवाय जब उससे स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा की जाए, इस निमित्त लिखित रूप में उस द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, विहित रीति में, उपस्थित हो सकेगा ।

प्राधिकृत
अधिकर्ता
के माध्यम
से उपस्थित
होने के
लिए
निर्धारित
आदि को
अनुज्ञात
करना ।

37. आयुक्त या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए किसी व्यक्ति से, जिसके अन्तर्गत कोई बैंककारी कम्पनी, डाकघर या उनका कोई अधिकारी भी है, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या उनसे सुसंगत कोई जानकारी या कथन देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

बैंककारी
कम्पनियों
आदि से
जानकारी
मंगाने की
शक्ति ।

38. ऐसे निर्बन्धों और शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी किसी भी शक्ति को किसी अधिकारी को, जो राज्य मुख्यालय में तैनात अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

शक्तियों का
प्रत्यायोजन ।

कारबार का
अन्तरण ।

39. जहां रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के कारबार का स्वामित्व पूर्णतः या भागतः अन्तरित कर दिया जाता है और अन्तरिती ऐसे कारबार को उसके पुराने नाम से या किसी अन्य नाम से चलाता है, तो अन्तरिती, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए (ऐसे व्यौहारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन पूर्व उन्मोचित दायित्वों के सिवाए) इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत हुआ और सदैव रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाएगा मानों ऐसे व्यौहारी का रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र अन्तरिती को प्रारम्भ में ही दिया गया था, और अन्तरिती विहित प्राधिकारी को आवेदन करने पर, तदनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को संशोधित करवाने का हकदार होगा ।

कतिपय
मामलों में
स्टॉक पर
कर का
दायित्व ।

40. इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन उस का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाना चाहिए, तो व्यौहारी, सिवाए जब उसने अपना कारबार किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर दिया है, और धारा 2 के खण्ड (घ) के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 के उपबन्धों के अध्याधीन, रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् हिमाचल प्रदेश राज्य में उस द्वारा क्रय किए गए माल पर, और प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के समय शेष अविक्रीत पर ऐसे माल के विक्रय के लिए उद्ग्राह्य दर पर, कर संदत्त करने का दायी होगा ।

विभक्त
हिन्दु
कुटुम्ब,
विघटित
फर्म आदि
का कर के
संदाय के
लिए
दायित्व।

41. (1) जहां कोई व्यौहारी अविभक्त हिन्दु कुटुम्ब फर्म या अन्य व्यक्तियों का संगम है, और ऐसा कुटुम्ब, फर्म या संगम, यथास्थिति, विभक्त, विघटित या विच्छिन्न हो जाता है,—

(क) इस अधिनियम के अधीन ऐसे कुटुम्ब, फर्म या व्यक्तियों के संगम द्वारा ऐसे विभाजन, विघटन या विच्छेद की तारीख तक की अवधि के लिए संदेय कर ऐसे निर्धारित किया जा सकेगा मानो ऐसा कोई विभाजन, विघटन या विच्छेद हुआ ही नहीं था और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे विभाजन, विघटन या विच्छेद के समय किसी अविभक्त हिन्दु कुटुम्ब फर्म या व्यक्तियों के संगम का सदस्य या भागीदार था, ऐसे विभाजन विघटन या विच्छेद के होते हुए भी ऐसे कुटुम्ब, फर्म या व्यक्तियों के संगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय कर जिसके अन्तर्गत ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, भी है, पृथकतः या संयुक्ततः संदाय करने के लिए दायी होगा, चाहे निर्धारण ऐसे विभाजन, विघटन या विच्छेद से पहले या बाद में किया जाता है ।

(2) जहां, किसी अविभक्त हिन्दु कुटुम्ब के विभाजन या किसी फर्म के विघटन या किसी व्यक्तियों के संगम के विच्छेद से भिन्न, किसी दशा में, किसी

व्यौहारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र इस अधिनियम के अधीन रद्द कर दिया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के रद्द किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए ऐसे व्यौहारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ऐसे व्यौहारी पर इस प्रकार निर्धारित किया जा सकेगा मानो कि ऐसा रद्दकरण हुआ ही नहीं था और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

42. जहां इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के दायी किसी व्यौहारी की मृत्यु हो जाती है, तब वहां —

विधिक वारिसों का कर संदत्त करने का दायित्व ।

(क) यदि व्यौहारी द्वारा चलाया जा रहा कारबार उस की मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है, तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन व्यौहारी से देय कर (जिसके अन्तर्गत कोई शास्ति भी है) संदत्त करने का दायी होगा, चाहे ऐसा कर (जिसके अन्तर्गत कोई शास्ति भी है) उस की मृत्यु से पूर्व निर्धारित किया गया है, किन्तु असंदत्त रहा है या उसकी मृत्यु के पश्चात् निर्धारित किया जाता है ; और

(ख) यदि व्यौहारी द्वारा चलाया जा रहा कारबार उस की मृत्यु के पश्चात् बन्द कर दिया जाता है, तो उसका विधिक प्रतिनिधि मृतक की सम्पदा में से उस परिमाण तक जिस परिमाण तक सम्पदा प्रभार पूरा करने में समर्थ है इस अधिनियम के अधीन व्यौहारी से देय कर (जिसके अन्तर्गत कोई शास्ति भी है) संदत्त करने का दायी होगा, चाहे ऐसा कर (जिसके अन्तर्गत कोई शास्ति भी है) उसकी मृत्यु से पूर्व निर्धारित किया गया है, या उसकी मृत्यु के पश्चात् निर्धारित किया जाता है ;

और इस अधिनियम के उपबन्ध, जहां तक हो सके, ऐसे विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति को लागू होंगे मानो वह स्वयं व्यौहारी था ।

43. आयुक्त या धारा 3 के अधीन उस की सहायता करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया कोई निर्धारण और पारित आदेश किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, और धारा 45, 46 और 48 में उपबंधित के सिवाए, ऐसे किसी निर्धारण या आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए कोई भी अपील या आवेदन नहीं होगा ।

कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन ।

अध्याय-6

अपील, पुनरीक्षण और परिशुद्धि

अधिकरण ।

44. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना करेगी जो अध्यक्ष और उतने सदस्यों से मिल कर बनेगा, जितने राज्य सरकार समय-समय पर अधिकरण को, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन, प्रदत्त कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए ठीक समझे ।

(2) अध्यक्ष और सदस्य ऐसी अर्हता रखेंगे, जैसी विहित की जाएं, और उनके पद के निबन्धन ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं ।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि साधारणतया चार वर्ष की होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा, ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसी वह उचित समझे, किन्तु किसी भी दशा में 62 वर्ष की आयु से परे नहीं ।

(4) अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं ।

(5) अधिकरण के समक्ष लाए गए समस्त मामले पीठ द्वारा बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे और किसी मामले में, जहां अध्यक्ष और सदस्यों का किसी विषय बिन्दु या विषय बिन्दुओं पर उनकी राय में मतभेद है, तो वे उस विषय बिन्दु या विषय बिन्दुओं, जिन पर उनमें मतभेद है, का कथन करेगा और मामले को निम्नलिखित से गठित पीठ द्वारा सुनवाई के लिए निर्दिष्ट करेगा,—

- (i) अध्यक्ष और सदस्य जिन्होंने इसकी पहले सुनवाई की है, ;
और
- (ii) कोई अतिरिक्त सहयोजित सदस्य जो सेवा कर रहा है
और उप-धारा (2) के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्ति
के लिए अर्हित है,

और ऐसा मामला पीठ के सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा :

परन्तु अतिरिक्त सदस्य मामले के निपटान पर पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा ।

(6) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधधीन जैसी विहित की जाएं, अधिकरण खर्चा अधिनिर्णीत कर सकेगा और ऐसे खर्च की रकम, जो देय तारीख के पश्चात् असंदत्त रह जाती है, उसका संदाय करने के लिए आदेशित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी ।

(7) अधिकरण की मोहर और इसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी राज्य सरकार विहित करे ।

(8) राज्य सरकार, अधिकरण की सहायता करने के लिए ऐसे अधिकारी और पदधारी नियुक्त कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन, इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित हों :

परन्तु अधिकरण के समक्ष राज्य के मामलों का प्रतिनिधित्व ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त (विधि) की पंक्ति से नीचे का न हो ।

45. (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित अपील । प्रत्येक मूल आदेश से, अपील निम्नलिखित को होगी :—

(क) यदि आदेश किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा या चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो द्वारा किया जाता है, तो उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को ;

(ख) यदि आदेश उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा किया जाता है, तो आयुक्त या राज्य मुख्यालय में तैनात अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त को ; और

(ग) यदि आदेश आयुक्त या अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त या आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है तो अधिकरण को ।

(2) उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त या अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अथवा किसी अधिकारी, जिस पर आयुक्त की

शक्तियां प्रदत्त की गई है, द्वारा अपील में पारित आदेश, आगे अधिकरण को अपीलीय होगा ।

(3) अधिकरण का प्रत्येक आदेश आयुक्त या आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अधिकारी या अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त का आदेश अथवा उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी या चैक पोस्ट या बैरिअर का भारसाधक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, का आदेश, यदि इसे अपील या पुनरीक्षण में चुनौती नहीं दी गई थी, अन्तिम होगा ।

(4) कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि यह उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर या ऐसी दीर्घतर-अवधि के भीतर, जिसे अपील प्राधिकारी कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अनुज्ञात करे, दायर नहीं की गई है ।

(5) किसी भी अपील प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक ऐसी अपील के साथ, यथास्थिति, कर (संदेय ब्याज सहित) या शास्ति, यदि कोई अधिरोपित की गई हो, या दोनों के संदाय का समाधानप्रद सबूत संलग्न न हो :

परन्तु यदि ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि व्यौहारी निर्धारित कर (संदेय ब्याज सहित) या शास्ति, यदि कोई अधिरोपित की गई हो या दोनों, संदत्त करने में असमर्थ है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, बिना कर के (संदेय ब्याज सहित) के या शास्ति के अथवा दोनों पूर्णतया संदत्त किए जा चुके हों या ऐसे कर (संदेय ब्याज सहित) या शास्ति या दोनों के आंशिक संदाय के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(6) प्रक्रिया के ऐसे नियमों के अध्यक्ष जो विहित किए जाएं, अपील प्राधिकारी, अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह न्याय संगत और उचित समझे ।

पुनरीक्षण ।

46. (1) आयुक्त, स्वप्रेरणा से, किन्हीं कार्यवाहियों, जो उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है या उस के द्वारा निपटाई गई है, का अभिलेख ऐसी कार्यवाहियों या उसमें किए गए आदेश की वैधता और औचित्य

के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, मंगवा सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन शक्तियां उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर ही प्रयोक्तव्य होंगी जिसको कि ऐसा आदेश संसूचित किया गया था ।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उप-धारा (1) के अधीन किसी भी अधिकारी को आयुक्त की शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी जिनका प्रयोग ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, और ऐसे क्षेत्रों की बाबत किया जाएगा, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसा अधिकारी उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए आयुक्त समझा जाएगा ।

(3) अधिकरण, आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर उप-धारा (1) के अधीन आयुक्त के आदेश के विरुद्ध उसको किए गए आवेदन पर ऐसे किसी मामले का अभिलेख ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के लिए मंगवा सकेगा और उनका परीक्षण कर सकेगा और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा न्यायसंगत और उचित समझता है ।

(4) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

47. (1) अधिकरण या आयुक्त या कोई अधिकारी, जिस पर राज्य सरकार द्वारा धारा 46 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए आयुक्त की शक्तियां प्रदत्त की गई है, उस को किए गए आवेदन पर उस द्वारा पारित किसी आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर किसी भी समय या स्वप्रेरणा से अभिलेख से प्रकट किसी भी भूल की परिशुद्धि कर सकेगा और ऐसे आदेश द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा उसके ध्यान में लाई गई ऐसी किसी भूल की ऐसी ही अवधि के भीतर परिशुद्धि करेगा :

भूलों की परिशुद्धि ।

परन्तु आयुक्त इस उप-धारा के अधीन कोई आवेदन उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है, कि आवेदक पर्याप्त कारणों द्वारा समय पर आवेदन करने से निवारित था :

परन्तु यह और कि कर को बढ़ाने वाली या प्रतिदाय की रकम को घटाने वाली ऐसी कोई परिशुद्धि तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि आयुक्त ने ऐसा

करने के अपने आशय का नोटिस लिखित में ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया है और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात नहीं किया हो ।

(2) जहां ऐसी कोई परिशुद्धि कर या शास्ति की रकम को बढ़ाने या घटाने का प्रभाव रखती हो वहां आयुक्त, विहित रीति में, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति से देय रकम की वसूली का आदेश या उसको देय रकम के प्रतिदाय का आदेश करेगा ।

उच्च न्यायालय में उप-धारा (3) के अधीन अधिकरण द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति पुनरीक्षण । ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने के नब्बे दिन के भीतर, ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को आवेदन कर सकेगा, यदि इसमें विधि के गलत विनिश्चय से उद्भूत होने वाला विधि का कोई प्रश्न या विधि के किसी प्रश्न का विनिश्चय करने में असफलता अन्तर्विलित हो ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन में आदेश में अन्तर्विलित विधि के प्रश्न का प्रमिततः कथन किया जाएगा और यह उच्च न्यायालय को विधि के प्रश्न को बनाने के लिए सक्षम करेगा ।

(3) जहाँ इस धारा के अधीन कोई आवेदन लम्बित है, तो उच्च न्यायालय या इस निमित्त आवेदन पर संदेय कर, शास्ति या ब्याज की किसी विवादित रकम की वसूली पर या पुनरीक्षण के लिए ईप्सित आदेश के अधीन देय किसी रकम के प्रतिदाय पर रोक लगा सकेगा :

परन्तु ऐसी विवादित रकम की वसूली पर रोक का कोई भी आदेश तीस दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि आवेदक सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी के समाधान के लिए पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे देता है ।

(4) उप-धारा (1) के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन या उप-धारा (3) के अधीन रोक के लिए आवेदन कम से कम दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा सुना और विनिश्चित किया जाएगा ।

(5) इस धारा के अधीन कोई आदेश, जिसका किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

49. अधिकरण या आयुक्त या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन शपथ आदि नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी वाद का पर साक्ष्य विचारण करते समय, निम्नलिखित विषयों के बारे में, वही शक्तियां प्राप्त लेने की प्राधिकारियों 1908 का 5 होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित की शक्ति हैं, अर्थात :—

- (क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना ;
- (ख) दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करना और उनको परिबद्ध या निरुद्ध करना ;
- (ग) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना ;
- (घ) शपथ-पत्रों द्वारा तथ्यों के सबूत की अपेक्षा करना या स्वीकार करना ;
- (ङ.) ऐसी अन्य शक्तियां जैसी विहित की जाएं ;

और इस अधिनियम के अधीन, अधिकरण या आयुक्त या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उस की सहायता करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराओं 193 और 228 1860 का के अर्थ के अन्तर्गत और धारा 199 के प्रयोजनों के लिए “न्यायिक कार्यवाही” 45 समझी जाएगी ।

अध्याय-7

अपराध और शास्तियाँ

50. (1) कोई व्यक्ति जो —

अपराध
और

- (क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के शास्तियाँ ।
उल्लंघन में जानबूझ कर कार्य करेगा ; या
- (ख) कोई प्रमाण पत्र, घोषणा, बिल, केश मेमो, वाउचर, परिदान नोट, माल रसीद या अन्य दस्तावेज देगा जिस के बारे में वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है; या
- (ग) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के नाते, विक्रय के लिए किसी माल के निर्माण में उस द्वारा प्रयोग के लिए किसी वर्ग के माल का क्रय करते हुए जब मिथ्या रूप से यह व्यपदिष्ट करेगा कि ऐसे वर्ग माल उस

- के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत आने वाले हैं ; या
- (घ) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी न होते हुए, हिमाचल प्रदेश में माल का क्रय करते हुए मिथ्या रूप से व्यपदिष्ट करेगा कि वह एक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी है ; या
- (ङ.) अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए किसी माल का क्रय के करने पश्चात् युक्तियुक्त हेतुक के बिना ऐसे किसी प्रयोजन के लिए माल का प्रयोग करने में असफल रहेगा ; या
- (च) सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदाय पर जारी किया गया कोई प्ररूप उसके कब्जे में है जो उस द्वारा या उसके मालिक द्वारा अथवा उसके अधिकर्ता द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभिप्राप्त नहीं किया गया है ; या
- (छ) बहियों, दस्तावेजों और लेखे का निरीक्षण या परीक्षण को निवारित करेगा या जानबूझ कर धारा 32 में उल्लिखित ऐसी बहियों, दस्तावेज और लेखे पेश करने में असफल रहेगा ; या
- (ज) धारा 34 में विनिर्दिष्ट किसी अभिलेख या दस्तावेज को अपने साथ ले जाने में असफल रहेगा ; या
- (झ) यथास्थिति, धारा 34 या धारा 35 में विनिर्दिष्ट किसी दस्तावेज में कोई कथन या घोषणा करता है, जिस कथन या घोषणा के बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह मिथ्या है; या
- (ञ) इस अधिनियम के अधीन किसी माल के विक्रय या क्रय में बारे में संदेय किसी कर के किसी कपटपूर्ण अपवंचन या अपवंचन के प्रयत्न अथवा अपवंचन के दुष्प्रेरण से किसी भी प्रकार से जानबूझ कर संबद्ध है ; या
- (ट) यदि वह माल यान या जलयान का चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति अथवा माल का स्वामी है, चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो आबकारी एवं कराधान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, मांग किए जाने पर अपना नाम और पता या माल यान के स्वामी या प्रेषक या माल के प्रेषक का नाम और पता देने से इन्कार करता है अथवा इन व्यक्तियों में किसी का कोई नाम और पता देता है जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास का कारण है कि यह मिथ्या है ; या
- (ठ) इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने में किसी व्यक्ति की सहायता करता है या दुष्प्रेरण करेगा :

तो वह, किसी कर या ब्याज अथवा शास्ति, जो उससे देय हो, की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारण कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा या जुमनि से अथवा दोनों से, और जहां जारी रहने वाला अपराध है, दैनिक जुमनि से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, पच्चास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

(2) जो कोई, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबन्धों अथवा तद्धीन किए या दिए गए किसी आदेश या निदेश का उल्लंघन करेगा या अनुपालन करने में अफल रहेगा, यदि ऐसे उल्लंघन या असफलता के लिए की इस धारा की उप-धारा (1) या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कोई अन्य दण्ड उपबन्धित नहीं किया गया है, शास्ति के अधिरोपण जो दो हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, और जहां ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, पच्चास रुपए से अनधिक की दैनिक शास्ति से, जिस अवधि के दौरान उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, दण्डनीय होगा ।

(3) चैक पोस्ट या बैरिअर का कोई भारसाधक अधिकारी या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, या ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उप-धारा (2) में उल्लिखित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु चैक पोस्ट या बैरिअर का भारसाधक अधिकारी केवल ऐसी चैक पोस्टों या बैरिअरों पर ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

51. (1) आयुक्त या अन्य अधिकारी, जो सहायक आबकारी एवं अपराधों का शमन। कराधान आयुक्त से नीचे की पंक्ति का न हो, या जिला का प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी धारा 50 या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कार्यवाहियां संस्थित करने से या तो पूर्व या पश्चात्, ऐसे अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति से, अपराध के शमन स्वरूप कर की रकम के दो गुणा के बराबर धन राशि स्वीकार कर सकेगा, जो विक्रयों या क्रयों के आवर्त पर, जिससे कि अपराध सम्बन्धित हों, संदेय होती, जो भी अधिकतर हो ।

(2) ऐसी रकम के संदाय पर, जो उप-धारा (1) के अधीन अवधारित की जाए, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध की बाबत कोई और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी और कोई कार्यवाहियां, यदि पहले की गई है, उपशमनीत (समाप्त) हो जाएंगी ।

अपराधों

52. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों का संज्ञान। के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान सरकार या ऐसे अधिकारी, जिसे राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए, की पूर्व मंजूरी के सिवाय न करेगा और प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

(2) आयुक्त, शर्त के अधीन, यदि कोई हो, जो विहित की जा सकेगी, या तो सामान्यतः या विशिष्टतः मामले या मामलों के वर्ग की बाबत किसी भी अधिकारी या उसके अधीनस्थ व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन सभी या किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) इस अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय सभी अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होंगे ।

अध्याय-8

प्रकीर्ण

व्यतिक्रम
कम्पनियों
के
निदेशकों
का कर
आदि
संदल
करने के
लिए दायी
होना

53. किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी पर निर्धारित कोई कर या अधिरोपित शास्ति कम्पनी के परिसमापन के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से वसूल नहीं की जा सकती है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो सुसंगत अवधि के दौरान किसी भी समय, जिसके लिए कर देय है या जिसका बारे में व्यतिक्रम किया गया था जिसके लिए शास्ति अधिरोपित की गई है, ऐसी कम्पनी का निदेशक था, ऐसे कर या शास्ति के संदाय के लिए सयुक्ततः और पृथक्तः दायी होगा जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि असंदाय या अवसूली कम्पनी के कार्यकलापों के सम्बन्ध में उसकी ओर से कर्तव्य की किसी उपेक्षा, अपकरण या भंग के कारण की गई नहीं मानी जा सकती है ।

कतिपय
सम्पत्ति का
व्ययन ।

54. इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत किसी सम्पत्ति का, जिस के लिए कोई व्यक्ति दावा नहीं करता है, पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 25, 26 और 27 के उपबन्धों के अनुसार व्ययन किया जाएगा मानों ऐसी सम्पत्ति अभिगृहीत करने वाला अधिकारी या प्राधिकारी पुलिस अधिकारी हो :

1861 का
केन्द्रीय
अधिनियम
संख्यांक 5

परन्तु यदि ऐसे उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञात अवधि के दौरान, कोई व्यक्ति सम्पत्ति का दावा करता है, तो इसे तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा

जब तक उसके बारे में इस अधिनियम के अधीन देय कर या शास्ति या दोनों ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त नहीं कर दिए जाते हैं ।

55. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक परित्राण की गई या की जाने को आशयित किसी बात के लिए कोई भी बाद, अभियोजन (इन्डेमनिटी) या अन्य विधिक कार्यवाही हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।

56. (1) इस अधिनियम के अनुसार किए गए किसी कथन में, दी गई विवरणियों विवरणी या प्रस्तुत किए गए लेखे अथवा दस्तावेज में या किसी दंडिक न्यायालय आदि का के समक्ष कार्यवाहियों से भिन्न इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य के किसी अभिलेख में, अन्तर्विष्ट सभी विशिष्टियां गोपनीय होना । उप-धारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाय, गोपनीय मानी जाएंगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय, यथा पूर्वोक्त के सिवाय, ऐसे किसी कथन, विवरणी, लेखा, दस्तावेज या अभिलेख अथवा उसके किसी भाग को अपने समक्ष पेश करने की या उसके बारे में उसके समक्ष साक्ष्य देने की अपेक्षा राज्य सरकार के किसी अधिकारी से करने का हकदार नहीं होगा ।

*

(2) यदि, उप-धारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाय, हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्टियों में से किसी को प्रकट करता है, तो वह कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(3) इस धारा की कोई भी बात —

- (क) इस अधिनियम या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी कथन, विवरणी, लेखे, दस्तावेज, साक्ष्य, शपथ-पत्र या अभिसाक्ष्य की बाबत ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के; या
- (ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम के प्रशासन से न्यस्त किसी व्यक्ति को ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के; या
- (ग) जब ऐसा प्रकटीकरण किसी नोटिस या समन की तामील अथवा किसी मांग की वसूली के लिए जब इस अधिनियम के अधीन किसी प्रक्रिया के विधि पूर्ण नियोजन द्वारा हुआ हो, तो ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के ; या

- (घ) किसी न्यायालय को किसी वाद में, जिसमें राज्य सरकार का आबकारी एवं कराधान विभाग या उक्त विभाग का कोई अधिकारी पक्षकार है और जो इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले किसी विषय से सम्बन्धित है की ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के ; या
- (ङ.) इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित कर की रसीदों या प्रतिदाय की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किसी अधिकारी को ऐसी किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के ; या
- (च) ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के, जहां ऐसी विशिष्टियां सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग के किसी पदधारी के आचरण की किसी जांच में सुसंगत है, लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन आयुक्त द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को अथवा संविधान के अधीन स्थापित लोक सेवा आयोग को जब ऐसी जांच से उत्पन्न किसी विषय के सम्बन्ध में अपने कृत्यों का प्रयोग किया जा रहा हो; या
- (छ) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी को दी गई विवरणी में या इस अधिनियम के अधीन पारित किसी निर्धारण आदेश में अवधारित दर्शाए गए वार्षिक सकल आवर्त के, जो उस सरकार को इस द्वारा अधिरोपित किसी कर या शुल्क के उद्ग्रहण या वसूली के प्रयोजन के लिए समर्थ बनाने को आवश्यक हो ; या
- (ज) ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के, जो किसी आयकर व्यवसायी या किसी अन्य व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करता है, के विरुद्ध आचरण के आरोप की किसी जांच में, सुसंगत है ; या
- (झ) हिमाचल प्रदेश सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक को ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के, जो किसी वस्तु पर कर के भार की गणना करने में या व्यापार, वस्तु या व्यौहारी का कोई सांख्यिकीय सर्वेक्षण करने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो ; और
- (ञ) कम्प्यूटरीकरण द्वारा डाटा तैयार करने तैयार की जाने के प्रयोजन के लिए ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के ; प्रकटीकरण को लागू नहीं होगी :

1850 का
37

परन्तु खण्ड (क), (च) और (छ) में उल्लिखित सूचना सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के भारसाधक आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा तभी प्रकट किए जाने के

लिए अनुज्ञात की जा सकेगी, जब इस निमित्त किए गए आवेदन की छानबीन के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, उसका समाधान हो जाता है कि प्रकटीकरण इस उप-धारा के अधीन अनुज्ञेय है ।

1860 का
45

57. धारा 3 और धारा 44 के अधीन नियुक्त सभी व्यक्ति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

नियुक्त
व्यक्तियों
का लोक
सेवक होना।

58. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

अन्तरराज्यिक
व्यापार आदि
की दशा में
उपबन्ध ।

(क) इस अधिनियम के अधीन माल के विक्रय और क्रय पर कोई कर अधिरोपित नहीं किया जाएगा—

- (i) जहां ऐसा विक्रय या क्रय हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर होता है ; या
- (ii) जहां ऐसा विक्रय या क्रय भारत में राज्य क्षेत्र के भीतर माल के आयात के अनुक्रम में या उसके बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में किया जाता है ; और

(ख) किसी माल के विक्रय या क्रय पर वहां कर अधिरोपित नहीं किया जाएगा जहां ऐसा विक्रय या क्रय अन्तर-राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम के सिवाय तक, जहां संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित करें, होता है ।

59. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी, जब कभी भी अपेक्षित हो, किसी पुलिस अधिकारी या सरकार के अन्य अधिकारी की सहायता ले सकेगा और सहायता के लिए किए गए ऐसे अनुरोध पर, पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी विधि के अनुसार आवश्यक सहायता देगा।

पुलिस और
अन्य
अधिकारियों
से सहायता
प्राप्त करने
की
शक्ति।

60. (1) धारा 21 की उप-धारा (4) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वर्ष में किसी भी समय, प्रत्येक निर्धारण प्राधिकारी धारा 16 की उप-धारा (3) और (4) के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए और कर, शास्ति और संदेय ब्याज की दरों, आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के दावे

विवरणियों
की
संवीक्षा।

संगणना की शुद्धता की जांच करने के लिए किसी भी कर अवधि के दौरान दाखिल की गई विवरणियों की संवीक्षा करेगा ।

(2) यदि उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार की गई ऐसी संवीक्षा के परिणाम स्वरूप किसी भूल (गलती) का पता चलता है, तो निर्धारण प्राधिकारी व्यौहारी को, विहित प्ररूप में कर, शास्ति और ब्याज की अतिरिक्त रकम का संदाय करने के नोटिस की तामील करेगा ।

(3) निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारियों की भी पहचान करेगा जिन्होंने किसी भी कर अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं की है या कर संदत्त नहीं किया है और वह धारा 16 के अधीन कार्रवाई प्रारम्भ करने के अतिरिक्त ऐसे व्यौहारी को तत्काल ऐसी विवरणी दाखिल करने और देय कर, शास्ति और ब्याज की रकम संदत्त करने के लिए निदेश देते हुए नोटिस की तामील करेगा ।

लेखा
परीक्षा और
निरीक्षण ।

61. (1) आयुक्त या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, प्रस्तुत विवरणियों की शुद्धता, विभिन्न दावों और आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की अनुज्ञेयता को अभिनिश्चित करने के लिए, किसी विहित मानदण्ड या समसंभाविक (रेन्डम) आधार पर, किसी भी प्रस्तुत विवरणी, अभिलेख या व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत वैधानिक प्ररूप का ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, निरीक्षण करेगा या लेखा परीक्षा करेगा या करवाएगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित निरीक्षण या लेखा परीक्षा या ऐसे प्राधिकारी के कार्यालय में या व्यौहारी के कारबार परिसरों में, या भांडागार में या कार्यालय में किया जाएगा ।

(3) विहित प्राधिकारी, कार्यवाहियों के अनुक्रम में प्रस्तुत किए गए समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्,—

- (क) धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन स्वतः निर्धारण की पुष्टि करेगा ; या
- (ख) धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन स्वतः निर्धारण की पुष्टि नहीं करेगा और व्यौहारी से देय कर की रकम की संगणना करेगा ; या
- (ग) किसी व्यौहारी से देय कर की रकम की संगणना करेगा, यदि ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया है :

परन्तु यह कि यदि विहित प्राधिकारी, निरीक्षण, लेखा परीक्षा या अन्वेषण के अनुक्रम में उस द्वारा संगृहीत किसी साक्ष्य पर निर्भर करने की प्रस्तावना करता है तो व्यौहारी को, नोटिस द्वारा, नब्बे दिन से अनधिक अवधि के भीतर अपने स्व:निर्धारण को ठीक करने का अवसर दिया जाएगा और यदि वह अपने स्व: निर्धारण का परिशोधन करने से असफल रहता है, तो ऐसा प्राधिकारी, अधिनियम के अधीन देय कर का निर्धारण करेगा ।

1968 का 24. **62. (1)** कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, जो हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय संक्रमणकालीन कर अधिनियम, 1968 (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी बना रहता यदि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ होता, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा । उपबन्ध ।

(2) जहां, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, प्रथम अप्रैल, 2004 को या के पश्चात् उस द्वारा क्रय किए गए किसी कराधेय माल के स्टॉक को रखता है तो वह, उनकी विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, देगा ।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी (धारा 7 या धारा 16 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले व्यौहारियों से अन्य) द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को अपने स्टॉक में रखा, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कराधेय माल, वह माल है जिस पर उक्त अधिनियम के अधीन विक्रय के प्रथम स्तर (स्टेज) पर कर दिया गया है और जिसका इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उस द्वारा पुनःविक्रय किया गया है तो उसे, उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे माल के क्रय पर संदत्त साबित की गई कर रकम की बाबत, आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु इस अधिनियम के अधीन प्रथम अप्रैल, 2005 को या के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को कराधेय माल के क्रयों के बाबत, आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) अनुज्ञात किया जाएगा, जहां ऐसे क्रय पुनः विक्रय या विक्रय के लिए माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए है, और ऐसे क्रय रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर किए गए हैं ।

(4) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, उक्त अधिनियम के अधीन कृत्य करने वाला वित्तायुक्त, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को और से इस

करने वाला वित्तायुक्त, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को और से इस अधिनियम के अधीन इसी रूप में कृत्य करना तब तक जारी रखेगा जब तक कि राज्य सरकार धारा 44 के अधीन अधिकरण स्थापित नहीं कर देती ।

(5) किसी भी व्यौहारी-को, जो माल विनिर्मित करता है और उसका विक्रय करता है और जो इस अधिनियम से ठीक पूर्व उक्त अधिनियम के अधीन विनिर्मित माल के विक्रय पर उदग्रहणीय विक्रय कर की किसी प्रकार की रियायत की प्रसुविधा ले रहा था और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को ऐसी रियायतों के लिए पात्र बना रहता यदि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ होता, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा,—

- (क) उस व्यौहारी द्वारा, अनवसित अवधि के लिए, विनिर्मित माल के अपने द्वारा किए गए विक्रय पर कर के संदाय से छूट की प्रसुविधा इस शर्त के अध्वधीन अनुज्ञात की जाती रहेगी कि कोई भी आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) ऐसे व्यौहारी (औद्यौगिक इकाई) द्वारा विनिर्मित और विक्रीत माल का क्रय करने वाले पश्चात्पूर्ती व्यौहारी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ; या
- (ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट छूट का उपभोग करने के बजाय प्रोत्साहन की अनवसित अवधि के लिए कर के आस्थगित संदाय की प्रसुविधा का उपयोग करने का विहित रीति में, विकल्प अनुज्ञात किया जाएगा ; या
- (ग) उस व्यौहारी द्वारा, अनवसित अवधि के लिए, विनिर्मित माल के अपने द्वारा किए गए विक्रय पर कर का आस्थगित संदाय करने की प्रसुविधा अनुज्ञात की जाती रहेगी और ऐसा व्यौहारी (औद्यौगिक इकाई) इस अधिनियम की धारा 11 के उपबन्धों के अध्वधीन रहते हुए कर बीजक जारी करने और आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का दावा करने का पात्र होगा ।

(6) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार, किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जो अपने विकल्प पर ऐसे माल के विक्रय पर उस द्वारा संदेय कर के बदले कर संदत्त कर सकेगा, ऐसे माल की अधिकतम फुटकर कीमत पर ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कर स्वीकार कर सकेगी।

63.(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर के उद्ग्रहण और नियम संग्रहण को सुनिश्चित करने और साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को बनाने की कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम के संगत, नियम बना सकेगी। शक्ति।

(2). इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधानसभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखे गए हों, या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1968 का 24

64.(1) हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें निरसन और इसके पश्चात् इस धारा में “उपर्युक्त अधिनियम” कहा गया है) का, इस अधिनियम व्यावृत्तियों के प्रवृत्त होने की तारीख से, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु उपर्युक्त अधिनियम का ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा :—

- (क) उपर्युक्त अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात ; या
- (ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; या
- (ग) उपर्युक्त अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड ; या
- (घ) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड से सम्बन्धित किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार ; और

ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियों या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानों उपर्युक्त अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया है।

(2) जब तक यह स्पष्टतया उपबन्धित न हो,—

(क) उपर्युक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का

प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस, आदेश या नियम या किसी प्ररूप या घोषणा के प्रयोग सहित), जहां तक यह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है प्रवृत्त बनी रहेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई या की गई समझी जाएगी मानों यह अधिनियम, उस तारीख, जिस को ऐसी बात या ऐसी कार्रवाही की गई थी, प्रवृत्त था जब तक इसे, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अधिकांत नहीं कर दिया जाता और उपर्युक्त अधिनियम के अधीन कर की सम्पूर्ण बकाया और देय अन्य रकम, इस अधिनियम के प्रारम्भ से वसूल की जा सकेगी मानों ये इस अधिनियम के अधीन प्रोदभूत हुई हों ।

(ख) कोई लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज, जिन्हें उपर्युक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन अभिगृहीत किया गया है, परन्तु निर्मुक्त नहीं किया गया है, तब तक प्रतिधारित रहेंगे जब तक कि उन्हें उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्मुक्त नहीं कर दिया जाता ; और

(ग) कोई माल, जिसे उपर्युक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन अभिगृहीत या निरुद्ध रखा गया है परन्तु निर्मुक्त नहीं किया गया है, तब तक अभिगृहीत या निरुद्ध रहेगा जब तक कि ऐसे माल को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन निर्मुक्त नहीं कर दिया जाता ।

(3) उपर्युक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्भूत होने वाला कोई निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही और या इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, सम्यक् रूप से निर्धारण करने, सुनवाई करने और विनिश्चय करने हेतु सशक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष लम्बित ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही, ऐसे प्रारम्भ की तारीख से, इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही निर्धारण करने, सुनवाई करने और विनिश्चय करने के लिए सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी को अन्तरित हो जाएगी और तत्पश्चात् उपर्युक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अवधि, यदि कोई हो, के भीतर ऐसा निर्धारण किया जाएगा या ऐसी अपील या पुनरीक्षण और अन्य कार्यवाही सुनी और विनिश्चित की जाएगी मानों वे उपर्युक्त अधिनियम के अधीन प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी थे ।

(4) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन किसी व्यौहारी द्वारा या

आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश करने हेतु वित्तायुक्त को दिया गया कोई आवेदन; या उपर्युक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन उच्च न्यायालय को किया गया कोई निर्देश, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लम्बित है, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 33 के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति, वित्तायुक्त या उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ हो और उपर्युक्त अधिनियम निरसित ही न किया गया हो ।

(5) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही जो उपर्युक्त अधिनियम के अधीन उद्भूत हुई हो परन्तु जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् प्रस्तुत किया गया हो या आरम्भ किया गया हो को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अपील, पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही को ग्रहण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुना और विनिश्चित किया जाएगा ।

अनुसूची 'क'

[धारा 6 की उप-धारा (1) का खण्ड (क) देखें]

भाग-1: एक प्रतिशत की दर से कराधेय माल

क्रम संख्या	माल
1	2

1. सोना, चांदी, और अन्य बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य रत्न और उनसे बने आभूषण ।

भाग-2: चार प्रतिशत की दर से कराधेय माल

1. हस्त अपरिचालित या पशु द्वारा न चलाए जाने वाले कृषि उपकरण ।
2. संसूचना के समस्त उपकरण जैसे कि प्राइवेट ब्रांच इक्सचेंज पी.बी.एक्स. और इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमैटिक ब्रांच इक्सचेंज ई.पी.ए.बी.एक्स. इत्यादि ।
3. सम्पूर्ण अमूर्त माल जैसे कि कापीराइट, पेटेंट और प्रतिनिधि अनुज्ञप्ति इत्यादि ।
4. सभी प्रकार की ईंटें जिनके अन्तर्गत फलाई ऑस ब्रिक्स, रिफ्रैक्टरी और छत पर लगने वाली मिट्टी की असफैलटिक टाइलें ।
5. अट्टी में कपास और रेशम सूत से अन्यथा सभी प्रकार के सूत और सिलाई धागा ।
6. ऐलमूनियम बर्तन और इनेमिल किए हुए बर्तन ।
7. ऐरिका नट, सुपारी पाउडर और सुपारी ।
8. बांस, बांस की लुगदी, बांस के छिलके और इससे निर्मित वस्तुएं (अनुसूची "ख" की मद संख्या 5 में सम्मिलित से अन्य) ।
9. बेयरिंग ।
10. वेल्टिंग ।
11. सुपारी पत्ते ।
12. बीड़ी के पत्ते ।
13. साइकिल, तिपिहिया साइकिल, साइकिल रिकशा और उनके पुर्जे ।
14. बिटूमन ।
15. अस्थिचूर्ण (बोन मील) ।
16. ब्रैंड ब्रेड ।
17. वलंक ड्रगज और अन्य ड्रगज, औषधियां और चिकित्सा प्लांट और उपकरण ।
18. पूंजी माल ।
19. कासटिंगज ।
20. सेनट्रिफ्यूगल, मोनो ब्लॉक और अवगाहनक्षम पम्प और उनके पुर्जे ।
21. काफी बीन और बीज ककोआ पौड, हरी पत्ती वाली चाय और चिकोरी ।
22. रासायनिक खाद, रासायनिक खाद का मिश्रण, कीटनाशक, नाशकजीवमार, कृतकनाशी,

कवक नाशी, बीडोसाइड, शाकनाशी, संयंत्र नियामक और संयंत्र वृद्धि पुष्टिकारक ।

23. नारियल-जटा और नारियल-जटा से निर्मित उत्पाद जिनके अन्तर्गत नारियल-जटा से बने गद्दे नहीं हैं ।
24. कपास और कपास अपशिष्ट ।
25. कुठाली (क्रुसिबलज) ।
26. केन्द्रीय बिक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 14 में यथाविनिर्दिष्ट घोषित माल।
27. खाद्य तेल, ऑइल केक और डी-आइल्ड केक ।
28. इलैक्ट्रोडज जिसके अन्तर्गत वैल्विंग इलैक्ट्रोडज और बैल्विंग रोडज हैं ।
29. अभ्यास पुस्तिकें (अनुसूची 'ख' की मद्य संख्या 25 में विनिर्दिष्ट के सिवाय), ग्राफ बुक और प्रयोगशाला नोट बुक ।
30. फेरस और नॉन फेरस धातुएं और मिश्र धातुएं; नॉन मेटलज जैसे कि ऐलुमिनियम, कॉपर, जिन्क और इनके निष्कासन ।
31. सभी प्रकार के फाईबर और फाईबर अपशिष्ट ।
32. आटा, मैदा, सूजी, बेसन इत्यादि ।
33. भूने हुए चने ।
34. गुड़, जैगरि और रब-गुड़ की खाद्य किस्में ।
35. हैंड पम्प और स्पेयर पार्ट्स ।
36. जड़ी-बूटियां, छिलके, सूखे पौधे या सूखी जड़ें, जो सामान्यतः जड़ी बूटी और सूखे फूलों के नाम से जाने जाते हैं ।
37. होज पाईपज ।
38. हौजरी का माल ।
39. भूसी और अनाज की चोकर ।
40. बर्फ ।
41. अनुकृत आभूषण ।
42. इनसेन्सस्टिकस सामान्यतः जो अगरबत्ती, धूपकाठी और धूपबत्ती के नाम से जानी जाती हैं ।
43. औद्योगिक केबिलज (हाई वोल्टेज केबिल, एक्स एल पी ई केबिल, जैली चड़ी हुई केबिल, आपटिकल फाईबरज केबिल) ।
44. सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित उत्पाद जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटर, टेलीफोन (जिनमें मोबाइल हैंडसेट और उनके पुर्जे भी हैं, टेलीप्रिन्टर और बेतार उपकरण और उनके पुर्जे और अन्य) उत्पाद जैसे अधिसूचित किए जाएं ।
45. औद्योगिक आगत और पैकिंग सामग्री जैसी अधिसूचित की जाए ।
46. लोक वितरण पद्धति के माध्यम से विक्रय किया गया मिट्टी का तेल ।
47. पतल और डूने (लीफ पलेट ऐंड कप) (अनुसूची 'ख' की मद्य संख्या 29 में विनिर्दिष्ट से अन्य)
48. मूरमूरालू, पेलालू, अटाकूटू, पफड राईस (मुरमुरा), मूड़ी ।
49. नेवार ।
50. नापा स्लैब्ज (रफ फ्लोरिंग स्टोंज) ।

51. कच्ची धातु और खनिज ।
52. धान, चावल, गेहूं और दालें ।
53. पेपर और न्यूज प्रिन्ट ।
54. सभी किस्म की पाईपें जिनके अन्तर्गत जी.आई.पाईपज, डिकटाईल पाईपज और पी.बी.सी. पाईपज हैं ।
55. प्लास्टिक के जूते ।
56. डायरी और कलैंडर सहित मुद्रित सामग्री ।
57. टोना और कार्टरिजिज को अपवर्जित करके प्रिंटिंग इन्क ।
58. संसाधित और ब्रांडिड नमक ।
59. रेल के डिब्बे, ईन्जन और वैगन्ज ।
60. बने-बनाए कपड़े (रेडिमेड गार्मेंट्स) ।
61. नवीकरणीय उर्जा यंत्र और उनके पुर्जे ।
62. सेफटी मैचिज ।
63. सिलाई मशीनें ।
64. समुद्री जहाज और अन्य जलयान ।
65. रेशमी कपड़ा (भाड़ा किराया करार के उन्मूलन के अध्यक्षीन रहते हुए) ।
66. स्कीमड मिलक पाउडर ।
67. कार्बनिक विलायक तेल से अन्यथा विलायक तेल ।
68. सभी किस्म और प्रकार के मसाले जिनमें जीरा, सौंफ, हल्दी और सूखी मिर्च भी सम्मिलित हैं ।
69. खेल-कूद सम्बन्धी सामान/माल जिनमें परिधान और जूते सम्मिलित नहीं हैं ।
70. मांडी (स्टार्च) ।
71. चीनी और खण्डसारी ।
72. इमली ।
73. बुना हुआ कपड़ा (टेक्सटाईल फेब्रिक्स) ।
74. तम्बाकू ।
75. ट्रैक्टर, थ्रैसर्स, हारवैस्टरज और अटैचमेन्ट्स और उनके पुर्जे ।
76. पारेषण टावरज ।
77. उद्यान छतरी के सिवाय, छतरी ।
78. वनस्पति (हाइड्रोजन से उत्पन्न वनस्पति तेल) ।
79. वनस्पति तेल जिसके अन्तर्गत सौंठ का तेल और चोकर तेल (ब्रान ऑयल भी है) ।
80. लिखने के इन्स्ट्रुमेन्ट्स (अनुसूची 'ख' की मद संख्या 25 में विनिर्दिष्ट से अन्य) ।

टिप्पण: - इस अनुसूची की क्रम संख्या, 71, 73 और 74 में विनिर्दिष्ट चीनी, टेक्सटाईल फेब्रिक्स और तम्बाकू के बारे में कर की दर उस तारीख से जैसे राज्य सरकार अधिसूचित करे, लागू होगी।

भाग-3: 12.5 प्रतिशत की दर से कराघेय माल

1 अनुसूची 'क' के भाग-1, भाग-2, भाग-4, भाग-5 और भाग-56 या अनुसूची 'ख' या अनुसूची-ग' अथवा अनुसूची-घ' में विनिर्दिष्ट किए गए माल से अन्यथा समस्त माल ।

भाग-4: 20 प्रतिशत की दर से कराघेय माल

क्रम संख्या

माल

- 1 आयुध और गोला बारूद ।
- 2 लाटरी टिकटें ।

भाग-5: 30 प्रतिशत की दर से कराघेय माल

क्रम संख्या

माल

- 1 चूना पत्थर ।
- 2 काष्ठ जिसमें संपरिवर्तित काष्ठ नहीं है ।

भाग-6: 100 प्रतिशत की दर से कराघेय माल

क्रम संख्या

माल

- 1 चूना पत्थर (एल.डी. ग्रेड) ।

अनुसूची 'ख'

(धारा 9 देखें)

कर मुक्त माल

क्रम संख्या	माल	शर्तें एवं अपवाद
1	2	3
1	किसी व्यक्ति द्वारा या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा विक्रीत/ जड़ी बूटियों या सैपलिंग सहित कृषि या बागवानी उपज जो स्वयं उगाई गई हो या ऐसी किसी भूमि पर उगाई गई हो जिसमें उसका कोई हित, चाहे स्वामी या भोग बन्धकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा हो ।	—
2	हस्त परिचालित और पशु द्वारा चलाए जाने वाले कृषि उपकरण ।	—
3	विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले साधन और उपकरण ।	—
4	पशुदाना (ऐनीमल फीड) और दाना परिपूरक अर्थात् मूर्गी दाना, पशुदाना (कैटलफीड), सुअर दाना, मछली दाना, मत्स्य भोजन, प्रान फीड, श्रिम्प फीड, दाना परिपूरक के रूप में विक्रीत प्रसंस्कृत वस्तु के रूप में, घास, सूखी घास और भूसे सहित दाना परिपूरकों के रूप में प्रयोग के लिए आशयित खनिज मिश्रण सान्द्र ।	—
5	कृषि प्रयोजनों में प्रयुक्त बांस से निर्मित वस्तुएं ।	—
6	बान ।	—
7	पुस्तिकें, पत्रिकाएं और जरनल्ज ।	—
8	चरखा, अम्बूर चरखा, हथकरघे, हिमाचली हथकरघों से निर्मित वस्तुएं, हिमाचली हथकरघा शालें, टोपियों और हैडस्पन यार्न और गांधी टोपी ।	—
9	चारकोल ।	—
10	धान, चावल और गेहूं से अन्यथा मोटा अनाज ।	—
11	निरोध (कन्डोम) और गर्भनिरोधक ।	—
12	हैंक में कपास सूत और हैंक में रेशमी सूत ।	—
13	दही, लस्सी, बटर मिल्क और सेपरेटिड मिल्क ।	—
14	मिट्टी के बर्तन (अनगलेजड) ।	—
15	विद्युत उर्जा ।	—
16	जलाने की लकड़ी ।	जब घरेलू उपयोग हेतु बेची जाए।
17	मछली जाल, मछली जाल का धागा और फीश सीडज ।	—
18	भारत सरकार द्वारा मुफ्त में दिया जाने वाला अनाज ।	—
19	ताजे फल ।	—
20	ताजा दूध और पासच्युराइजड मिल्क ।	—
21	फ्रेश प्लान्ट्स, सैलिंगाज और फ्रेश फलावरज ।	—
22	ताजी सब्जियां ।	—
23	लहसुन और अदरक, हरी मिर्च, प्याज, आलू, शकरकंद, टेपिओका और उनके बीज ।	—

1

2

3

24 कांच की चूड़ियां [जिनमें प्लास्टिक के खोल (शैल) और लाख की चूड़ियां भी —
हैं]।

25 ग्रेफाइट पेन्सिले, लिखने वाली चाक,केआन, स्केच, पेन, रबर, डाइंग कलर इरेजर —
शॉर्पनर, फुटरूल्ज, रेखा गणित बाक्स, सियाही की टिक्कीयां, स्कूलों में प्रयुक्त
किए जाने वाली अभ्यास और चित्रकला/पुस्तकें और विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त की
जाने वाली तख्तियां ।

26 मानव रक्त (हयूमेन ब्लड) प्लाजमा ।

27 हाथ के बनाए हुए स्वदेशीय संगीत वाद्य ।

28 कुमकुम, बिन्दी, अल्टा और सिन्दूर ।

29 पत्तल और डूने जब कम्प्रेसड न हों ।

30 मांस, मछली, प्रांन और अन्य जलीय उत्पाद जब सुरक्षित याजमाए न गये हों; डिब्बों में बेची गई
अण्डे और पशुधन तथा जानवरों के बाल । के सिवाए

31 राष्ट्रीय झण्डा ।

32 सरकारी खजानों द्वारा बिक्रीत नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर; सरकार द्वारा बिक्रीत —
पोस्टल वस्तुएं जैसे कि लिफाफे, पोस्ट कार्ड इत्यादि; कागज वाला रुपए का
नोट जब उसे भारतीय रिजर्व बैंक को बेचा जाए और चेक चाहे अवद्ध या
पुस्तिका के रूप में हों ।

33 जैविक खाद ।

34 कच्ची ऊन (रॉ वूल) ।

35 बीज

36 वीर्य जिसके अन्तर्गत जमा हुआ वीर्य भी है ।

37 कॉकून और कच्चा रेशम देने वाला रेशम का कीड़ा ।

38 कच्चा हरा नारियल ।

39 तडी, नीरा और अरक ।

40 अनब्रान्डड ब्रेड ।

41 अन प्रोसेसडज और अनब्रान्डड साल्ट (नमक) ।

42 निम्नलिखित से अन्यथा जल--

(i) ऐओरेटिड, मिनरल, डिसटिलड, मेडिसिनल, आयोजनिक, बाटरी,
डिमिनरलाईन्ड वाटर; और

(ii) बंद डिब्बों में बेचा जाने वाला जल ।

43 लिखने में प्रयुक्त होने वाली स्लेट और स्लेटियां ।

अनुसूची 'ग'

[धारा 6 की उप-धारा (1) का खण्ड (ख) देखें]

क्रय कर के अधधीन माल

क्रम	
संख्या	माल
1	2

1 रेजिन (क्रूड पाइन गम)

2 खैर, गन्ध सफेदा, पाप्लर वृक्ष जब वे तनों, जड़ों सहित गिराए गए हैं या काटे गए हैं या जिन्हे गिराए जाने हेतु सहमति हुई है, ईन्धन लकड़ी और सभी प्रकार की अन्य लकड़ी (काष्ठ) जब जिसे राज्य के भीतर उत्पादकों से क्रय किया गया हो ।

अनुसूची 'घ'

[धारा 6 की उप-धारा (1) का खण्ड (ग) देखें]

क्रम	
संख्या	माल
1	2

1 मोटर स्पिरिट (विमानन टर्बाइन इंधन सहित पेट्रोल तथा डीजल)

2 शराब

उद्देश्यों और कारणों का कथन

* माल के विक्रय और क्रय पर कर, वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 के अधीन उद्गृहीत किए जा रहे हैं तथा कर प्रथम स्तर पर ही संगृहीत किया जा रहा है। संव्यवहार के अनुक्रम में समस्त मूल्य परिवर्धनों पर उद्ग्रहण के प्रभाव को समवितरित करने, कराधान के नुतनान्त प्रभाव (कैसकेडिंग इफैक्ट) का परिहार करने, राजकोषीय रूप में अहितकर और हानिकर कर परिपाटियों (टैक्स प्रैक्टिसिज) जैसे राज्यों के मध्य कर दर संघर्ष उत्पन्न करने वाले टैक्स हैवनज या अधिमानी कर प्रणालियों को निरस्त करने के दृष्टिगत समस्त राज्यों के मुख्यमन्त्रियों के राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलनों में विद्यमान माल कराधान (कमोडिटी टैक्सेसन) को समरूपेण सुधारने तथा इसे मूल्य परिवर्धित कराधान की अधिक हितकर, विवेकपूर्ण, और प्रभावी पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। अतः राज्य में माल के विक्रयों और क्रयों पर कर के उद्ग्रहण की मूल्य परिवर्धित कर पद्धति पुरःस्थापित करना अनिवार्य समझा गया है। इसलिए नया विधान अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक, उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:

....., 2005.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 के अधीन, क्रयों और विक्रयों पर कर के उद्ग्रहण को, अधिक विवेकपूर्ण उद्ग्रहण द्वारा, जिससे लगभग पांच करोड़ रुपये आय होना संभाव्य है, प्रतिस्थापित करने के लिए, परिकल्पित है इस विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित होने पर आबकारी एवं कराधान विभाग के विद्यमान तंत्र द्वारा, कोई अतिरिक्त व्यय, उपगत किए बिना, प्रशासित किए जाएंगे ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 63, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए है शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य प्रकृति का है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारशें

[आबकारी एवं कराधान विभाग नस्ति संख्या ई0 एकस0 एन0-एफ0(11) 5/2004]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर विधेयक, 2005 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश राज्य में माल के विक्रयों या क्रयों पर मूल्य परिवर्धित कर के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध करने हेतु विधि पुनः अधिनियमित करने और उससे सम्बद्ध कतिपय अन्य विषयों के लिए विधेयक ।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि)

शिमला:

-----, 2005

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX BILL, 2005

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to re-enact the law to provide for the levy of a value added tax on the sales or purchases of goods in the State of Himachal Pradesh and for certain other matters connected therewith.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005. Short title and commencement.

(2) It shall come into force from such date as the Government may, by notification, appoint.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,— Definitions.

(a) “**Act**” means the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

(b) “**Assessing Authority**” means any person appointed by the State Government under sub-section (2) of section 3 to make any assessment under this Act;

(c) “**business**” includes,—

(i) any trade, commerce, manufacture, any adventure or concern, in the nature of trade, commerce or manufacture, whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make profit and whether or not any profit accrues therefrom; and

(ii) any transaction in connection with or ancillary to such trade, commerce, manufacture, adventure or concern;

-
- (d) “**capital goods**” means plant, machinery or equipment used in the process of manufacturing, processing and packing of goods for sale excluding civil structures as may be prescribed;
- (e) “**casual dealer**” means any person who carries on occasional transactions of business of buying, selling, supplying or distributing goods whether for cash, deferred payment, commission, remuneration or other valuable consideration;
- (f) “**Commissioner**” means the Excise and Taxation Commissioner appointed under sub-section (1) of section 3;
- (g) “**dealer**” means any person who carries on (whether regularly or otherwise) the business of buying, selling, supplying or distributing goods, directly or indirectly, for cash, or for deferred payment, or for commission, remuneration or other valuable consideration, and includes,—
- (i) a local authority, a body corporate, a company, a co-operative society or other society, club, firm, Hindu Undivided Family or other association of persons which carries on such business;
 - (ii) a factor, broker, commission agent, a dealer’s agent or any other mercantile agent, by whatever name called;
 - (iii) an auctioneer who carries on the business of selling or auctioning goods belonging to any principal, whether disclosed or not, and whether the offer of the intending purchaser is accepted by him or by the principal or a nominee of the principal;
 - (iv) every person engaged in the business of,—
 - (a) transfer; otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;
 - (b) transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;
 - (c) delivery of goods on hire-purchase or any system of payment by instalments;
 - (d) transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;
 - (e) supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration; and

- (f) supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating) where such supply or service, is for cash, deferred payment or other valuable consideration.

Explanation -I. — Every person who acts as an agent, in Himachal Pradesh, of a dealer residing outside this State and buys, sells, supplies or distributes goods in the State or acts on behalf of such dealer as—

3 of 1930

- (i) a mercantile agent as defined in the Sale of Goods Act, 1930; or
- (ii) an agent for handling of goods or documents of title relating to goods; or
- (iii) an agent for the collection of the payment of the sale price of goods or as a guarantor for such collection or payment;

and every local branch or office in Himachal Pradesh of a firm registered outside this State or a company or other body corporate, the principal office or headquarters whereof is outside this State, shall be deemed to be a dealer for the purpose of this Act.

Explanation-II. — Every department, or its subordinate offices, of a Government which whether or not in the course of business, buys, sells, supplies or distributes goods, directly or otherwise, for cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration, shall, except in relation to any sale, supply or distribution of surplus, unserviceable or old stores or materials or waste products or obsolete or discarded machinery or parts or accessories thereof, be deemed to be a dealer for the purpose of this Act.

Explanation-III. — For the purpose of this clause “Government” shall include the Central Government or the Government of any other State or Union Territory.

74 of 1956.

- (h) “**declared goods**” shall have the meaning assigned to that expression in clause (c) of section 2 of the Central Sales Tax Act, 1956;
- (i) “**Deputy Excise and Taxation Commissioner**” means the Deputy Excise and Taxation Commissioner, appointed under sub-section (1) of section 3 of this Act, to assist the Commissioner and shall also include the Joint/Additional Excise and Taxation Commissioner;
- (j) “**document**” includes title deeds, writing or inscription, statement of account and data stored electronically in whatever form and the like that furnishes evidence;
- (k) “**goods**” means every kind of movable property (other than newspapers, actionable claims, stocks and shares and securities) and

includes live stock, all materials, commodities and articles and every kind of property (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract, and all growing crops, grass, trees or things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale;

- (l) **“import”** means the bringing of goods into Himachal Pradesh from any place outside its territorial jurisdiction;
- (m) **“input tax”** means the amount paid or payable by way of tax under this Act, by a purchasing registered dealer to a selling registered dealer on the purchase of goods in the course of business for re-sale, or for use in the manufacture of taxable goods or for use as containers or packing material or for the execution of works contract;
- (n) **“invoice”** means a document listing goods with price, quantity, tax involved and other particulars as may be prescribed and includes a bill, cash memorandum, slip, receipt or similar record, regardless of its form;
- (o) **“motor spirit”** means any inflammable hydrocarbon including any mixture of hydrocarbons or any liquid containing hydrocarbon, which is ordinarily used for providing reasonably efficient motive power for any form of motor vehicle;
- (p) **“notification”** means notification published in the Rajpatra, Himachal Pradesh;
- (q) **“output tax”** output tax in relation to any registered dealer means the tax payable under this Act in respect of any taxable sale or purchase of goods made by that dealer in the course of his business;
- (r) **“prescribed”** means prescribed by rules made under this Act;
- (s) **“purchase”** with all its grammatical or cognate expressions, means the acquisition of goods for cash or deferred payment or other valuable consideration otherwise than under a mortgage, hypothecation, charge or pledge and includes—
 - (i) the transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;
 - (ii) the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;
 - (iii) the delivery of goods on hire-purchase or any system of payment by instalments;
 - (iv) the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;

- (v) the supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration;
- (vi) the supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating), where such supply or service, is for cash, deferred payment or other valuable consideration;

and such transfer, delivery or supply of any goods shall be deemed to be a sale of those goods by the person making the transfer, delivery or supply and a purchase of those goods by the person to whom such transfer, delivery or supply is made;

- (t) “**registered**” means registered under this Act;
- (u) “**reverse input tax**” means that amount of input tax credit in relation to any goods for which input tax credit has been availed of, but which shall stand reversed in the circumstances specified in sub-sections (9) and (10) of section 11;
- (v) “**sale**” means any transfer of property in goods for cash or for deferred payment or for any other valuable consideration other than a mortgage, hypothecation, charge or pledge, and includes—
 - (i) the transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;
 - (ii) the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;
 - (iii) the delivery of goods on hire-purchase or any system of payment by instalments;
 - (iv) the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;
 - (v) the supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration;
 - (vi) the supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating), where such supply or service, is for cash, deferred payment or other valuable consideration;

and such transfer, delivery or supply of any goods shall be deemed to be a sale of those goods by the person making the transfer, delivery or supply and a purchase of those goods by the person to whom such transfer, delivery or supply is made;

- (w) “**Schedule**” means a Schedule to this Act;
- (x) “**section**” means the section of this Act;
- (y) “**State Government**” or “**Government**” means the Government of Himachal Pradesh;
- (z) “**tax**” or “**value added tax**” means the tax on the sale or purchase of goods, levied under section 6 or 7;
- (za) “**tax period**” means the period prescribed for filing a return;
- (zb) “**timber**” includes trees when they have fallen, or have been felled or agreed to be felled and all wood whether cut up or fashioned or hollowed out for any purpose or not;
- (zc) “**tribunal**” means the Tribunal established under section 44;
- (zd) “**turnover**” means the aggregate amount of sales, purchases and parts of sales and purchases made by any dealer during the given period and includes any sum charged, on account of freight, storage, demurrage, insurance and for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before delivery thereof;

Explanation-I. — The proceeds of any sale made outside Himachal Pradesh by a dealer, who carries on business both inside and outside Himachal Pradesh, shall not be included in the turnover.

Explanation-II. — The turnover of any dealer in respect of transactions of forward contracts, in which goods are actually not delivered, shall not be included in the turnover.

Explanation-III. — The proceeds of sale of any goods on the purchase of which tax is leviable under this Act, or the purchase value of any goods on the sale of which tax is leviable under this Act, shall not be included in the turnover.

Explanation-IV. — The sum allowed as cash discount according to ordinary trade practice shall not be included in the turnover.

Explanation-V. — The amount to be included in the turnover in respect of delivery of goods on hire purchase or any system of payment by instalments shall be

the total sum payable by the hirer under the hire-purchase agreement in respect of the goods so delivered, or the amount actually paid in instalments.

Explanation-VI. — The amount to be included in the turnover in respect of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract shall be its sale price.

(ze) “**vehicle**” includes any carriage or conveyance used on land, water or air; and

(zf) “**year**” means the financial year.

CHAPTER-II

TAXING AUTHORITIES

3. (1) For carrying out the purposes of this Act, the State Government Taxing may, by notification, appoint a person to be the Commissioner and such other persons Authorities. with such designations, as it thinks fit.

(2) The State Government may, by notification, appoint as many Assessing Authorities as it may think fit.

(3) The Commissioner and other persons appointed under sub-section (1) shall perform such functions and duties as may be required by or under this Act or as may be conferred, by the State Government, by notification.

(4) The jurisdiction of the Commissioner and other officers posted at the State headquarters shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh, and the jurisdiction of other officers or officials shall, unless the State Government otherwise directs, by notification, extend to the districts or the areas of the districts for which they are for the time being posted.

CHAPTER-III

INCIDENCE, LEVY AND RATE OF TAX

4. (1) Subject to the provisions of sections 6, 7 and sub-section (2) of Incidence of section 16, every dealer (except one dealing exclusively in goods declared tax free taxation. under section 9) whose gross turnover during the year immediately preceding the commencement of this Act exceeded the taxable quantum shall be liable to pay tax under this Act on all sales effected and purchases made after the coming into force of this Act.

(2) Every dealer, who does not deal exclusively in goods declared to be tax free under section 9, shall be liable to pay tax under this Act from the date on which his gross turnover during any year first exceeds the taxable quantum.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2) no tax on the sale of any goods shall be levied if a tax on their purchase is levied under this Act.

(4) Every dealer who has become liable to pay tax under this Act shall continue to be so liable until the expiry of three consecutive years during each of which his gross turnover has failed to exceed the taxable quantum and such further period after the date of such expiry as may be prescribed, and on the expiry of this later period his liability to pay tax shall cease.

(5) Every dealer, whose liability to pay tax has ceased under the provisions of sub-section (4), shall again be liable to pay tax under this Act with effect from the date on which his gross turnover first exceeds the taxable quantum.

(6) In this Act, the expression "taxable quantum" means, —

- (a) in relation to any dealer who imports for sale or use in manufacturing or processing any goods in Himachal Pradesh.. Rupee 1/-;
- (b) in relation to any dealer, who himself manufactures or produces any goods for sale.. Rs. 2,00,000/- ;
- (c) in relation to any dealer, who runs a hotel, restaurant, bakery or other similar establishment wherein food preparations including tea are served.. Rs. 2,00,000/- ;
- (d) in relation to any particular classes of dealers not falling within clauses (a), (b) and/or (c), such sum as may be prescribed; or
- (e) in relation to any other dealer.. Rs.4,00,000/-:

• Provided that the registration of dealers already registered under this clause shall not be cancelled until their turnover in each of three consecutive years does not entitle them to cancellation under sub-section (4).

Liability of a dealer registered under the Central Sales Tax Act, 1956.

5. A dealer registered under the Central Sales Tax Act, 1956 who is not liable to pay tax under section 4 shall nevertheless be liable to pay tax under this Act on any sale or purchase made by him inside the State of Himachal Pradesh: 74 of 1956

Provided that nothing herein shall apply to a dealer who deals exclusively in goods declared tax free under section 9.

Levy of tax.

6. (1) Subject to the provisions of this Act, there shall be levied a tax,—

- (a) at every point of sale in respect of the goods specified in the second column of Schedule 'A',

- (b) at the prescribed points of purchase in respect of goods specified in the second column of Schedule 'C', and
- (c) at the first point of sale in respect of the goods specified in the second column of Schedule 'D',

on the taxable turnover of a dealer, at the rates as specified in the respective Schedules or at such rates not exceeding 100 paise in a rupee as the State Government may, by notification, direct:

Provided that the State Government may notify different rates in respect of different goods or classes of goods:

Provided further that the rate of tax in respect of declared goods shall not exceed the maximum rate of tax specified in clause (a) of section 15 of the Central Sales Tax Act, 1956:

Provided further that subject to furnishing of a declaration as may be prescribed, the Government may, by notification, reduce the rate of tax levied under sub-section (1) upto 4% in respect of goods sold to the Government, not being a registered dealer, for captive use in telecommunication network, or in the generation or distribution of electricity or any other form of power.

(2) Notwithstanding anything contained in this section, where any goods are sold in container or are packed in any packing material, the rate of tax applicable to such container or packing material, shall, whether the price of the container or packing material is charged separately or not, be the same as is applicable to the goods, contained or packed therein and the turnover in respect of the container and packing material, shall be included in the turnover of such goods. Where the goods, sold in container or packed in packing material are tax free, the sale of such container or packing material shall also be tax free.

(3) In this Act, the expression "taxable turnover" means that part of the dealer's gross turnover during any period which remains after deducting therefrom —

- (a) his turnover during that period on—
 - (i) the sale of goods declared tax free under section 9;
 - (ii) sale or purchase of goods falling under section 58; and
 - (iii) such other sales or purchases as may be prescribed; and
- (b) the amount of tax included in the gross turnover.

7. Notwithstanding anything contained in this Act, every registered dealer, whose gross turnover in any year does not exceed such amount as may be prescribed, shall, in lieu of the tax payable under this Act, pay presumptive tax on the entire taxable turnover of sales or purchases, as the case may be, at such rates, not exceeding the rates specified in section 6, as the State Government may, by notification, direct, and

subject to such conditions and restrictions and in such manner as may be prescribed:

Provided that no input tax credit shall be available to such dealer:

Provided further that no registered dealer, who imports goods for sale or use in manufacturing or processing any goods for sale, shall be entitled to make payment of presumptive tax under this section.

Levy of
purchase tax
on certain
goods in
certain
circum-
stances.

8. Where a dealer who is liable to pay tax under this Act purchases any goods other than those specified in Schedule 'B' from any source, and —

- (a) uses them within the State in the manufacture of goods specified in Schedule 'B', or
- (b) uses them within the State in the manufacture of any goods, other than those specified in Schedule 'B', and sends the goods so manufactured outside the State in any manner otherwise than by way of sale in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India, or
- (c) uses such goods for a purpose other than that of resale within the State or sale in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India, or
- (d) sends them outside the State in any manner otherwise than by way of sale in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India,

and no tax is payable on the purchase of such goods under any other provisions of this Act, there shall be levied a tax on the purchase of such goods equal to the rate as notified, under sub-section (1) of section 6, by the State Government.

Tax free
Goods.

9. No tax shall be payable on the sale of goods specified in the second column of Schedule 'B', subject to the conditions and exceptions, if any, set out in the corresponding entry in the third column thereof and no dealer shall charge sales tax on the sale of goods which are declared tax free from time to time under this section.

Power to
amend
Schedules.

10. The State Government, after giving by notification, not less than thirty days' notice of its intention to do so, may, by like notification, add to or delete from the Schedules 'A', 'B', 'C' or 'D' any goods, or otherwise amend these Schedules, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

Input tax
credit.

11. (1) The input tax credit which a purchasing registered dealer (hereinafter in this section called 'the purchasing dealer'), is entitled to claim, shall be the amount of input tax paid or payable by such purchasing dealer to the selling registered dealer, on the turnover of purchases made by him during the tax period and input tax credit shall be calculated as provided in this section and allowed subject to such conditions as may be prescribed.

(2) The purchasing dealer availing of the input tax credit shall maintain the tax invoices, the registers and the books of accounts in the manner as may be prescribed.

(3) The input tax credit shall be allowed to the extent of the amount of input tax paid by the purchasing dealer on the purchases of taxable goods made by him in the State, from a registered dealer holding a valid certificate of registration, which are intended for the purposes of, —

- (a) sale or re-sale of goods by him in the State; or
- (b) sale in the course of inter-State trade or commerce; or
- (c) sale in the course of export out of the territory of India; or
- (d) use as raw material or as capital goods in the manufacturing or processing of taxable goods for sale of the nature referred to in clauses (a), (b) or (c); or
- (e) use as containers or packing material of taxable goods for sale of the nature referred to in clauses (a), (b), (c) or (d):

Provided that if the goods so purchased are used partially for the purposes specified in this sub-section, the input tax credit shall be allowed proportionate to the extent these are used for the purposes specified in this sub-section:

Provided further that input tax credit on fuels and lubricants, shall be allowed only to the extent by which the amount of input tax paid in the State exceeds 4 percent subject to the condition that such fuels and lubricants are used in the manufacture of taxable goods or captive generation of power.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), the input tax credit shall be allowed only to the extent by which the amount of input tax paid in the State exceeds 4 percent on purchase of goods—

- (a) sent outside the State otherwise than by way of sale in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of territory of India; and
- (b) used in manufacture or in packing of taxable goods sent outside the State otherwise by way of sale in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of territory of India.

(5) The input tax credit shall not be claimed by the purchasing dealer until the tax period in which he receives from a registered dealer from whom he has purchased the goods, a tax invoice in the prescribed form (in original) evidencing the payment of amount of input tax:

Provided that for good and sufficient reasons, to be recorded in writing and in the prescribed manner, the Commissioner or any person appointed under section 3 may allow such credit subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(6) The input tax credit on capital goods shall be limited to plant and machinery directly connected with the manufacturing or processing of the finished goods and input tax credit as admissible under this section shall commence from the date of commencement of commercial production and shall be adjusted against tax payable on turnover of sales over a period of three years:

Provided that in case of closure of business before the period of three years, no further input tax credit shall be allowed and input tax carried forward, if any, shall be forfeited.

(7) No input tax credit shall be claimed by a purchasing dealer and shall not be allowed to him for, —

- (a) tax collected on the purchase of goods used in the manufacture or processing or packing of goods declared tax free under section 9;
- (b) purchases of goods made in the course of inter-State trade or commerce or in the course of import of goods into the territory of India or import from outside the State, in respect of tax paid in any other country or other State;
- (c) purchase of goods made in the State from,—
 - (i) an un-registered dealer or a casual dealer, or
 - (ii) a dealer whose certificate of registration has been suspended, or
 - (iii) a registered dealer who has opted to pay lump-sum amount, in lieu of tax, by way of composition under sub-section (2) of section 16 or presumptive tax under section 7;
- (d) purchase of goods used as free samples or gift or for personal consumption;
- (e) goods purchased for the uses specified in sub-section (3) but not sold because of theft, loss or destruction for any reason including natural calamity;
- (f) purchase of capital goods other than those specified in sub-section (6);
- (g) stock of goods remaining unsold at the time of closure of business and if a dealer has already taken any input tax credit against purchase of such stock of goods there shall be a reverse tax credit on closure of such business;
- (h) save as provided in sub-section (4), tax collected on purchase of goods but subsequently despatched to a place outside the State in any manner otherwise than by way of sale in the course of inter-State trade or commerce;
- (i) save as provided in sub-section (4), tax collected on the purchase of goods used as raw material in the manufacture of goods, and the goods so manufactured are despatched outside the State in any manner otherwise than by way of sale in the course of inter-State trade or commerce;

- (j) purchase of goods for sale under the transfer of right to use goods for any purpose (whether for specified period or not);
- (k) purchases where,—
 - (i) tax invoice is not available with the registered dealer; or
 - (ii) there is evidence that the tax invoice has not been issued by the selling dealer from whom the goods have been or stated to have been purchased; or
 - (iii) original tax invoice does not contain the details of tax charged separately by the selling dealer from whom purchasing dealer has purchased the goods.

(8) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, as may be prescribed, specify any goods in respect of which input tax credit shall not be allowed in part or in full or specify the class of dealers who shall not be entitled to input tax credit in part or in full.

(9) If the goods purchased are intended for the purposes specified in sub-section (3) and are subsequently used fully or partly for purposes other than those specified in the said sub-section, the input tax credit, if availed of, shall be reduced from the input tax credit being claimed for the tax period during which such use has taken place; and such reduction, shall be done in the manner as may be prescribed.

(10) Subject to the provisions of this section, input tax credit already availed of shall stand reversed if, —

- (a) the dealer discontinues business; or
- (b) the certificate of registration granted to the dealer is cancelled; or
- (c) the goods fall under clause (d), (e) or (g) of sub-section (7); or
- (d) excess input tax credit has been claimed; or
- (e) the goods purchased are returned to the selling dealer within three months of the date of purchase of such goods; or
- (f) the credit note has been received from selling registered dealer for the amount of tax charged in excess of the tax due according to the provisions of this Act; or
- (g) there exist any other circumstances as may be prescribed.

(11) The dealer shall be liable to pay such amount of reverse input tax credit alongwith interest under section 19 from the date immediately succeeding the last date prescribed for filing the return for the period for which such input tax credit was claimed till the date of its payment.

(12) Where any purchasing dealer has been issued with a credit note or debit note or if he returns or rejects goods purchased, as a consequence of which the input tax credit availed of by him during any tax period (to which the purchase of goods relates) becomes either short or excess, he shall compensate such short or excess by adjusting the amount of input tax credit allowed to him in respect of the tax period in which the credit note or debit note has been issued or the goods are returned

or rejected, subject to such conditions as may be prescribed.

(13) The amount of net input tax credit, which may be availed of by a purchasing dealer, shall be determined on the basis of the following formula, namely:—

Net Input Tax Credit = A+B-C

Explanation.— In this formula—

- (i) “A” represents the amount of input tax credit for which the purchasing dealer is entitled to;
- (ii) “B” represents outstanding input tax credit brought forward from the previous tax period; and
- (iii) “C” represents reverse input tax credit as determined under sub-section (10).

(14) The methods that are used by a purchasing dealer in a year to determine the extent to which the goods are sold, used, consumed or supplied, or intended to be sold, used, consumed or supplied in the course of making taxable sales shall be fair and reasonable:

Provided that the Commissioner or any person appointed under section 3 may, after giving the dealer an opportunity of being heard and for the reasons to be recorded in writing, reject the method adopted by the purchasing dealer and calculate the amount of input tax credit.

(15) Where a registered dealer without entering into a transaction of sale, issues to another registered dealer a tax invoice, retail invoice, bill or cash memorandum with the intention to defraud the State Government revenue or with the intention that the State Government may be defrauded of its revenue, the Commissioner or any person appointed under section 3 may, after making such inquiry as he thinks fit and giving a reasonable opportunity of being heard, deny the benefit of input tax credit to such registered dealer issuing or accepting such tax invoice, retail invoice, bill or cash memorandum or other invoice either prospectively or retrospectively from such date as he may fix.

Net tax payable.

12. (1) The net tax payable by a registered dealer for a tax period shall be the difference between the output tax plus purchase tax, if any, and the input tax credit, which can be determined from the following formula, namely:—

Net tax payable = (O+P) – I

Explanation. —In this formula—

- (i) ‘O’ denotes the output tax payable for any tax period;
- (ii) ‘P’ denotes the purchase tax paid by a registered dealer for any tax period; and
- (iii) ‘I’ denotes the input tax paid or payable for the said tax period, including input tax credit, if any, carried forward from any preceding tax period as determined under section 11.

(2) If the amount of input tax credit is more than the amount of output tax, the same may be adjusted, at the option of the dealer, against the tax liability for the said tax period, if any, under the Central Sales Tax Act, 1956 and only the remaining amount of the Central Sales Tax shall be payable. 74 of 1956.

(3) Excess amount of input tax credit, if any, after adjustment under sub-section (2) shall be adjusted against any outstanding tax, penalty or interest under this Act or, at the option of the dealer, under the Central Sales Tax Act, 1956. 74 of 1956.

(4) Excess amount of input tax credit, if any, after adjustment under sub-sections (2) and (3) may be carried forward to subsequent tax period or at the option of the dealer, on application being made in the prescribed manner, be refunded in accordance with the provisions of this Act.

(5) The net tax payable for a tax period by a dealer, liable to pay tax, but not registered under this Act, shall be equal to the output tax plus purchase tax, if any, payable for the said tax period as per the provisions of this Act and no input tax credit shall be admissible to him.

13. In respect of any sale or purchase effected by a dealer the burden of proving that he is not liable to pay tax under section 6 or section 8 or that he is eligible to input tax credit under section 11 shall be on him. Burden of proof.

CHAPTER-IV REGISTRATION, RETURNS, ASSESSMENT, RECOVERY AND REFUND OF TAX.

14. (1) No dealer shall, while being liable to pay tax under this Act, carry on business as a dealer unless he has been registered and possesses a registration certificate of dealers.

Provided that in the case of a casual dealer, on payment of a fee of Rs.50/-, the Assessing Authority or the Officer-Incharge of the check-post or barrier or any other officer inspecting the goods at any other place, may dispense with the requirement of a valid certificate of registration under this section.

(2) Any person intending to establish a business in Himachal Pradesh for the purpose of manufacturing goods for sale may, notwithstanding that he is not liable to registration under sub-section (1), be granted a registration certificate subject to such conditions and in the manner as may be prescribed, and such person when granted a registration certificate shall, for so long as such certificate is in force, be liable to pay tax under the Act:

Provided that grant of such a certificate of registration shall be subject to the conditions that if such person fails to establish the business within the period specified in the certificate or fails to comply with any of the conditions specified therein, he shall be liable by order of the Assessing Authority, to pay a penalty equivalent to one-half

of the amount of tax which would have been payable by him in respect of all the goods purchased by him as if he had not been registered under this sub-section:

Provided further that a dealer who sells taxable goods, not liable to register under sub-section (1) but who desires to register voluntarily may make an application to the appropriate Assessing Authority in the manner as may be prescribed and shall pay tax only in accordance with section 4 from the date his gross turnover exceeds a taxable quantum as specified in sub-section (6) of section 4.

(3) Every dealer required by sub-section (1) to be registered and every person who may be granted a registration certificate under sub-section (2) shall make an application in this behalf in the prescribed manner, to the Assessing Authority.

(4) If the Assessing Authority is satisfied that an application for registration made under sub-section (3) is in order, he shall, in accordance with such rules and on payment of such fee and subject to such conditions as may be prescribed, register the applicant and grant him a certificate of registration in the prescribed form.

(5) When any dealer fails to apply for registration in contravention of sub-section (1), the Assessing Authority shall register such dealer and grant him a certificate of registration and such registration shall take effect as if it had been made under sub-section (4) on the dealer's application.

(6) The Assessing Authority may, by order, —

- (a) amend certificate of registration on the dealer's application if the dealer or his legal representative furnishes the information that he—
 - (i) has transferred his business, or
 - (ii) has changed the name (constitution) or nature of his business, or
 - (iii) wants to open a new place of business or make any change either in the places of business or in the class or classes of goods specified in his certificate of registration for resale or for use in manufacture of goods for sale;
- (b) suspend a certificate of registration, without prejudice to any other penalty, if the dealer or person has violated any provision of this Act or rules made thereunder;
- (c) cancel a certificate of registration, on dealer's or, as the case may be, of his legal representative's application or suo-motu, without affecting liability to pay tax till such cancellation,—
 - (i) if the dealer sells or otherwise disposes of his business or any place of business or discontinues his business, or
 - (ii) if the dealer dies, or

- (iii) for any other sufficient cause including misuse of the certificate of registration or cessation of liability to payment of tax under this Act:

Provided that no order affecting any person adversely shall be made under clauses (b) and (c) of this sub-section without affording him a reasonable opportunity of being heard; and

- (d) renew a certificate of registration for such period and in such manner and on payment of such fee as may be prescribed.

15. (1) The Commissioner or any other person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3, if it appears to him to be necessary so to do for the proper realisation of the tax levied under this Act, may, for reasons to be recorded in writing, impose as a condition of the issue of a certificate of registration to a dealer, or of the continuance in effect of such certificate issued to any dealer, a requirement that the dealer shall give security, in the manner as may be prescribed, for such amount as may be specified in the order.

Security from certain class of dealers.

(2) No dealer shall be required to furnish security under sub-section (1), unless he has been given an opportunity of being heard.

(3) Where the security furnished by a dealer under sub-section (1) is in the form of a surety bond and the surety becomes insolvent or is otherwise incapacitated or dies or withdraws, the dealer shall, within fifteen days of the occurrence of any of the aforesaid events, inform the Authority granting the certificate of registration and shall within thirty days of such occurrence furnish a fresh surety bond.

(4) The Authority granting the certificate of registration may, by an order in writing, for good and sufficient cause, forfeit the whole or any part of the security furnished by a dealer for realising any amount of tax, penalty or interest payable by a dealer:

Provided that no order shall be passed under this sub-section without giving the dealer and the surety a reasonable opportunity of being heard.

(5) The Authority granting a certificate of registration may, on application by the dealer, order the refund of security furnished by him or any part thereof, if the same is not required for the purposes of this Act.

16. (1) Tax payable under this Act shall be paid in the manner hereinafter provided at such intervals as may be prescribed.

Payment of tax and returns.

(2) The State Government may, in public interest and subject to such conditions as it may deem fit, accept from any class of dealers in lieu of the amount of tax payable under this Act for any period, by way of composition, a lump sum to be determined and to be paid at such intervals and in such manner as may be prescribed,

or the lumpsum amount may be calculated at a fixed rate on the taxable turnover, as may be prescribed in respect of such class of dealers and for this purpose a simplified system of registration, maintenance of accounts, filing of returns may also be prescribed which shall remain in force during the period of such composition.

(3) Such dealers as may be required so to do by the Assessing Authority by notice served in the prescribed manner and every registered dealer shall furnish such returns by such dates and to such Authority as may be prescribed.

(4) Before a registered dealer furnishes the return required by sub-section (3), he shall, in the prescribed manner, pay into a Government Treasury or the Scheduled Bank which is a treasury bank, or at the office of the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer-in-charge of the District, the full amount of tax due from him under the Act according to such returns and shall furnish along with the returns a receipt from such treasury, bank or office of the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer-in-charge of the District showing the payment of such amount:

Provided that no payment of such amount shall be accepted at the office of the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer-in-charge of the District save through a crossed cheque or bank draft payable at a local branch of a Scheduled Bank in favour of the Assessing Authority:

Provided further that when a dealer makes payment through a Scheduled Bank other than the treasury bank, he shall obtain from such bank a certificate, as may be prescribed, to the effect that the bank has remitted the amount of tax to the treasury bank on the dealer's directions and on production of such certificate to the Assessing Authority the dealer shall be deemed to have paid the tax on the date following the date on which such certificate is issued by such bank:

Provided further that in case of payment through a Scheduled Bank which is located at a station other than that of the treasury bank, the dealer shall need to procure the prescribed certificate from the concerned bank, as mentioned under the preceding proviso, at least three days before the expiry of the due date prescribed under sub-section (2) for filing the return and only in that case the dealer shall be deemed to have made the payment by due date:

Provided further that where the payment is made through a crossed cheque, such crossed cheque must be delivered in the office of the Assessing Authority concerned, not less than ten clear days before the expiry of the due date prescribed under sub-section (3) for filing the return, and the dealer shall be deemed to have made the payment on the date on which such crossed cheque, after its presentation in the bank, is actually credited into the Government account and necessary receipt is issued by the bank in favour of the dealer:

Provided further that where the payment is made through a crossed cheque and the cheque is dishonoured, the dealer shall be deemed to have not made the payment and shall be liable to any action which may be taken for not making payment under this Act or the rules framed thereunder.

Explanation.—For the purposes of this sub-section “Scheduled Bank” means a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934. 2 of 1934.

(5) If any dealer discovers any omission or other error in any return furnished by him, he may, at any time, before the date prescribed for the furnishing of the next return by him, furnish a revised return, and if the revised return shows a greater amount of tax to be due than was shown in the original return, it shall be accompanied by a receipt showing payment, as may be prescribed, in sub-section (4), of extra amount.

(6) If a dealer fails without sufficient cause to furnish the returns by the prescribed date as required under sub-section (3), the dealer shall be liable to pay, by way of penalty, a sum equal to Rs. 25/- per day for delay in furnishing such return upto 10 days, whereafter the penalty shall be Rs. 50/- per day till the default continues, but such penalty shall not exceed Rs. 3000/- provided that where no tax is payable, such penalty shall not exceed Rs. 500/- for every return.

(7) If a dealer fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (4), the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, a sum which shall not be less than ten per centum, but which shall not exceed one and a half times of the amount of tax to which he is assessed or is liable to be assessed under section 21 in addition to the amount of tax to which he is assessed or is liable to be assessed.

(8) If a dealer has maintained false or incorrect accounts with a view to suppressing his sales, purchases or stocks of goods, or has concealed any particulars of his sales or purchases or has furnished to, or produced before, any Authority under this Act or the rules made thereunder any account, return or information which is false or incorrect in any material particular, the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, after affording such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty in addition to the tax to which he is assessed or is liable to be assessed, an amount which shall not be less than twenty-five per centum, but which shall not exceed one and a half times of the amount of tax to which he is assessed.

17. (1) Notwithstanding anything contrary contained in section 20, every person making any payment or discharge or any liability on account of valuable consideration payable—

(a) for the transfer of property in goods, whether as goods or in some other form, involved in the execution of works contract, and

Tax deduction from the bills or invoices of the works contractors etc.

(b) for the transfer of property in goods on account of sales of such goods made to the Government of India or to any State Government,

shall deduct an amount not exceeding four percentum, as may be prescribed, purporting to be a part or full of the tax payable on such sales, from the bills or invoices raised by the works contractor or by the dealer selling such goods, as payable by the person:

Provided that no deduction of such amount shall be made in respect of any transfer of property in goods, the turnover of which is deductible, from the dealer's gross turnover, under sub-section (3) of section 6:

Provided further that no such payment or discharge of any bill raised by the works contractor of the dealer selling such goods shall be made without deductions:

Provided further that if the State Government is satisfied that it is necessary to do so in the interest of the State revenue, it may notify the names/posts of such persons who shall be competent persons to make such deduction.

(2) The deduction referred to in sub-section (1) shall be made in the manner, as may be prescribed, and the payment of such deduction into the Government treasury shall be the responsibility of the person making such deduction.

(3) The person making such deduction shall issue deduction certificate in the prescribed manner to the person or dealer from whose bill or invoice, such deduction has been made.

(4) If any person contravenes any or all of the provisions of sub-section (1) or (2) or (3), the prescribed Authority shall, after giving an opportunity of being heard, by an order, in writing, direct that such person shall pay by way of penalty, a sum not exceeding twice the amount of tax deductible under sub-section (1).

(5) The provisions of sections 25 and 27 for recovery of any amount of tax due from a dealer shall mutatis mutandis apply for recovery of any amount of tax, deducted and / or any penalty imposed but not deposited under this section.

Declaration
and
certificates
to be filed
alongwith
returns.

18. Every dealer claiming,—

- (i) any deduction from his gross turnover, or
- (ii) any part of his taxable turnover to be a sale to Government, or
- (iii) any part of the taxable turnover to be liable to tax at concessional rate of tax under this Act,

shall, alongwith the return under sub-section (3) of section 16, furnish to the Assessing Authority, the declaration or the certificate as required under this Act.

Payment of
interest.

19. (1) If any dealer fails to pay the amount of tax due from him under this Act except to the extent mentioned in sub-section (2), he shall, in addition to the

amount of tax, be liable to pay simple interest on the amount of tax due and payable by him at the rate of one percentum per month, from the date immediately following the last date on which the dealer should have either filed the return or paid the tax under this Act, for a period of one month and thereafter at the rate of one and a half per centum per month till the default continues.

(2) If the amount of tax or penalty due from a dealer is not paid by him within the period specified in the notice of demand or, if no period is specified within thirty days from the service of such notice, the dealer shall, in addition to the amount of tax or penalty, be liable to pay simple interest on such amount at the rate of one percentum per month from the date immediately following the date on which the period specified in the notice or the period of thirty days, as the case may be, expires, for a period of one month and thereafter at the rate of one and a half percentum per month till the default continues:

Provided that where the recovery of any tax or penalty is stayed by an order of any court, the amount of tax or penalty shall, after the order of stay is vacated, be recoverable along with interest at the aforesaid rate on the amount ultimately found to be due and such interest shall be payable from the date the tax or penalty first became due.

(3) The amount of interest payable under this section shall—

- (i) for the purposes of collection and recovery, be deemed to be tax under this Act; and
- (ii) be in addition to the penalty, if any, imposed under this Act.

20. (1) No person shall collect any sum by way of tax in respect of sale or purchase of any goods on which no tax is payable under this Act.

Prohibition
against
collection of
tax in certain
cases.

(2) No person, who is not a registered dealer and liable to pay tax in respect of any sale or purchase, shall collect on the sale or purchase of any goods any sum by way of tax from any other person and no registered dealer shall collect any amount by way of tax in excess of the amount of tax payable by him under this Act.

(3) If any person, or a dealer referred to in sub-section (1) and (2) contravenes any of these provisions he shall be liable to pay, in addition to any tax for which he may be liable, a penalty of an amount not exceeding five hundred rupees, or double the amount so collected, whichever is greater.

(4) If the Commissioner, or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3, in the course of any proceedings under this Act or otherwise, has reason to believe that any person has become liable to pay penalty under sub-section (3), he shall serve on such person a notice in the prescribed form requiring him to show cause why a penalty as provided in sub-section (3) should not be imposed on him and thereupon hold an enquiry and shall make such order as he thinks fit.

Assessment
of tax.

21. (1) The returns furnished by a dealer shall be duly acknowledged in the manner prescribed and where all the returns relating to any year have been filed and are correct and complete in material particulars, the dealer shall, subject to the provisions of sub-section (2), be deemed to have been assessed for that year:

Provided that where the returns are not complete in material particulars, the dealer shall be given an opportunity to complete the same within fifteen days of service of the notice.

Explanation.— For the purpose of sub-section (1) a return shall be deemed to be—

- (i) correct, if its version conforms to that of the accounts maintained by the dealer and the account version cannot be impeached by any adverse information available on record till 31st October of the following year; and
- (ii) complete, in material particulars, if it contains the entire information required to be furnished therein, is correct arithmetically and is accompanied by the statutory or prescribed lists, documents and proof of payment of the full amount of tax due according to the returns and is duly signed by the dealer.

(2) The State Government may prescribe the manner of selection of cases for scrutiny of returns filed by the dealers specified in sub-section (1) and the Assessing Authority shall, in respect of each selected case, serve on the dealer a notice in the prescribed manner requiring him, on a date and at a place specified therein, either to attend in person or to produce or cause to be produced any evidence on which such dealer may rely in support of the returns filed by him under sub-section (1) and after hearing the dealer and considering the evidence produced by him assess the amount of tax, if any, due from him.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government considers it necessary and expedient, in public interest so to do, it may in respect of a dealer, whose gross turnover in a year does not exceed such amount as the Government may specify, in a special scheme of self-assessment for any year which may be notified, under this Act:

Provided that in case any dealer, whose taxable turnover has been assessed under the self-assessment scheme, is found to have evaded the tax, the Assessing Authority shall, after affording such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, in addition to the amount of tax assessed, a sum which shall not be less than one hundred per centum but which shall not exceed one and a half times of the amount of tax found to have been evaded and assessed.

(4) The Assessing Authority shall serve on the dealer not covered under sub-section (1) a notice in the prescribed manner requiring him, on a date and at a place specified therein, either to attend in person or to produce or cause to be produced any evidence on which such dealer may rely in support of such returns and after

hearing such evidence as the dealer may produce, and such other evidence as the Assessing Authority may require on specified points, assess the amount of tax due from the dealer.

(5) If a dealer, having furnished returns in respect of a period, fails to comply with the terms of a notice issued under sub-section (2) or (4), the Assessing Authority shall, within five years after the expiry of such period, proceed to assess to the best of his judgment the amount of the tax due from the dealer.

(6) If a dealer does not furnish returns in respect of any period by the prescribed date, the Assessing Authority shall, within five years after the expiry of such period, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, proceed to assess, to the best of his judgment, the amount of tax, if any, due from the dealer.

(7) If upon information which has come into his possession, the Assessing Authority is satisfied that any dealer has been liable to pay tax under this Act in respect of any period but has failed to apply for registration, the Assessing Authority shall, within five years after the expiry of such period, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, proceed to assess, to the best of his judgment, the amount of tax, if any, due from the dealer in respect of such period and all subsequent period and in cases where such dealer has wilfully failed to apply for registration, the Assessing Authority may direct that the dealer shall pay by way of penalty, in addition to the amount so assessed, a sum which shall not be less than fifteen per centum, but which shall not exceed one and a half times that amount.

(8) The amount of any tax, penalty or interest payable under this Act shall be paid by the dealer by such date as may be specified in the notice issued by the Assessing Authority for the purpose and the date so specified shall not be less than fifteen days and not more than thirty days from the date of service of such notice:

Provided that the Assessing Authority may, with the prior approval of the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer in-charge of the district, extend the date of such payment, but not more than 90 days, or allow payment by monthly instalments not exceeding three, against an adequate security or a bank guarantee.

(9) If the tax assessed under this Act or any instalment thereof is not paid by any dealer within the time specified therefore in the notice of assessment or in the order permitting payment in instalments, the Commissioner, or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3, may after giving such dealer an opportunity of being heard, impose on him a penalty not exceeding the sum due from him.

(10) Any assessment made under this section shall be without prejudice to any penalty imposed under this Act.

Assessment
of a casual
dealer.

22. (1) A casual dealer who is registered under this Act, shall be assessed like any other registered dealer under section 21.

(2) A casual dealer who is not registered shall, immediately on completion of transaction of sale or purchase for which he is liable to pay tax, report to the Assessing Authority having jurisdiction with reference to the place of such transaction or to the Officer-Incharge of the nearest check-post or barrier, the amount of sale or purchase price and the tax payable thereon and shall deposit the amount of tax with such Assessing Authority or such Incharge of the check-post or barrier within such time and in such manner as such Authority or Incharge may direct:

Provided that if a casual dealer desires voluntarily to pay the tax in advance in respect of the goods which such dealer intends to sell or purchase, he may pay the amount of tax on the sale or purchase value of such goods enhanced by ten percentum to the Assessing Authority or the Officer-Incharge of the nearest check-post or barrier.

(3) Where a casual dealer fails to make a report as required in sub-section (2), the Assessing Authority having jurisdiction or Excise and Taxation Officer-Incharge of the nearest check-post or barrier may require such casual dealer to make a report of the sale or purchase price and the tax due, failing which such Assessing Authority or such Incharge of the check-post or barrier may assess to the best of his judgement the amount of tax due and direct the casual dealer to pay the amount of tax within such time and in such manner as he may direct.

(4) Where a casual dealer fails to pay the tax as directed by the Assessing Authority or the Excise and Taxation Officer-Incharge of the check-post or barrier under sub-section (2) or (3), the goods belonging to such casual dealer shall be detained until the tax is paid or adequate security for payment of tax is furnished.

Reassessment
of tax.

23. (1) If in consequence of definite information which has come into his possession, the Assessing Authority discovers that the turnover of the business of a dealer has been under-assessed or escaped assessment in any year, the Assessing Authority may, at any time within three years from the date of assessment under section 21, proceed to re-assess the tax payable on the turnover which has been under-assessed or has escaped assessment:

Provided that the Assessing Authority may also take action to impose the penalty and interest under this Act:

Provided further that no order of re-assessment or imposition of penalty and interest shall be made unless the dealer is afforded a reasonable opportunity of being heard in the prescribed manner.

(2) The Assessing Authority or any such Authority as may be prescribed may, at any time, within one year from the date of any order passed by him and subject to such conditions as may be prescribed, rectify any clerical or arithmetical mistake apparent from the record.

24. (1) Notwithstanding the provisions relating to the period of limitation contained in section 21 or section 23 or in any other provisions of this Act, assessment or re-assessment may be made at any time in consequence of, or to give effect to, any order made by any court or other Authority under this Act.

Period of limitation for completion of assessment or re-assessment

(2) Where the assessment proceedings relating to any dealer remained stayed under the orders of any court or other Authority for any period, such period shall be excluded in computing the period of limitation for assessment or re-assessment specified in section 21 or section 23 or in any other provisions of this Act.

not to apply in certain cases.

25. The amount of any tax and penalty imposed or interest payable under this Act, which remains unpaid after the due date, shall be recoverable as arrears of land revenue.

Tax and penalty recoverable as arrears of land revenue.

26. Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, any amount of tax and penalty including interest, if any, payable by a dealer or any other person under this Act shall be a first charge on the property of the dealer or such other person.

Tax, penalty and interest to be first charge on property.

27. (1) Notwithstanding anything contained in section 25 or any law or contract to the contrary, Commissioner, or any officer other than an Excise and Taxation Inspector, appointed under section 3 to assist the Commissioner, may, at any time or from time to time, by notice in writing (a copy of which shall be sent to the dealer at his last address known to the officer issuing the notice), require –

Special mode of recovery.

- (a) any person from whom any amount is due or may become due to a dealer who has failed to comply with a notice of demand for any amount due under this Act;
- (b) any person who holds or may subsequently hold any money for or on account of such dealer,

to pay into the Government treasury in the manner specified in the notice issued under this sub-section, so much of the money as is sufficient to pay the amount due from the dealer in respect of the arrears of the tax, interest and penalty under this Act.

Explanation.— For the purposes of this sub-section, the amount due to a dealer or money held for or on account of a dealer by any person shall be computed after taking into account such claim, if any, as may have fallen due for payment by such dealer to such person and as may be lawfully subsisting.

(2) The officer issuing a notice under sub-section (1) may at any time, or from time to time, amend or revoke any such notice or extend the time for making any payment in pursuance of the notice.

(3) Any person making any payment in compliance with a notice issued under sub-section (1) shall be deemed to have made the payment under the Authority of the dealer and the treasury receipt for such payment shall constitute a good and sufficient discharge of the liability of such person to the extent of the amount specified in the receipt.

(4) Any person discharging any liability to the dealer after service on him of the notice issued under sub-section (1) shall be personally liable to the State Government to the extent of the liability discharged or to the extent of the liability of the dealer for tax, interest and penalty, whichever is less.

(5) Where a person on whom a notice is served under sub-section (1), proves to the satisfaction of the officer who issued the notice that the sum demanded or any part thereof was not due to the dealer or that he did not hold any money for or on account of the dealer, at the time the notice was served on him, then nothing contained in this section shall be deemed to require such person to pay into the Government treasury any such money or part thereof, as the case may be.

(6) Any amount of money which a person is required to pay under sub-section (1), or for which he is personally liable to the State Government under sub-section (4) shall, if it remains unpaid, be recoverable as an arrear of land revenue.

(7) The provisions of this section shall be without prejudice to any action that may be taken for the recovery of the arrears of tax, interest and penalty, if any, due from the dealer.

Refund.

28. (1) The Assessing Authority either suo-motu or on an application shall, in the prescribed manner, refund to a registered dealer or any other person any amount of tax, interest or penalty paid by such dealer or any such other person under this Act, if the amount of tax, penalty or interest so paid is in excess of the amount due from him under this Act, either by a refund voucher or, at the option of the dealer or such other person, by adjustment of the amount so paid with the amount due from him, in respect of any other period:

Provided that no application for refund of any excess amount of input tax credit under sub-section (4) of section 12 shall be made and no refund allowed until the expiry of two years from the date of commencement of this Act, and thereafter the claim may be made at the end of each subsequent year:

Provided further that no refund under this section shall be allowed unless the claim for refund is made within a period of three years from the date on which such claim accrues.

(2) Where any amount required to be refunded by the Assessing Authority to any person by virtue of an order sanctioning such refund issued under this Act is not refunded to him within ninety days of the date of the order, the dealer shall be entitled to get simple interest on such amount at the rate of one percentum per month from the date immediately following the date of expiry of the said period for a period of

one month and thereafter at the rate of one and a half percentum per month till the refund is made.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or (2), the Assessing Authority shall first adjust the amount to be refunded towards the recovery of any amount due from the dealer on the date of such adjustment, and shall thereafter refund the balance, if any.

(4) If the delay in allowing refund within the aforesaid period of ninety days is for reasons beyond the control of the Assessing Authority or attributable to the dealer, whether wholly or in part, the period of such delay shall be excluded from the period for which interest is payable.

(5) If any question arises whether any period is to be excluded for the purposes of calculation of interest under sub-section (4), the same shall be referred to the Commissioner, or such other officer as the State Government may, by notification, appoint, whose decision shall be final.

(6) Where an order allowing refund is the subject-matter of any appeal or further proceedings or where any other proceedings under this Act are pending, and the Assessing Authority is of the opinion that the refund is likely to adversely affect the recovery, the Assessing Authority may withhold the refund and refer the case to the Commissioner whose orders shall be final.

(7) The period during which the refund remains withheld under sub-section (6) shall be excluded for the purpose of calculation of interest under this section.

CHAPTER-V ACCOUNTS, SURVEY AND INSPECTION

29. (1) Every registered dealer or a dealer on whom a notice has been served Accounts. to furnish returns under sub-section (3) of section 16 shall maintain a true and upto date account of the value of goods purchased, manufactured and sold by him, or goods held by him in stock and in addition to the books of accounts that a dealer maintains and keeps for the purpose referred to in this sub-section, he shall maintain and keep such registers and accounts in such form as may be prescribed.

(2) Every dealer referred to in sub-section (1) shall retain at his place of business all accounts, registers and documents.

(3) Where a dealer as referred to in sub-section (1) has established branch offices of the business in the State other than the principal place of business, the relevant accounts, registers and documents in respect of each such branch shall, without prejudice to the provisions of sub-section (5), be maintained and retained by him at such branch also.

(4) If the Assessing Authority is of the opinion that the accounts maintained by any dealer or class of dealers do not sufficiently enable him to verify the returns or to properly make assessment on the basis thereof, he may, by an order, require such dealer or class of dealers to maintain such accounts, in such manner as may be prescribed.

(5) The State Government may, by notification, in public interest, exempt any class of registered dealers from the operation of the provisions of this section.

Tax invoice,
retail invoice
etc.

30. (1) The tax invoice shall contain such particulars as are specified in this section and shall be issued by one registered dealer to another dealer (whether registered or not) on the basis of which the purchasing registered dealer shall be entitled to claim input tax credit.

(2) Every registered dealer making a taxable sale to another dealer (whether registered or not) shall issue to such purchasing dealer a tax invoice, at the time of sale, containing such particulars as specified in sub-section (5), and retain a copy thereof.

(3) The tax invoice shall not be issued by the registered dealer when the sale is—

- (a) by a registered dealer paying presumptive tax under section 7 or lump sum under sub-section (2) of section 16 of this Act; or
- (b) of goods declared tax free under section 9 of this Act; or
- (c) in the course of inter-State trade and commerce; or
- (d) the sale is in the course of export out of the territory of India.

(4) For every taxable sale only one invoice shall be issued.

(5) The tax invoice issued under sub-section (2) shall contain the following particulars, namely:—

- (a) the words 'Tax Invoice' in bold letters at the top or at other prominent place;
- (b) the name, address and number of certificate of registration of the selling registered dealer;
- (c) the name, address and number of certificate of registration of the purchasing registered dealer;
- (d) serial number and the date on which the tax invoice is issued;
- (e) description, quantity, volume and value of goods sold, and amount of tax involved shown separately;
- (f) signatures of the selling dealer or his servant, manager or agent, duly authorized by him; and
- (g) the name and address of the printer.

(6) Except where tax invoice is required to be issued under sub-section (2), every registered dealer who sells any goods exceeding two hundred rupees, in any

one transaction, to any person, he shall issue to the purchaser a retail invoice containing the particulars specified in sub-section (7), and retain a copy thereof.

(7) The retail invoice shall contain the following particulars, namely:—

- (a) the words 'Retail Invoice' or 'Cash Memorandum' or 'Bill' in bold letters at the top or at a prominent place;
- (b) the name, address and number of certificate of registration of the selling registered dealer;
- (c) in case the sale is in the course of inter-State trade or commerce or export out of the territory of India, the name, address and registration number, if any, of the purchasing dealer/foreign buyer and the type of statutory form, if any, against which the sale has been made;
- (d) serial number and the date on which the retail invoice is issued;
- (e) description, quantity, volume and value of goods sold, amount of tax involved, if any ;
- (f) signature of the selling dealer or his servant, manager or agent, duly authorized by him; and
- (g) the name and address of the printer.

(8) Every registered dealer shall intimate, in writing, to the Assessing Authority, the total number of the tax invoices and the retail invoices got printed and kept for use by him during each year.

(9) The tax invoice shall be issued in triplicate and the original alongwith second copy shall be given to the purchaser or the person taking delivery of the goods, as the case may be, and the third copy shall be retained by the selling dealer.

(10) The retail invoice shall be issued in duplicate and the original copy shall be given to the purchaser and the second copy shall be retained by the selling dealer.

(11) Where tax invoice or retail invoice is not required to be issued, every registered dealer shall issue such other invoice as may be prescribed.

(12) Every dealer shall preserve books of accounts including tax invoices and retail invoices until the expiry of five years after the end of the year to which they relate or for such other period as may be prescribed or until the assessment attains its finality whichever is later.

(13) Where any dealer is a party to any appeal or revision under this Act or any other proceeding, he shall retain every record and accounts which pertain to the subject matter of such appeal, revision or other proceeding, until it is finally disposed of.

(14) Every dealer who maintains the records electronically shall also maintain day to day print-out of all such records and shall retain them for the period specified in sub-section (12), or, as the case may be, in sub-section (13).

(15) The State Government may, by notification, in public interest, exempt any class of the registered dealers from the provisions contained in sub-sections (2) to (14).

(16) Where any dealer contravenes the provisions of sub-sections (2) to (14), the Commissioner or any other person appointed under section 3 may, after affording such dealer a reasonable opportunity of being heard, impose upon him a penalty which may extend to five thousand rupees for every contravention.

Issue of credit
notes and
debit notes.

31. (1) Where a tax invoice has been issued for any sale of goods but if within six months from the date of such sale, the amount shown as tax charged in such tax invoice is found to exceed the tax payable, the registered dealer effecting the sale shall immediately issue to the purchasing registered dealer a credit note containing such particulars as may be prescribed.

(2) Where a tax invoice has been issued for sale of any goods and the tax payable in respect of the sale exceeds the amount shown as tax charged in such tax invoice, the registered dealer making the sale, shall immediately issue to the purchasing registered dealer a debit note containing such particulars as may be prescribed.

(3) Any registered dealer who receives or issues a credit note or a debit note shall modify his return for the period in which the credit note or debit note is received or issued, as the case may be, and pay any tax due before furnishing such return.

Production
and
inspection
of books,
documents
and
accounts.

32. (1) The Commissioner, or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 not below the rank of Excise and Taxation Officer may, for the purposes of this Act, require any dealer to produce before him any book, document or account relating to his business and may inspect, examine and copy the same and make such enquiries from such dealer relating to his business as may be necessary:

Provided that books, documents and accounts of a period more than five years prior to the year in which assessment is made shall not be so required.

(2) Every registered dealer shall—

- (a) maintain day-to-day accounts of his business;
- (b) maintain a list of his account books, display it alongwith his registration certificate and furnish a copy of such list to the Assessing Authority ;
- (c) produce, if so required, account books of his business before the Assessing Authority for authentication in the prescribed manner;
- (d) retain his account books at the place of his business unless removed therefrom by an official for inspection, by any official agency, or by auditors, or for any other reasons which may be considered to be satisfactory by the Assessing Authority.

(3) If any officer referred to in sub-section (1) has reasonable grounds for believing that any dealer is trying to evade liability for tax or other dues under this Act, and that anything necessary for the purpose of an investigation into his liability may be found in any books, account, register or document, he may seize such book, account, register or document as may be necessary. The officer seizing the book, account, register or document shall forthwith grant a receipt for the same and shall,—

- (a) in the case of book, account, register or document which was being used at the time of seizing, within a period of twenty-one days from the date of seizure, and
- (b) in any other case, within a period of ninety days from the date of seizure,

return it to the dealer or the person from whose custody it was seized after examination or after having such copies or extracts taken therefrom as may be considered necessary, provided the dealer or the aforesaid person gives a receipt in writing for the books, account, register or document returned to him and the officer may, before returning the book, account, register or document, affix his signatures and his official seal at one or more places thereon:

Provided that where the dealer fails to comply with the directions of the officer seizing the books or any other officer under this Act, such officer may further retain such books for such period as he may think fit after obtaining the permission of the Commissioner:

Provided further that such officer shall inform the dealer the reasons for which the books are required to be retained beyond the period prescribed under this sub-section.

(4) For the purposes of sub-section (2) or sub-section (3), an officer referred to in sub-section (1) may enter and search any office, shop, godown, vessel, vehicle, or any other place of business of the dealer or any building, dwelling house, or place where such officer has reason to believe that the dealer keeps or is, for the time being, keeping any books, accounts, registers, documents or goods relating to his business:

Provided that no entry or search in the dwelling house shall be made—

- (i) after the sunset and before the sunrise;
- (ii) by an officer below the rank of an Excise and Taxation Officer; and
- (iii) without obtaining the sanction of the District Magistrate within whose jurisdiction such house is situated.

(5) The powers conferred by sub-section (4) shall include the power to open and search any box or receptacle in which any books, accounts, registers or other relevant documents of the dealer may be contained and to take copies or extracts of the said accounts, registers or documents and such inventory of the goods and cash found as appears to him necessary for the purpose of this Act.

(6) Any officer empowered to act under sub-section (3) or sub-section (4) shall have power to seize any goods which are found in any office, shop, godown, vessel, vehicle or any other place of business or any building or place of the dealer but not accounted for by the dealer in his books, accounts, registers, records and other documents.

Power of
survey.

33. (1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, any Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer appointed to assist the Commissioner under sub-section (1) of section 3 or an Excise and Taxation Inspector, duly authorized by the Commissioner may, for the purpose of survey regarding ascertainment of commencement of liability to pay tax for registration under section 14 of this Act, and extent of business, enter—

- (a) any place within the limits of the area assigned to him, or
- (b) any place occupied by any dealer in respect of which he exercises jurisdiction,

at which the dealer carrying on the business, keeps any of his books of accounts or other documents or any part of his cash relating to the sale or purchase of goods or stock of goods relating to his business and require any dealer, employee or any other person who may at that time and place be attending in any manner to, or helping in carrying on of such business—

- (i) to afford him the necessary facility to inspect such books of accounts or other documents as he may require and which may be available at such place,
- (ii) to afford him the necessary facility to check or verify the cash and stock of goods which may be found therein, and
- (iii) to furnish such information including such statement as he may require as to any matter which may be useful for, or relevant to, any proceedings under this Act.

(2) For the purpose of sub-section (1), no entry in the dwelling house shall be made.—

- (i) after sunset or before the sunrise;
- (ii) by any officer below the rank of an Excise and Taxation Officer; and
- (iii) without obtaining the sanction of the District Magistrate within whose jurisdiction such house is situated.

Establishment
of check-
posts or
barriers and
inspection
of goods in
transit.

34. (1) If, with a view to preventing or checking evasion of tax under this Act, the State Government considers it necessary so to do, it may, by notification direct the establishment of a check post or the erection of a barrier or both at such place or places as may be notified.

(2) The owner or person in-charge of a goods carriage or vessel shall carry with him a goods carriage record, a trip sheet or a log book, as the case may be, and a tax invoice or a bill of sale or a delivery note containing such particulars as may be

prescribed, in respect of such goods, meant for the purpose of business, and produce the same before an officer in-charge of a check post or barrier or any other officer not below the rank of an Excise and Taxation Inspector checking the vehicle or vessel at any place.

(3) At every check post or barrier or at any other place when so required by any officer referred to in sub-section (2), the driver or any other person-in-charge of the [goods carriage] or vessel, shall stop the vehicle or vessel, as the case may be, and keep it stationary as long as may reasonably be necessary, and allow the officer-in-charge of the check post or barrier or the aforesaid officer to examine the contents in the vehicle or vessel and inspect all records relating to the goods carried which are in the possession of such driver or other person-in-charge, who shall also furnish such other information as may be required by the aforesaid officer, and if considered necessary such officer may also search the [goods carriage] or vessel and the driver or other person-in-charge of the vehicle or vessel or of the goods.

(4) The owner or person-in-charge of a goods carriage or vessel entering the limits of State or leaving the State limits shall also give in triplicate a declaration (generated electronically or otherwise) containing such particulars of goods carried in such vehicle or vessel, as the case may be, before the officer-in-charge of the check post or barrier and shall produce the copy of the said declaration duly verified and returned to him by the said officer or before any other officer referred to in sub-section (2) at the time of checking under this section:

Provided that where a goods carriage or vessel bound for any place outside the State passes through the State, the owner or person-in-charge of such vehicle or vessel shall furnish, in duplicate, to the officer-in-charge of the check post or barrier of his entry into the State a declaration in the prescribed form and obtain from him a copy duly verified. The owner or person-in-charge of the goods carriage or vessel, as the case may be, shall deliver within seventy two hours the said copy to the officer-in-charge of the check post or barrier at the point of its exit from the State, failing which he shall be liable to pay a penalty to be imposed by the officer-in-charge of the check post or barrier of the entry not exceeding twenty-five percentum of the value of the goods but which shall not be less than fifteen percentum of the value of the goods:

Provided further that no penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

(5) At every station of transport of goods, bus stand or any other station or place of loading or unloading of goods, other than a rail head or a Post Office, when so required by the Commissioner, or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3, the driver or the owner of goods carriage or the employee of a transport company or goods booking agency shall produce for examination transport receipt and all other documents and account books concerning the goods carried, transported, loaded, unloaded, consigned or received for transport (maintained by him in the prescribed manner). The Commissioner or the person so appointed shall, for the purpose of examining that such transport receipts or other documents or account books are in respect of the goods carried, transported, loaded, unloaded, or consigned

or received for transport, have the powers to break open any package or packages of such goods.

(6) If the officer-in-charge of the check post or barrier or other officer as mentioned in sub-section (2) has reasons to suspect that the goods under transport are meant for business and are not covered by proper and genuine documents as mentioned in sub-section (2) or sub-section (4), as the case may be, or that the person transporting the goods is attempting to evade payment of tax due under this Act, he may, for reasons to be recorded in writing and after hearing the said person, but subject to previous approval of the Excise and Taxation Officer Incharge of the barrier order the unloading or detention of the goods, for such period as may reasonably be necessary and shall allow the same to be transported only on the owner of goods or his representative or the driver or other person in-charge of the goods carriage or vessel on behalf of the owner of the goods, furnishing to his satisfaction a security or executing a bond with or without sureties for securing the amount of tax, in the prescribed form and manner, for an amount not exceeding twenty-five per centum of the value of the goods but which shall not be less than fifteen per centum of the value of the goods:

Provided that where any goods are detained a report shall be made immediately and in any case within twenty four hours of the detention of the goods by the officer detaining the goods to the Assistant Excise and Taxation Commissioner-Incharge of the District or the Excise and Taxation Officer-Incharge of the District or barrier, as the case may be, seeking the latter's permission for the detention of the goods for a period exceeding twenty four hours, as and when so required and if no intimation to the contrary is received from the latter the former may assume that his proposal has been accepted.

(7) The officer detaining the goods shall record the statement, if any, given by the owner of the goods or his representative or the driver or other person-in-charge of the goods carriage or vessel and shall require him to produce proper and genuine documents as referred to in sub-section (2) or sub-section (4), as the case may be, before him in his office on a specified date on which date the officer shall submit the proceeding along with the connected records to such officer as may be authorised in that behalf by the State Government for conducting necessary enquiry in the matter. The said officer shall, before conducting the enquiry, serve a notice on the owner of the goods and give him an opportunity of being heard and if, after the enquiry, such officer finds that there has been an attempt to evade the tax due under this Act, he shall, by order, impose on the owner of the goods a penalty not exceeding twenty five per centum of the value of the goods but which shall not be less than fifteen per centum of the value of the goods, and in case he finds otherwise, shall order the release of the goods.

(8) If the owner of the goods or his representative or the driver or other person-in-charge of the goods carriage or vessel does not furnish security or does not execute the bond as required under sub-section (6) within ten days from the date of detaining the goods or goods carriage or vessel, the officer referred to in that sub-section may order further detention of the goods and in the event of the owner of the

goods not paying the penalty imposed under sub-section (7) within twenty days from the date of the order imposing the penalty, the goods detained shall be made liable to be sold by the officer, who imposed the penalty, for the realisation of the penalty by public auction as may be prescribed. If the goods detained are of a perishable nature or subject to speedy or natural decay or when the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value the officer-in-charge of the check post or barrier or any other officer referred to in sub-section (2), as the case may be, shall immediately sell such goods or otherwise dispose them of. The sale proceeds shall be deposited in the Government treasury and the owner of the goods shall be entitled to only the balance amount of sale proceeds after deducting the expenses and other incidental charges incurred in detaining and disposing of the goods.

(9) The officer detaining the goods shall issue to the owner of the goods or his representative or the driver or the person-in-charge of the goods carriage or vessel receipt specifying the description and quantity of the goods so detained and obtain an acknowledgement from such person or if such person refuses to give an acknowledgment, record the fact of refusal in the presence of two witnesses.

(10) If the order of detention of goods under sub-section (6) or of imposition of penalty under sub-section (7) or sub-section (8) is in the meantime set aside or modified in appeal or other proceedings, the officer detaining the goods and imposing the penalty, as the case may be, shall also pass consequential orders for giving effect to the orders in such appeal or other proceedings, as the case may be.

(11) No dealer or any person, including a carrier of goods or agent of a transport company or booking agency acting on behalf of a dealer, shall take delivery of, or transport, from any vessel, station, airport or any other place, whether of similar nature or otherwise, any consignment of goods other than personal luggage or goods for personal consumption, the sale or purchase of which is taxable under this Act, except in accordance with such conditions as may be prescribed with a view to ensuring that there is no evasion of the tax imposed by or under this Act:

Provided that no place which is a rail head or post office shall be so notified by the State Government.

Explanation- I.—In this section the expression 'goods carriage' has the same meaning as is assigned to it in clause (14) of section 2 of the Motor Vehicles Act, No. 59 of 1988.

Explanation- II.— For the purposes of sub-section (2), the goods meant for the purposes of personal consumption shall not be construed as meant for the purposes of business.

Explanation-III.— For purposes of sub-section (7), service of notice on the representative of the owner or the driver or other person-in-charge of the goods carriage or vessel shall be deemed to be a valid service on the owner of the goods.

- Registration and submission of returns by carrier of goods and agent of transport companies. **35.** (1) For carrying out the purposes of section 34, every carrier of goods, agent of transport company and booking agency having a place of business in the State of Himachal Pradesh and transporting or clearing or forwarding goods on behalf of a dealer, shall be required to obtain a certificate of registration, in the prescribed manner, from the Assessing Authority of the area in which it has a place of business, on payment of such fee as may be prescribed and on furnishing of a security to the satisfaction of the said Authority in the manner as may be prescribed.
- (2) Every agency, referred to in sub-section (1), shall submit to the Assessing Authority such returns of the goods transported, cleared or forwarded by it, by such dates and in such manner as may be prescribed.
- (3) The Assessing Authority shall have the powers to call for and examine the books of accounts, documents and other record in possession of such agency with a view to verifying the correctness of returns submitted and the compliance to the requirements of provisions of section 34.
- Assessee etc. permitted to attend through authorised agent. **36.** Any assessee, dealer or other person, who is entitled or required to attend before any Authority in connection with any proceedings under this Act, except when required to attend in person, may attend through a person authorised by him in writing in this behalf, in the prescribed manner.
- Power to call for information from banking companies etc. **37.** The Commissioner or any other person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, for carrying out the purposes of this Act, require any person including a banking company, post office or any officer thereof to furnish any information or statement useful for, or relevant to, any proceedings under this Act.
- Delegation of powers. **38.** Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, the Commissioner may, by order in writing, delegate any of his powers under this Act to an officer not below the rank of Additional Excise and Taxation Commissioner posted at the State headquarters.
- Transfer of business. **39.** Where the ownership of the business of a registered dealer is entirely or in part transferred and the transferee carries on such business either in its old name or in some other name, the transferee shall, for all the purposes of this Act (except for liabilities under this Act already discharged by such dealer), be deemed to be and to have always been registered as if the certificate of registration of such dealer had initially been granted to the transferee; and the transferee shall on application to the prescribed authority be entitled to have the registration certificate amended accordingly.
- Liability on stock in certain cases. **40.** Should his certificate of registration be cancelled under any provision of this Act, a dealer, save when he has transferred his business to some one else, and notwithstanding clause (s) of section 2 but subject to the provisions of section 9, shall be liable to pay tax on goods purchased by him in the State of Himachal Pradesh after registration, and remaining unsold at the time of cancellation of certificate at a rate leviable on the sale of such goods.

- 41.** (1) Where a dealer is an undivided Hindu family, firm or other association of persons, and such family, firm or association is partitioned, dissolved or disrupted, as the case may be,—
- Liability to pay tax of a partitioned Hindu family, dissolved firm etc.
- (a) the tax payable under this Act by such family, firm or association of persons for the period upto the date of such partition, dissolution or disruption may be assessed as if no such partition, dissolution or disruption had taken place and all the provisions of this Act shall apply accordingly; and
- (b) every person who was, at the time of such partition, dissolution or disruption, a member or partner of an undivided Hindu family, firm or association of persons shall, notwithstanding such partition, dissolution or disruption, be liable severally and jointly for the payment of the tax including interest and penalty, if any, payable under this Act by such family, firm or association of persons, whether assessment is made prior to or after such partition, dissolution or disruption.
- (2) Where the registration certificate of a dealer is cancelled under this Act in any case, other than that of a partition of Hindu Undivided Family or dissolution or disruption of a firm or association of persons, the tax payable under this Act by such dealer for the period upto the date of cancellation of the registration certificate may be assessed on such dealer as if no such cancellation had taken place and all the provisions of this Act shall apply accordingly.
- 42.** Where a dealer, liable to pay tax under this Act, dies, then—
- Liability of legal heirs to pay tax.
- (a) if the business carried on by the dealer is continued after his death by his legal representative or any other person, such legal representative or other person shall be liable to pay the tax (including any penalty) due from the dealer under this Act, whether such tax (including any penalty) has been assessed before his death but has remained un-paid, or is assessed after his death; and
- (b) if the business carried on by the dealer is discontinued after his death, his legal representative shall be liable to pay out of the estate of the deceased to the extent the estate is capable of meeting the charge, the tax (including any penalty) due from the dealer under this Act, whether such tax (including any penalty) has been assessed before his death, or is assessed after his death, the provisions of this Act shall, so far as may be, apply to such legal representative, or other person as if he were the dealer himself.
- 43.** No assessment made and no order passed, under this Act, or the rules made thereunder, by the Commissioner or any person appointed under section 3 to assist him shall be called into question in any civil court and, save as provided in sections 45, 46 and 48, no appeal or application for revision shall lie against any such assessment or order.
- Bar of certain proceedings.

CHAPTER-VI**APPEAL, REVISION AND RECTIFICATION**

Tribunal

44. (1) The State Government shall by notification, establish an appellate tribunal consisting of a Chairperson and as many members as the Government may, from time to time, deem fit for the proper discharge of the functions conferred on the Tribunal by or under this Act.

(2) The Chairperson and the member shall possess such qualification as may be prescribed, and their terms of office shall be such as may be prescribed.

(3) The tenure of the Chairperson and members shall ordinarily be four years which may be extended by the State Government, by such period as it may think fit, but shall not be beyond the age of 62 years in any case.

(4) The salary, allowances and conditions of service of the Chairperson and other members of the tribunal, shall be such as may be prescribed.

(5) All cases coming before the tribunal shall be decided by a bench according to the opinion of the majority, and in any case where the Chairperson and the members are divided in their opinion on any point or points, they shall state the point or points on which they differ and refer the case for hearing by a bench consisting of,—

- (i) the Chairperson and the member who first heard it; and
- (ii) an additional co-opted member who is serving and qualified to be appointed as member under sub-section (2),

and such case shall be decided in accordance with the opinion of the majority of members of the bench:

Provided that the additional member shall cease to hold the office on the disposal of the case.

(6) Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the tribunal may award costs and the amount of such costs which remains unpaid after the due date, shall be recoverable from the person ordered to pay the same as arrears of land revenue.

(7) The seal of the tribunal and the procedure to be followed by it shall be such as the State Government may prescribe.

(8) The State Government may appoint such officers and officials, as may be required, to assist the tribunal in the discharge of its functions under this Act:

Provided that the cases of the State shall be represented before the tribunal by an officer not below the rank of Assistant Excise and Taxation Commissioner (Legal).

45. (1) An appeal from every original order passed under this Act or rules made thereunder shall lie—

- (a) if the order is made by an Assessing Authority or by an officer-in-charge of the check post or barrier or any other officer not below the rank of the Excise and Taxation Officer, to the Deputy Excise and Taxation Commissioner;
- (b) if the order is made by the Deputy Excise and Taxation Commissioner, to the Commissioner or the Additional Excise and Taxation Commissioner, posted at the State headquarters;
- (c) if the order is made by the Commissioner or the Additional Excise and Taxation Commissioner posted at the State headquarters or any officer exercising the powers of the Commissioner, to the tribunal.

(2) An order passed in appeal by a Deputy Excise and Taxation Commissioner or by the Additional Excise and Taxation Commissioner posted at the State headquarters or by the Commissioner or any officer, on whom the powers of the Commissioner are conferred, shall be further appealable to the tribunal.

(3) Every order of the tribunal, the Commissioner or any officer exercising the powers of the Commissioner or the Additional Excise and Taxation Commissioner posted at the State headquarters or the order of the Deputy Excise and Taxation Commissioner or of the Assessing Authority or an officer-in-charge of check-post or barrier or any other officer not below the rank of an Excise and Taxation Officer, if not challenged in appeal or revision, shall be final.

(4) No appeal shall be entertained unless it is filed within sixty days from the date of communication of the order appealed against, or such longer period as the Appellate Authority may allow, for reasons to be recorded in writing.

(5) No appeal under sub-section (1) shall be entertained by an Appellate Authority unless such appeal is accompanied by satisfactory proof of the payment of the tax (including interest payable) or of the penalty, if any, imposed or both, as the case may be:

Provided that if such Authority is satisfied that the dealer is unable to pay the tax (including interest payable) assessed or the penalty, if any, imposed or both, he may, for reasons to be recorded in writing, entertain an appeal without the tax (including interest payable) or penalty or both having been paid in full or after part payment of such tax (including interest payable) or penalty or both.

(6) Subject to such rules of procedure as may be prescribed, an Appellate Authority may pass such order on appeal as it deems just and proper.

Revision

46. (1) The Commissioner may, of his own motion, call for the record of any proceedings which are pending before, or have been disposed of by, any Authority subordinate to him, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such proceedings or order made therein and, on finding the proceedings or the orders prejudicial to the interest of revenue, may pass such order in relation thereto as he may think fit:

Provided that the powers under this sub-section shall be exercisable only within a period of five years from the date on which such order was communicated.

(2) The State Government may, by notification, confer on any officer powers of the Commissioner under sub-section (1) to be exercised subject to such conditions and in respect of such areas as may be specified in the notification and such officer shall be deemed to be the Commissioner for the purposes of sub-section (1).

(3) The tribunal, on application made to it against an order of the Commissioner under this section within sixty days from the date of the communication of the order, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such order, may call for and examine the record of any such case and may pass such orders thereon as it thinks just and proper.

(4) No order shall be passed under this section, which adversely affects any person unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

Rectification
of mistakes.

47. (1) The tribunal or the Commissioner or the officer on whom powers of the Commissioner for the purposes of sub-section (1) of section 46 have been conferred by the State Government may at any time within one year from the date of any order passed by him on an application made to him or of his own motion, rectify any mistake apparent from the record, and shall within a like period rectify any such mistake which has been brought to his notice by any person affected by such order:

Provided that the Commissioner may entertain an application under this sub-section after the expiry of the said period of one year, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from making the application in time:

Provided further that no such rectification shall be made if it has the effect of enhancing the tax or reducing the amount of refund, unless the Commissioner has given notice in writing to such person of his intention to do so and has allowed such person a reasonable opportunity of being heard.

(2) Where any such rectification has the effect of enhancing or reducing the amount of tax or penalty, the Commissioner shall, in the prescribed manner, order the recovery of the amount due from or as the case may be, order the refund of the amount due to, such person.

48. (1) Any person aggrieved by an order made by the tribunal under sub-section (2) of section 45 or under sub-section (3) of section 46, may, within 90 days of the communication of such order, apply to the High Court of Himachal Pradesh for revision of such order if it involves any question of law arising out of erroneous decision of law or failure to decide a question of law. Revision to High Court.

(2) The application for revision under sub-section (1) shall precisely state the question of law involved in the order, and it shall be competent for the High Court to formulate the question of law.

(3) Where an application under this section is pending, the High Court may, on application, in this behalf, stay recovery of any disputed amount of tax, penalty or interest payable or refund of any amount due under the order sought to be revised:

Provided that no order for stay of recovery of such disputed amount shall remain in force for more than 30 days unless the applicant furnishes adequate security to the satisfaction of the Assessing Authority concerned.

(4) The application for revision under sub-section (1) or the application for stay under sub-section (3) shall be heard and decided by a bench consisting of not less than two judges.

(5) No order shall be passed under this section which adversely affects any person unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

49. The tribunal or the Commissioner or any person appointed under sub-section (1) of section 3 shall, for the purposes of this Act, have the same powers as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 when trying a suit, in respect of the following matters, namely:— Power of authorities to take evidence on oath etc.

- (a) enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation;
- (b) compelling the production of documents and impounding or detaining them;
- (c) issuing commissions for the examination of witnesses;
- (d) requiring or accepting proof of facts by affidavits;
- (e) such other powers as may be prescribed; and

any proceeding under this Act before the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 shall be deemed to be a "judicial proceeding" within the meaning of sections 193 and 228 and for the purposes of section 199 of the Indian Penal Code, 1860.

CHAPTER-VII

OFFENCES AND PENALTIES

Offences and
penalties.

50. (1) Any person who—
- (a) wilfully acts in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder; or
 - (b) furnishes any certificate, declaration, bill, cash memorandum, voucher, delivery note, goods receipt or other document, which he knows or has reason to believe it to be false; or
 - (c) being a registered dealer, falsely represents when purchasing any class of goods for use by him in the manufacture of any goods for sale, that goods of such class are covered by his certificate of registration; or
 - (d) not being a registered dealer, falsely represents when purchasing goods in Himachal Pradesh that he is a registered dealer; or
 - (e) after purchasing any goods for any of the purposes specified in the Act, fails, without reasonable excuse, to make use of the goods for any such purpose; or
 - (f) has in his possession any form issued under the Act on payment by the Government, which has not been obtained by him or by his principal or by his agent in accordance with the provisions of this Act or any rules made thereunder; or
 - (g) prevents inspection or examination of books, documents and accounts or knowingly maintains false books, documents and accounts or wilfully fails to produce the books, documents and accounts mentioned in section 32; or
 - (h) fails to carry with him any of the records or documents specified in section 34; or
 - (i) makes any statement or declaration in any of the documents specified in section 34 or section 35, as the case may be, which statement or declaration he knows or, has reasons to believe to be false; or
 - (j) in any way is knowingly concerned in any fraudulent evasion or attempt at evasion or abetment of evasion of any tax payable in respect of the sale or purchase of any goods under this Act; or
 - (k) if he is a driver or any other person-in-charge of goods vehicle or vessel or an owner of the goods, refuses on demand by the officer-in-charge of the check post or barrier or any other officer, not below the rank of an Excise and Taxation Inspector, to give his name and address or the name and address of the owner of the goods vehicle or of the consignor or consignee of the goods or gives any name and address of any of these persons, which he knows or has reason to believe to be false; or
 - (l) aids or abets any person in the commission of any offence specified in this sub-section,

he shall, without prejudice to the recovery of any tax or interest or penalty which may be due from him, be punishable with simple imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both; and when the offence is a continuing offence, with a daily fine which may extend to fifty rupees for every day during which the offence continues.

(2) Whosoever contravenes or fails to comply with, any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, or any order or direction made or given thereunder, shall, if no other penalty is provided either under sub-section (1) of this section or under any other provisions of this Act for such contravention or failure, be liable to imposition of a penalty, not exceeding two thousand rupees, and where such contravention or failure is continuing one, to a daily penalty not exceeding fifty rupees during the period of the continuance of the contravention or failure.

(3) Any officer-in-charge of the check post or barrier or any other officer, not below the rank of an Excise and Taxation Officer, appointed under sub-section (1) of section 3 or such other officer as the State Government may, by notification, appoint, may, after affording to the person concerned a reasonable opportunity of being heard, impose the penalty mentioned in sub-section (2):

Provided that the officer-in-charge of the check post or a barrier shall exercise such powers only at such check posts or barriers.

51. (1) The Commissioner or any other officer not below the rank of Compounding Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer-Incharge of offences. of the district may, either before or after the institution of proceedings for any offence punishable under section 50 or under any rule made under this Act, accept from any person accused of such offence by way of composition of offence a sum of money equal to double the amount of tax which would have been payable on the turnover of sales or purchases to which the said offence relates, whichever is greater.

(2) On payment of such sum as may be determined under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the accused person in respect of the same offence and any proceedings, if already taken, shall stand abated.

52. (1) No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or the rules made thereunder except with previous sanction of the State Government or of such officer as may be authorised by a notification published in Official Gazette and no Court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any such offence. Cognizance of offences.

(2) Subject to the condition, if any, as may be prescribed, the Commissioner, may authorise, either generally or in respect of a particular case or class of cases, any officer or person subordinate to him to investigate all or any of the offences punishable under this Act.

(3) All offences punishable under sub-section (1) of section 49 shall be non-cognisable and bailable.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

Directors of
defaulting
companies
to be liable
to pay tax
etc.

53. Notwithstanding anything contained in any other law, where any tax assessed or penalty imposed under this Act on a company cannot be recovered by reason of the company having gone into liquidation or for any other reason, then every person, who was Director of such company at any time during the relevant period for which the tax is due or in respect of which the default for which the penalty is imposed was committed, shall be jointly and severally liable for the payment of such tax and penalty unless he proves that the non-payment or non-recovery cannot be attributed to any neglect, mis-feasance or breach of duty on his part in relation to the affairs of the company.

Disposal of
certain
property

54. Any property seized or detained under this Act, which is not claimed by any person, shall be disposed of in accordance with the provisions of sections 25, 26 and 27 of the Police Act, 1861, as if the officer or authority seizing or detaining such property were a police officer:

Provided that if, during the period allowed in accordance with such provisions, any person claims the property, it shall not be released to him unless the tax or penalty or both due in respect of the same under this Act is paid by such person.

Indemnity

55. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or servant of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Returns etc.
to be
confidential.

56. (1) All particulars contained in any statement made, return furnished or accounts or documents produced in accordance with this Act, or in any record of evidence given in the course of any proceedings under this Act other than proceedings before a criminal court, shall, save as provided in sub-section (3), be treated as confidential and notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872, no court shall, save as aforesaid, be entitled to require any officer, of the State Government to produce before it any such statement, return, accounts, document or record or any part thereof, or to give evidence before it in respect thereof.

(2) If, save as provided in sub-section (3), any officer of the State Government discloses any of the particulars referred to in sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, and shall also be liable to fine.

(3) Nothing contained in this section shall apply to the disclosure—

(a) of any such particulars in respect of any such statement, return, accounts, document, evidence, affidavit or deposition for the purpose of any prosecution under this Act or the Indian Penal Code, 1860; or

- (b) of any such particulars to any person entrusted with the administration of this Act for the purposes of carrying out the objects of this Act; or
- (c) of any such particulars when such disclosure is occasioned by the lawful employment under this Act of any process for the service of any notice or summons or the recovery of any demand; or
- (d) of any such particulars to a civil court in any suit to which the State Government in the Excise and Taxation Department or any officer of the said Department is a party and which relates to any matter arising out of any proceeding under this Act; or
- (e) of any such particulars to any officer appointed to audit receipts or refunds of the tax imposed by this Act; or
- (f) of any such particulars where such particulars are relevant to any enquiry into the conduct of an official of the Excise and Taxation Department of the State Government to any person or persons appointed by the Commissioner under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850, or to any officer otherwise appointed to hold such inquiry or to a Public Service Commission established under the Constitution when exercising its functions in relation to any matter arising out of such inquiry; or
- (g) of the annual gross turnover, shown in any return furnished or determined in any assessment order passed under this Act, to any officer of the Central or any State Government, as may be necessary for the purpose of enabling that Government to levy or realise any tax or duty imposed by it; or
- (h) of any such particulars which are relevant to any inquiry into the charge of misconduct, against an income-tax practitioner or other person who represents any assessee before any authority in any proceeding under this Act; or
- (i) of any such particulars to the Director of Economics and Statistics Department of the State Government as may be necessary for enabling him to work out the incidence of tax on any commodity or for carrying out any statistical survey of trade, commodity or dealer; and
- (j) of any such particulars for the purpose of preparing data by computerization :

Provided that the information mentioned in clauses (a), (f) and (g) may be permitted to be disclosed by the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer in-charge of the District only when he is satisfied, after scrutiny of the request made in this behalf and after such enquiries as he considers necessary, that the disclosure is admissible under this sub-section.

57. All persons appointed under sections 3 and 44 shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Persons appointed to be public servants.

58. Notwithstanding anything contained in this Act,—

- (a) a tax on the sale or purchase of goods shall not be imposed under this Act—

Provision in case of inter-State trade etc.

- (i) where such sale or purchase takes place outside the State of Himachal Pradesh; or
- (ii) where such sale or purchase takes place in course of import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India; and

(b) a tax on the sale or purchase of any goods shall not be imposed where such sale or purchase takes place in the course of inter-State trade or commerce except in so far as Parliament may by law otherwise provide.

Power to seek assistance from police and other officers.

59. An officer exercising the powers under this Act may take assistance of any police officer or other officer of the Government, as and when required and upon such request for assistance being made, the police officer or the other officer shall render necessary assistance in accordance with law.

Scrutiny of returns.

60. (1) Without prejudice to the provisions of sub-section (4) of section 21, at any time in the year, every Assessing Authority may undertake scrutiny of the returns filed during any tax period for ascertaining compliance of the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 16 and to check correctness of application and calculation of rates of tax, penalty and interest payable, claim of input tax credit and payment of full amount of tax due according to such return.

(2) If any mistake is detected as a result of such scrutiny made as per the provisions of sub-section (1), the Assessing Authority shall serve a notice in the prescribed form on the dealer to make payment of the extra amount of tax, penalty and interest.

(3) The Assessing Authority may also identify the dealers who have not filed the return for any tax period or not paid the tax, and shall, besides initiating action under section 16, serve a notice in the prescribed form directing such dealer to forthwith file such return and pay the amount of tax, penalty and interest due.

Audit and inspection.

61. (1) The Commissioner or any other Authority as may be authorised by him in this behalf may, for ascertaining the correctness of returns furnished, admissibility of various claims and input tax credit, on the basis of any prescribed criteria or on random basis, inspect or audit or cause to be audited any of the returns furnished, documents or statutory forms submitted by a dealer, subject to such conditions and in such manner as may be prescribed.

(2) The inspection or audit as required under sub-section (1), may either be undertaken in the office of such authority or in the business premises, or warehouse, or office of the dealer.

(3) The prescribed authority shall after considering all the evidence produced in the course of proceedings either, —

- (a) confirm the self-assessment under sub-section (1) of section 21; or

- (b) not confirm the self-assessment under sub-section (1) of section 21 and calculate the amount of tax due from the dealer; or
- (c) calculate the amount of tax due from a dealer, if no such assessment has been made:

Provided that if the prescribed authority proposes to rely upon any evidence collected by him in the course of inspection, audit or investigation, the dealer shall, by a notice, be afforded an opportunity of correcting his self-assessment within a period not exceeding thirty days and if he fails to rectify his self-assessment, such authority shall re-assess the tax due, under the Act.

62. (1) Any registered dealer, who would have continued to be so liable to pay tax under the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968, (hereinafter in this section called the 'said Act') had this Act not come into force, shall be deemed to be registered under this Act. Transitional provisions.

(2) Where, on the date of commencement of this Act, a registered dealer holds the stock of any taxable goods, purchased by him on or after 1st April, 2004, he shall furnish the particulars thereof, in such form within such period, in such manner and to such authority, as may be prescribed.

(3) Where the taxable goods, referred to in sub-section (2), held in stock by a registered dealer [other than the dealers falling in section 7 or sub-section (2) of section 16] on the date of commencement of this Act are those on which tax under the said Act has suffered at the first stage of sale, and are resold by him after the commencement of this Act, an input tax credit shall be allowed to him in respect of the amount of tax proved to have been paid, on the purchase of such goods, under the said Act:

Provided that the input tax credit shall be allowed to a dealer, registered under this Act on or after 1st day of April, 2005, in respect of purchases of taxable goods where such purchases are for resale or use in manufacture of goods for sale and that such purchases have been made within three months prior to the date of registration.

(4) The Financial Commissioner functioning under the said Act before the commencement of this Act shall, on and from the date of commencement of this Act, continue to function as such under this Act, until the State Government, establishes the tribunal under section 44.

(5) Any dealer who manufactures and sells goods and who, immediately before the commencement of this Act, was enjoying the benefit of any incentive of sales tax leviable on the sale of manufactured goods under the said Act and who would have continued to be eligible for such incentive on the date of commencement of this Act, had this Act not come into force, may be allowed by the State Government, by notification, —

- (a) to continue to avail of the benefit of exemption from payment of tax on the sale of manufactured goods made by such dealer himself for the

unexpired period, subject to the condition that no input tax credit shall be allowed to the subsequent dealer purchasing goods manufactured and sold by such dealer (industrial unit), or

- (b) to opt, in the prescribed manner, to avail of the facility of making deferred payment of tax for the unexpired period of incentive instead of availing the exemption specified in clause (a), or
- (c) to continue to avail of the facility of making deferred payment of tax on the sale of manufactured goods made by such dealer himself for the unexpired period and such dealer (industrial unit) shall be eligible to issue tax invoice and to claim input tax credit subject to the provisions of section 11 of this Act.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the State Government may accept from any registered dealer, who may at his option pay the tax in lieu of the tax payable by him on the sale of such goods, the tax at such rate on the maximum retail price of such goods, as the State Government may by notification, specify.

Power to
make rules.

63. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules consistent with this Act, for securing the levy and collection of tax and generally for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fifteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly agrees in making any modifications in the rules or the Assembly decides that the rule should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier under that rule.

Repeal and
savings.

64. (1) The Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968, (hereinafter in this section called the 'aforesaid Act') is hereby repealed from the date of coming into force of this Act: 24 of

Provided that such repeal of the aforesaid Act shall not affect, —

- (a) the previous operation of the aforesaid Act or anything duly done or suffered thereunder; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the aforesaid Act; or
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the aforesaid Act; or

- (d) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, punishment as aforesaid; and

any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the aforesaid Act had not been repealed.

- (2) Unless it is otherwise expressly provided—

- (a) anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order or rule or use of any form or declaration) in the exercise of any power conferred by or under the aforesaid Act shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force and be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under the provisions of this Act as if this Act were in force on the date on which such thing was done or such action was taken unless and until it is superseded by or under this Act and all arrears of tax and other amount due under the aforesaid Act, at the commencement of this Act may be recovered as if they had accrued under this Act;
- (b) any account, register or document seized under any provision of the aforesaid Act and not released shall continue to be retained, till the same is released, in accordance with the provisions of the aforesaid Act; and
- (c) any goods seized or detained under any provision of the aforesaid Act or the rules made thereunder and not released shall continue to remain seized or detained, till such goods are released, in accordance with the provisions of aforesaid Act.

(3) Any assessment, appeal, revision or other proceeding arising under the aforesaid Act and the rules made thereunder and or pending before an officer or authority duly empowered to make assessment or hear and decide such appeal, revision or other proceeding immediately preceding the commencement of this Act shall, on the date of such commencement stand transferred to the officer or authority competent to make assessment or to hear and decide appeal or revision or other proceedings under this Act and thereupon such assessment shall be made or such appeal or revision or other proceeding shall be heard and decided within the period, if any, specified therefore, by such officer or authority in accordance with the provisions of the aforesaid Act or the rules made thereunder as if they were the officers or authorities duly empowered for the purpose under the aforesaid Act.

(4) Any application by a dealer or the Commissioner to the Financial Commissioner for making a reference to the High Court under section 33 of the aforesaid Act; or any reference made to the High Court under section 33 of aforesaid Act, pending on the date of commencement of this Act shall be disposed of by the Financial Commissioner or the High Court, as the case may be, in accordance with the provisions

of section 33 of the aforesaid Act as if this Act had not been enacted and the aforesaid Act had not been repealed.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any appeal, revision or other proceeding arising under the aforesaid Act but preferred or initiated after the commencement of this Act, shall be heard and decided by the authority competent to entertain any appeal, revision or any other proceeding in accordance with the provisions of this Act.

SCHEDULE 'A'

[See clause (a) of sub-section (1) of section 6]

PART—I

GOODS TAXABLE @ 1 percentum

Sr. No.	Goods
1	2

1. Gold, silver, other precious metals, precious stones and ornaments thereof.

PART—II

GOODS TAXABLE @ 4 percentum

1. Agricultural implements not operated manually or not driven by animal.
2. All equipments for communication such as, Private Branch Exchange (P.B.X.) and Electronic Private Automatic Branch Exchange (E.P.A.B.X.) etc.
3. All intangible goods like copyright, patent and representative licence etc.
4. All kinds of bricks including fly ash bricks, refractory bricks and asphaltic roofing earthen tiles.
5. All types of yarn other than cotton and silk yarn in hank and sewing thread.
6. Aluminium utensils and enamelled utensils.
7. Areca nut, betel nut and betel nut powder.
8. Bamboo, pulp of bamboo, bamboo paper, wood and its articles (other than those covered by item No. 5 of Schedule 'B').
9. Bearings.
10. Belting.
11. Betel leaves.
12. Bidi leaves.
13. Bicycles, tricycles, cycle rickshaws and parts.
14. Bitumen.
15. Bone meal.
16. Branded Bread.
17. Bulk drugs and other drugs, medicines and medical plant and equipment.
18. Capital Goods.
19. Castings.
20. Centrifugal, mono block and submersible pumps and parts thereof.
21. Coffee beans and seeds, cocoa pod, green tea leaves and chicory.
22. Chemical fertilizers and chemical fertilizer mixtures; insecticides, pesticides, rodenticides, fungicides, weedicides, herbicides, plant regulators and plant growth nutrients.
23. Coir and coir products excluding coir mattresses.
24. Cotton and cotton waste.
25. Crucibles.
26. Declared goods as specified in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act, 74 of 1956).
27. Edible oils, oil cake and de-oiled cake.
28. Electrodes including welding electrodes and welding rods.
29. Exercise books (except those specified in item No. 25 of Schedule 'B'), graph book and laboratory note book.

30. Ferrous and non-ferrous metals and alloys; non-metals such as aluminium, copper, zinc and extrusions thereof.
31. Fibres of all types and fibre waste.
32. Flour (atta), maida, suji, besan etc.
33. Fried grams.
34. Gur, jaggery and edible variety of rub-gur.
35. Hand pumps and spare parts.
36. Herbs, bark, dry plants or dry roots, commonly known as jari booti and dry flowers.
37. Hose pipes.
38. Hosiery goods.
39. Husk and bran of cereals.
40. Ice.
41. Imitation jewellery.
42. Incense sticks commonly known as aggarbati, dhupkathi and dhup bati.
43. Industrial cables (high voltage cable, XL PE cables, jelly-filled cables, optical fibre cables).
44. IT products including computers, telephone (including mobile handsets and parts thereof, teleprinter and wireless equipments and parts thereof) and other products as may be notified.
45. Industrial input and packing materials as may be notified.
46. Kerosene oil sold through Public Distribution System.
47. Leaf plates and cups (other than those specified in item No. 29 of Schedule 'B').
48. Murmuralu, pelalu, atakutu, puffed rice, muri.
49. Newars.
50. Napa slabs (rough flooring stones).
51. Ores and minerals.
52. Paddy, rice, wheat and pulses.
53. Paper and news print.
54. Pipes of all varieties including G.I. pipes, C.I. pipes, Ductile pipes and PVC pipes.
55. Plastic footwear.
56. Printed material including diary and calendar.
57. Printing ink excluding toner and cartridges.
58. Processed and branded salt.
59. Rail coaches, engines and wagons.
60. Readymade garments.
61. Renewable energy devices and parts thereof.
62. Safety matches.
63. Sewing machines.
64. Ship and other water vessels.
65. Silk fabrics (subject to abolition of rental agreement).
66. Skimmed milk powder.
67. Solvent oils other than organic solvent oil.
68. Spices of all varieties and forms including cumin seed, aniseed, turmeric and dry chillies.
69. Sports goods excluding apparels and footwear.
70. Starch.
71. Sugar and khandasari.
72. Tamarind.
73. Textile fabrics.
74. Tobacco.

75. Tractors, threshers harvesters and attachments and parts thereof.
76. Transmission towers.
77. Umbrella except garden umbrella.
78. Vanaspati (hydrogenated vegetable oil).
79. Vegetable oil including gingili oil and bran oil.
80. Writing instruments (other than those specified in item No. 25 of Schedule 'B').

Note: - The rate of tax in respect of Sugar, Textile fabrics and Tobacco, specified at Sr. No. 71, 73 and 74 of this Schedule, shall be applicable from the date as the State Government may notify.

PART-III

GOODS TAXABLE @ 12.5 percentum

1. All other goods than those specified in Part-I, Part-II, Part-IV, Part-V and Part-VI of Schedule 'A' or in Schedule 'B' or in Schedule 'C' or in Schedule 'D'

PART-IV

GOODS TAXABLE @ 20 percentum

1. Arms and ammunition.
2. Lottery tickets.

PART-V

GOODS TAXABLE @ 30 percentum

1. Lime-stone (non-L.D. Grade)
2. Timber (excluding converted timber)

PART-VI

GOODS TAXABLE @ 100 percentum

1. Lime-stone (L.D. grade)

SCHEDULE 'B'

(See section 9)

GOODS EXEMPTED FROM TAX

Sl. No.	Goods	Conditions of exemption
1	2	3
1.	Agriculture or horticulture produce, including herbs or saplings of trees sold by person or a member of his family, grown by himself or grown on any land in which he has an interest whether as owner or usufructuary mortgagee, tenant or otherwise.	—
2.	Agricultural implements manually operated or animal driven.	—
3.	Aids and implements used by handicapped persons.	—
4.	Animal feed and feed supplements, namely, processed commodity sold as poultry feed, cattle feed, pig feed, fish feed, fish meal, prawn feed, shrimp feed and feed supplements and mineral mixture concentrates, intended for use as feed supplements including grass, hay and straw.	—
5.	Articles made of bamboo-wood used for agricultural purposes.	—
6.	Baan	—
7.	Books, periodicals and journals.	—
8.	Charkha, Ambar Charkha, handlooms, Himachali handloom articles, Himachali handloom shawls, caps and handspun yarn, and Gandhi Topi.	—
9.	Charcoal.	—
10.	Coarse grains other than paddy, rice and wheat.	—
11.	Condoms and contraceptives.	—
12.	Cotton yarn in hank and silk yarn in hank.	—
13.	Curd, lassi, butter milk and separated milk.	—
14.	Earthen pots (unglazed).	—
15.	Electric Energy.	—
16.	Fire wood.	When sold for domestic use
17.	Fishnet, fish fabrics and fish seeds.	—
18.	Foodgrains supplied free of cost by the Government of India.	—
19.	Fresh fruits.	—
20.	Fresh milk and pasteurised milk.	—
21.	Fresh plants, sapling and fresh flowers.	—
22.	Fresh vegetables.	—
23.	Garlic, ginger, green chillies, onions, potatoes, sweet potatoes, tapioca and their seeds.	—
24.	Glass bangles (including plastic shell and lac bangles).	—
25.	Graphite pencils, writing chalk, crayons, sketch pens, drawing colour eraser, sharpener, footrules, geometry boxes, ink tablets, exercise and drawing books of the type used in schools and takhties used by students.	—
26.	Human blood and blood plasma.	—
27.	Indigenous handmade musical instruments.	—
28.	Kumkum, bindi, alta and sindur.	—
29.	Leaf plates and leaf-cups (when not compressed).	Except when sold in sealed containers
30.	Meat, fish, prawn and other aquatic products when not cured or frozen; eggs and live stock and animal hair.	—

31.	National flag.	-
32.	Non-Judicial stamp paper sold by Government Treasuries; postal items like envelope, postcard etc. sold by Government; rupee note when sold to the Reserve Bank of India and cheques, loose or in book form.	-
33.	Organic manure.	-
34.	Raw wool.	-
35.	Seeds.	-
36.	Semen including frozen semen.	-
37.	Silk worm laying cocoon and raw silk.	-
38.	Tender green coconut.	-
39.	Toddy, Neera and Arak.	-
40.	Unbranded bread.	-
41.	Unprocessed and unbranded salt.	-
42.	Water other than - (i) aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, demineralised water, and (ii) water sold in sealed container.	-
43.	Writing slate and slate pencils.	-

SCHEDULE 'C'

(See clause (b) of sub-section (1) of section 6)

GOODS SUBJECT TO PURCHASE TAX

Sl. No. 1	Goods 2
1.	Resin (crude pine gum).
2.	Khair, Eucalyptus and Popular trees when they have fallen or have been felled or agreed to be felled including their stumps, roots, fuel wood and other wood in all forms when purchased from the growers within the State.

SCHEDULE 'D'

(See clause (c) of sub-section (1) of section 6)

Sl. No. 1	Goods 2
1.	Motor-spirit (Petrol including Aviation Turbine Fuel and Diesel).
2.	Liquor.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The taxes on the sale and purchase of goods are at present levied under the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 and tax is being collected at the first point only. With a view to evenly distribute the impact of levy on all value additions in the course of transactions, avoid cascading effect of taxation and eliminate fiscally unsalutary and harmful tax practices like tax havens or preferential tax regimes creating tax-rate war amongst the States, it has been decided at the national level conferences of the Chief Ministers of all the States to uniformly reform the existing commodity-taxation and replace it by a more wholesome, rational and effective system of value added taxation. Accordingly, it is considered essential to introduce the value added tax system of levy of tax on sales or purchases of goods in the State. This has necessitated the enactment of new legislation.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SIMLA:

The2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of this Bill are designed to replace levy of tax on purchases and sales under the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968, by a more rationalised levy which is likely to yield about Rs.500 crores per annum. The provisions of the Bill, when enacted, will be administered by the existing Government machinery without incurring extra expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 63 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

**RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF
THE CONSTITUTION OF INDIA**

[Excise and Taxation Department File No. EXN-F (11) 5/ 2004]

The Governor, Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Value Added Tax Bill, 2005, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX BILL, 2005

A

BILL

to re-enact the law to provide for the levy of a value added tax on the sales or purchases of goods in the State of Himachal Pradesh and for certain other matters connected therewith.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA:

The2005.

